

Haryana VIDHAN SABHA

Debates

22nd July, 1968

Vol. I—No. 5

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 22nd July, 1968

	Page
Starred Questions and Answers	1
Unstarred Question and Answers	5
Message from the Governor regarding	
Motion of Thanks	10
Call Attention Notice	11
Statement by—	
The Chief Minister in regard to Call	
Attention Notice No. 5	13
Election of the Deputy Speaker	14
Papers laid on the table	18
General discussion on the Budget	
For the year 1968-69	18-66

**HARYANA VIDHANSABHA SECRETARIAT,
CHANDIGARH**

ERRATA

TO

HARYANA VIDHAN SBHA DEBATES, VOL, I-NO. 5,

DATD THE 22ND JULY, 1968

Read	For	Page	Line
Leylands	Leylands	(5)1	2 from bottom
बसें	बेस	(5)2	2
Syngol	Syngal	(5)3	5 from bottom
1963	1967	(5)4	Heading
ओम प्रकाश गर्ग	ओम प्रकाश गर्ग	(5)5	7

And	And	(5)12	5 from bottom
शब्दों	शब्दों	(5)16	2
हरियाणा	हरियाणा	(5)18	23
गलतियां	गलतियां	(5)20	20
शोर	शोर	(5)21	नीचे से पहली
गई	गई	(5)26	30
देगी	दूंगी	(5)29	5
सरपंच	सरपंच	(5)31	24
मंगल सेन	मंगल सेन	(5)32	1
सबसे पहले	सबसे पहले	(5)39	27
उपज	उपज	(5)41	8
मिल	मिल	(5)41	15
गवर्नमेंट	गवर्नमेंट	(5)41	16
हमारे	हमारे	(5)44	2
पैदावार	पैदावार	(5)45	अन्तिम लाईन

मैट्रिक	मैट्रिक	(5)46	6
प्रैक्टिकली	प्रैक्टिकली	(5)46	13
खाइयों	खाइयों	(5)50	21
मैजिस्ट्रेट	मैजिस्ट्रेट	(5)50	नीचे से पांचवी
अपन	अपन	(50)50	नीचे से तीसरी
हूं	हूं	(50)51	5
की	को	(5)51	18
माधोसिघाना	माधोसिघाना	(5)52	23
शोरांवली	शोरांवली	(5)53	14
चैनल	चैनल	(5)53	14
एलनाबाद	एलानाबाद	(5)53	20
बुर्जी	बुर्जे	(5)53	23
उपाध्यक्षा	उपाध्यक्षा	(5)53	नीचे से दूसरी
करेगी	करेगी	(5)58	4

ड्रन	ड्रैन	(5)59	13
श्री सत्य नारायण	श्री सत्य नारायण	(5)60	9
श्री सत्य नारायण	श्री सत्य नारायण	(5)63	2
शराब	शराब	(5)63	अन्तिम लाईन
इसके बाद में	इसके बाद में	(5)65	21
फीसदी	रूपये	(5)65	22
रिश्वत ली हो उसे	रिश्वत ली हो	(5)66	10

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, the 22nd July, 1968

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha Vidhan Bhava, Sector-1 Chandigarh at 2-00 P.M. of the Clock. Mr Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTION AND ANSWERS

Mr. Speaker : In respect of Question No. 7 extension was a;;oied for which had been granted. The same applies to question No. 8.

श्री मंगल सेन : सर, इनका कब जवाब मिल जायेगा?

Mr. Speaker : I have been told that efforts are being made to obtain the necessary information as early as possible.

श्री मंगल सेन : क्या इस सैशन में इनका जवाब मिल जायेगा?

Mr. Speaker : Yes

Total number of Buses which fell to the share of Haryan

***9 Shrimati Chandravati :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The total number of the buses which fell to the share of Haryana as a result of reorganization together with the makes of each bus ; and

(b) The year in which the buses referred to in part (a) above were purchased and the present condition of each such bus?

Shri Bansi Lal : A statement is laid on the table of the House

(a) STATEMENT

Sr.	Make	No. of Vehicles
1.	Leyand	164
2.	Mercedez	14
3.	Doge	297
	Total	475

(B) —

Sr. No	Year of purchase	No. of vehicles purchased
-------------------	-------------------------	----------------------------------

1.	1960	31
2	1961	111
3	1962	85
4	1963	70
5	1964	23
6	1965	106
7	1966	49
	Total	475

119 buses e.i. 118 Doges and one Leyland have since been condemned and replaced. The remaining 356 vehicles are in operation and are entirely roadworthy. However, 107 buse (i.e. 83 doges and 24 Ley) are due for replacement on completion of their normal during the current financial year viz. 1968-69.

श्रीमती चन्द्रावती : क्या चीफ मिनिस्टा साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि 119 बेंस जो है यह रियाणा बनने के बाद खराब हुई या पहले ही खराब मिली थी?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, जो बसें चलती है वे ड्यूटाईम पर खराब भी होती है और जो खराब हो गयी है। उनको इस साल रिप्लेस कर रहे है।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहिब मै तो यह पूछना चाहती हूं कि वे जो बसें हमें पंजाब से मिल है वे हमारे हिस्से में खराब ही आयी थी या कुछ देर ओर कुछ मील चलने के बाद खराब हुई ।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, जो डीज है उन की उमर 6 साल है और गड़ियों लेलैण्ड है उन की उमर 8 साल है तो उसी हिसाब से ये कनडैम की गयी है ।

श्री मंगल सेन : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री साहिब ने बताया है कि 118 गाड़िया डौज जिनकी उमर उन्होंने 6 साल बताई, कनडैम हुई है मगर लेलैण्ड जिसकी उमर 8 साल है केवल एक कनडैम हुई है । तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि जब ये बसें ली गयी तो उनकी कीमतों में भी फर्क था या इनकी एक जैसी ही कीमत थी?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, जो उस समय डौज की कीमत थी वह दे दी गयी थी और जो लेलैण्ड की कीमत थी वह दे दी गया थी ।

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, मैने तो मुख्य मंत्री जी से डैफिनिट स्वेश्चन पूछा है । अगर वे अभी उसका उत्तर नहीं दे सकते तो उन्हें चाहिए कि टाईम मांग ले ।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, यह सप्लीमैअरी तो एराईज ही नहीं होता ।

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, मैंने तो उनके जवाब में से जवाब पूछा है। और वह भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी कहानी जानता हूँ। ये से सुरेन्द्र हिंस कौरों से ली गया थी। तो स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त लेलैण्ड की क्या कीमत थी और डौज की क्या कीमत थी?

Mr. Speaker: It appears that the exact information is not available. You may ask another question.

Chief Minister: Sir, this supplementary does not arise out of this question.

Shri Mangal Sein: It is for the Hon. Speaker to decide.

Mr. Speaker: Actually the original question put by Shrimati Chandravati does not cover this question.

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहिब, मेरी सबमिशन यह है कि हाउस में जब किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर को ध्यान में रखते हुए ही सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि से टालमटोल करने की बजाय मेरे प्रश्न का डैफिनिट उत्तर दें।

Mr. Speaker: Could you read out the portion of the answer which leads to this question?

Shri Mangal Sein: Sir, in part (b) of the question it has been asked-

“The year in which the buses referred to in part (a) above were purchased and the present condition of each such bus?”

स्पीकर साहिब, इस प्रश्न के जवाब में इन्होंने यह बताया कि कुल 119 गाड़ियां कन्डैम हुईं जिनमें 118 डीज हुईं और एक ललैण्ड हुई। मैं स्पीकर साहिब, आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूँ कि 118 डीज गाड़ियां जो इतनी ज्यादा तादाद में कन्डैम हुईं उनकी प्रति गाड़ी क्या कीमत थी? और ललैण्ड जो एक कन्डैम हुई उसकी क्या कीमत थी?

मुख्य मंत्री: इसके लिए आप अलग सवाल पूछें तो आपको जवाब मिल जायेगा।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये 119 बसें जिनका आपने खराब होने का जिक्र किया है, खराब होने की वजह से हरियाणा को दे दी गई थी। और बाकी की अच्छी बसें पंजाब ने स्वयं रख ली थी?

मुख्य मंत्री: स्पीकर साहिब, बटवारे के वक्त यह फैसला हुआ था कि जो डिपोज हरियाणा के पास है उनकी बसें हरियाणा में रह जायें और जो डिपोज पंजाब के पास है उनकी बसें पंजाब में रह जाएं तो हमारे हरियाणा में गुड़गांव और अम्बाला डिपुओं पर जितनी बसें थी वे हमारे हिस्से में आ गयीं।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहिब, मै मुख्य मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि क्याउनके नोटिस में यह बात है कि जिस वक्त यह बटवारा हुआ, निकम्मी और नाकारा बसें हरियाणा के डिपुओं पर रातों रात खड़ी कर दी गई और वहां से अच्छी बसें पंजाब ली जाई गई थी?

मुख्य मंत्री: स्पीकर, साहिब, मुझे तो किसी ऐसी बात का पता नहीं लेकिन आरेबल मैम्बर साहिब के नोटिस में कोई ऐसी बात है तो वे कोई आर्थेटिक इन्फर्मेशन दे हम इनक्यायरी करवा देंगे।

Shri Satya narain Syngal: Sir, the hon. Member has brought to the notice of the Chief Minister that there were some instances of unfair districbutionof buses at thetie of Reorgnaisationof Punjab, and still the Chief Minister ask him to quote specific instances. Does this very question not mean that there were instances of unfair distributionof buses?

Mr.Speaker: Iam sorry, this is no question.

मुख्य मंत्री: इसके लिए कोई आर्थेटिक इन्फर्मेशन चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मुख्य मंत्री जी उन लोगों के, खिलाफ जो उस समय जो जी.एम.पी.टी.सी. या दूसरे अफसर थे गुडगांव और रोहतक के डिपुओं पर, जिन्होंने यह बसों की हेरा-फेरी की है, उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे?

मुख्य मंत्री: अगर कोई ऐसी बात मुझे मिली तो मैं जरूर ऐक्शन लूंगा।

Tuition fees from the students

***18 Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government have taken any decision to withdraw the order of charging tuition fees from the students upto the 18th class in the state. If so, the date on which the said decision was taken?

Shir Bansi Lal: Yes from 1st August, 1968

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the scheme of granting Old Age Pension in the State : if so, the time by which it expected to be implemented :

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to fix the rate of pension at more than Rs. 15 per month?

Ch. Ran Singh: (a) Yes. The matter of the revival of the scheme is under the active consideration of Government.

(b) No.

श्री मंगल सेन: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि यह स्कीम ऐक्टिव कन्सिड्रेशन में है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका फैसला कब तक हो जायेगा?

मुख्य मंत्री: जब भी गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी फैसला करेगी।

श्री मंगल सेन: यह मुनासिब जो शब्द है क्या मुख्य मंत्री जी इसकी तशरी करे देंगे?

मुख्य मंत्री: यह डिक्शनरी में दिया हुआ है, आप वहां से देख ले।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगे कि क्या वह इस बात के लिए तैयार है कि पुरानी पेन्शनें है उनको तो पहले दोबारा जारी कर दिया जाए और बाकी की जो नयी दरखास्तें हैं उनका फैसला बाद में कर दें।

मुख्य मंत्री: जो सामने आयेगा और जैसा मुनासिब सरकार समझगी वैसा करेंगी।

श्री मंगल सेन: क्या मुख्य मंत्री जी हो एक जानकारी है कि पंजाब जो हरियाणा से अलग हो गया है वहां पर तो 15 रूपये से 25 रूपये पैन्शन कर दी गयी है? क्या हमारी सरकार भी यहां ऐसा करेगी?

मुख्य मंत्री: दूसरी सरकार जो करती है वह हमारे ऊपर वाईडिंग नहीं है। तो मुनासिब बात होगी वह सरकार करेगी।

श्री ओम प्रकाशक गर्ग: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जिसके सुपर चीफ मिनिस्टर श्री मंगल सेन थे ने यह पैन्शनज जारी रखी थी या बन्द कर दी थी?

श्रम मंत्री: उन्होंने यह स्कीम बन्द कर दी थी।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Brokent Rice with Dealeers in the Satae

2. **Shir Om Parkash Garg:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) The quantity of brokenrice lying with the deals in the State:

(b) Whether it is a fact that the stocks of broken rice are very heavy and there is little demand of the same in the market; and

© If so, whether Government is considering any proposal to allow the dealers to export the same to the deficit state?

Shr. K. L. Poswal: (a) & (b) Approximately six thousand tones Tota-Kani for which there is no demand in the state.

(c) Yes.

Export of Cows from the State

3. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) The details of steps taken by the Government to prevent export of cows from the state; and

(b) Whether the state Government is in correspondence with the Government of India in respect of preventing the export of cows from the state?

Shri Ram Dhari Gaur: (a) & (b) The matter is under consideration of the Government.

Schools without sanctioned staff

(a) The total number of schools in the State where the staff has not been provided according to the sanctioned strength ;

(b) If the staff according to the sanctioned strength has not been provided in the schools referred to in part (a) above, the reasons therefore together with details of steps taken

or proposed to be taken by the Government in providing the sanctioned strength of staff in the said schools?

Shri Bansi Lal: (a) The information shall have to be collected from more than five thousand schools and the labor involved will not be commensurate with the result.

(c) The vacancies were got advertised through the commission in the most cases. Some of them were to join their posts on the opening of schools after summer vacation. Appointments/posting of about 900 masters are being issued, very shortly.

(d) Training qualifications have been relaxed in the case of Science and Mathematics Master/Mistresses for which there is a general shortage.

(e) In cases where the public Service Commission has not been able to recommend the required number of candidates, Heads of Institutions are competent to make arrangements.

Construction of Ladas Shahabad Road

6. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Public works be pleased to state the time limit within which the Ladwa-Shahabd road is expected to be constructed together with the details of steps so far taken by Government in the regard?

Shri K.L. Poswal: The work of construction of Ladwa-Shahabad Road, five miles from Ladwa side, has been taken in hand and is likely to be completed during 1970-71, subject to availability of funds during 1969-70 and 1970-71

Inclusion of intervening five miles of road for new construction, in and draft Fourth Five Year Plan, 1969-74, is likely to be considered depending on the size ultimately, fixed for this plan.

Re-conditioning of 4½ mills from Shahabad side is in hand and is likely to be completed by early 1969.

PROCUREMENT OF WHEAT FROM THE MARKETS IN THE STATE

7. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Public Works be pleased to state:

(a) Whether Government have received any complaints regarding irregularities committed in procurement of wheat from the markets in the state; if so, the action taken thereon;

(b) Whether Government have fixed any price for procurement of wheat from the markets in the state, if so, the details thereof; and

Shri. K. L. Poswal: Yes. The complaints received were of varied nature and action was taken according to the nature of complaints.

(b) Yes. The procurement prices for purchase of wheat as fixed by the Government of India are Rs. 76 per quintal for F.A. quality Dara/Mexican wheat and Rs. 81 per quintal for superior wheat subject to levy of quality cuts according as specifications laid downy Government for each variety.

(c) Yes

Preventing cow- slaughter in the state

8. **Shri Om Parkash Garg:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) The steps, if any, taken by the Government for preventing cow-slaughter in the state; and

(b) Whether the Government have been in correspondence with the Central Government on the subject referred to in part (a) above: if so, with what result?

Shri Ram Dhari Gaur: (a) The cow slaughter is already banned under Punjab prohibition of Cow-slaughter act, 1955, and the rules framed there under, which is already in force in this state.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

Switching over Hindi in the State

9. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) Whether Government has fixed any date for switching over to Hindi in the State:

(b) If so, the date fixed therefore?

Shrimati Om Parbha Jain: (a) Yes, please

(b) 26th January, 1969

Distribution of Tractors amongst the Farmers in the State

10. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Labor be pleased to State-

(a) The procedure laid down by Government for distribution of tractors amongst the farmers in the state;

(b) The total number of tractors received by Government and distributed amongst the farmers in the state up to 30th June, 1968>

Ch. Ran Singh: (a) The Board of Directors of the Haryana Agro-Industries Corporation in the meeting held on the 10th January, 1968, in view the number of applications received up to 10th January, 1968, from each district; and that the allocations be make thought drawing

of the lots. The decision to draw lots was difficult to list them up in chronological order in fairness to all. Accordingly, the lots were drawn and the tractors allotted.

Applications received after 10th January, 1968 were decided to be considered against future allotment.

(b) (i) 200 Zetor tractors

(iii) 199 for farmers and one retained by the Corporation for its own use.

Medical College in the State

11. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of Government for starting another Medical College in the State ;

(b) If so, the place of its location and the date by which it is likely to start functioning?

Ch. Khurshed Amed: (a) Yes

(b) The location and the date by which it would start functioning will be decided after the requisite funds become available.

12. Shri Om Parkash Garg: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The object for which I.T. Is were started in the State ;

(b) The total number of trainees undergoing in each of the said institutions?

Shri Bansi Lal: (a) The I.T.Is. were started to impart free training in the Engineering and non-Engineering trades to urban and rural inhabitants of Haryana State so as to equip them to a standard of semiskilled and skilled craftsmen of providing essential technical manpower to the developing industry and also to increase employment opportunities in the state.

(b) The total number of trainees on role as on 31st August, 1967 was 3,632. New admission to the I.T.Is will take place with effect from 23rd July, 1968.

Setting-up sugar Mills in the State

14. Shri Om Parkash Garg: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for setting up new sugar mills by the Government in the state ; if so, the names of the places of their location and the time by which these are likely to be set up?

Shri Mahabri Singh: (Development Minister) : No, please.

Unallotted surplus land in the state

15. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the Tehsilwise details of the unallotted surplus area of land as on the 1st July, 1968;

(b) The steps, if any, proposed to be taken by the Government to settle Harijan tenants on such-land?

Shrimati Om Parbha Jain: (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) The aread declared surplus is utilized for resentlement of the tensnts including Harijan tenants ojected under the provisions of the Punjab Security of Land Tenures Act. 1953/Pepsu Tenancy and Gargicultureal Lands Act, 1955 and rules framed thereunder. Thee is no provision in the Acts, to allot the surplus land to Harijan tenants exclusively.

STATEMENT SHOWING DETAILS OF SURPLUS AREA (UNALLOTTED)

HISSAR DISTRICT

	S.A.	U
Sirsa Tehsil	7014	4 ½
Fatehabad Tehsil	1252	12 ½
Hissar Tehsil	3195	7 ¼
Hansi Tehsil	7086	4 ½
Bhiwani Tehsil	46	9 ¼
TOTAL	18595	6 ¼

ROHTAK DISTRICT

Rohtak Tehsil	260	3 ¼
Gohana Tehsil		
Sonepat Tehsil	1374	2 ¼
Jhajjar Tehsil	316	2 ¼
Total	2450	7 ¾

GURGAON DISTRICT

Gurgaon Tehsil	58	2 ³ / ₄
Rewari Tehsil	346	9 ³/₄
Nuthe Tehsil	246	3 ¹ / ₂
Ferozepurt Jhirkan Tehsil	95	6 ¹ / ₂
Palwal Tehsil	19	9
Ballabgarh Tehsil	206	11 ¹ / ₂
Total	972	11

KARNAL DISTRICT

Karnal Tehsil	4559	12 ¹ / ₄
Thanesar Tehsil	1670	5
Kaithal Tehsil	7565	6 ¹ / ₄
Panipat Tehsil	772	7
Total	14,567	14 ¹ / ₂

AMBALA DISTRICT

Ambala Tehsil	3	1
Jgadhri Tehsil	231	2 ½
Naraingarh Tehsil	2	14
Kalka Tehsil	36	½
Total	273	2

MOHINDERGARH DISTRICT

Narnaul Tehsil		
Mohindergarh Tehsil	3	7
Dadri Tehsil	78	9
Total	82	0

JIND DISTRICT

Jind Tehsil	1,065	0
Narwana Tehsil	2,227	0
Total	3,812	0
Grand Total	40,753	9 ¼

--	--	--

Surplus Evacuee Land Acquired from Government of India

16. Shri Om Parkash Garg: Will the Minister for Finance be pleased to state the villagewise surplus evacuee land in the state acquired from the Government of India, the auction of which was declared restricted only to Harijans during the year 1963-64, but later on such land was put to open auction?

Shrimati Om Prabha Jain: No rural evacuee land, internded to be sold to the harijans intheauctions restricted tothem, has been sold in open auction.

Message from the Governor

Mr. Speaker: I have received a message from the Governor which reads as follows:-

“ I writer to acknowledge with thanks the receipt of your demi-official leter No. HVS-LA/50/68/5819, dated the 18th/19th July, 1968, forwarding a coply of the motionof thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on the 18the of July, 1968. Please convey to the Members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for this kind though.”

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker: Now, I would taken up the item regarding "Call Attention Notices". Call Attention Notice No. 4 given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A., regarding failure of the Government to get the due share in the Agricultural University, Ludhiana, is admitted. The hon. Member may please read out his motion.

Shir Mangal Sein: Sir, I beg to draw the attention of the Haryana Government that interests of the Haryana state are suffering in the Agricultural University, Ludhiana, on account of the failure of the Government to get the said University partitioned. A sum of one hundred and twenty five lakh ruppes is being paid by the Haryana Government of this joint Agricultural University but instead of denving any benefit ourt of it, Haryana is suffering a loss. Therefore, I invite the attention of the Government to this matter throught this Call Attention Motion.

Labour Minsiter (Ch. Ran Singh): The Punjab Aggricultural University was constituted under the Punjab Aggricultural Univerwity Act, 1961. The univerwity is aorporate body. Under Section 72 of the Punjab Reorgnisation Act, 1966, theUniversity, having become inter-state corporate boy 'on and from the appointed day' continues to function and operte in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before ehat day, subject to such directions as may from time to time be issued by the Central

Government until another provision is made by law in respect of the University. The successor States are required to make such grants as the Central Government may, from time to time, by order, determine. On the basis of population, cultivated areas, number of blocks in each state, the Central Government has finally determined the share of the successor states as under:-

Punjab Government	51.77%
Haryana Government	39.50%
Himachal Pradesh Government	8.43%
Union Territory of Chandigarh	0.30%

The Punjab Agricultural University Act, 1961 was amended by the Central Government with effect from the 1st November, 1966. Under Section 8 of the Act, the Board of Management, Academic Council, Board of Studies and such other bodies as may be declared by the Statutes are the authorities of the University. All the powers of the University are vested in the Board of Management which consists of 13 Members as under:-

Vice-Chancellor	1
Representatives of Punjab Government	5
Representatives of the Haryana Government	4
Representatives of the Himachal Pradesh Govt.	3

Under section (1) of the Act, Governor of Punjab shall be the Chancellor of the University. Under Section 11, the Vice-Chancellor is appointed by the Board of Management unanimously. Shri S.K. Chhibber, former Financial Commissioner Development, has been functioning as Acting Vice-Chancellor is on long leave due to illness.

The rate of contribution as explained earlier has been fixed as 39.50% by Government of India. Since Re-organisation the following amounts as share of this state have been paid to P.A.U.:-

Year	Plain	Non-Plain	Total
1 st November, 1966 to 31 st March, 1967	15,69,000	11,70,000	27,39,000
1967-68	34,70,350	46,09,630	80,79,980
1968-69 (1 st quarter), (11 th quarter)	15,00,000	24,28,900	39,28,900

It was felt that Haryana Government was exercising very little power of directions over the affairs of the university although it was paying 39.50% of its total Budget. There were also overwhelming sentiments in Haryana that there should be a separate Agricultural University in the new State of Haryana and the present common links should be bifurcated.

The matter was, accordingly, considered at the Cabinet level and on 27th October, 1967 it was decided that the P.A.U. should be bifurcated and a separate University set up for Haryana as early as possible.

The Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi was accordingly addressed on the 16th November, 1967 to amend the Punjab Re-organisation Act, 1966 as also to issue necessary directives relating to the bifurcation of existing assets and liabilities. The matter is being vigorously pursued with the Government of India at personal level also.

The Government of India in the Ministry of Home Affairs replied in May, 1968, as under:-

(i) If and when it is decided to divide the University, it will be necessary for the Haryana Legislature to enact a separate Law setting up its own Agricultural University. In such a law provision can be made for vesting in the new University the assets of existing University within the state of Haryana along with the corresponding liabilities ;

(ii) The Punjab Legislature on its own part will have to enact reciprocal legislation for divesting to existing University of such assets and liabilities ;

(iii) Such Legislative measures should be preceded by an agreement between the Government of Punjab and Haryana regarding the assets and liabilities of existing University ;

(iv) The alternative appears to be to have a recourse to article 252 (i) of the constitution, if the Legislatures of both the States agree on the matter being regulated by a Parliamentary law.

The Government of India has further advised that the question of having a separate Agricultural University for Haryana would require very careful consideration with special reference to the finances available and the demand for manpower in the areas now served by the existing University and financial aspect be considered in detail at the time of finalizing the next Five-Year plan. The Indian Council of Agricultural Research would be glad to make a detailed assessment of the situation in consultation with the State Government in case such assistance is desired by the State Governments.

The advice received from the Government of India is under examination of the Government. Steps are being taken to bifurcate the existing University and to set up a separate University of Haryana state, as per decision of the Council of Ministers already taken and this issue is already receiving urgent attention of the State Government.

6. With a view to safeguarding the interests of the Haryana State in a Agricultural University in the intervening period, the matter was considered by Government. The University decided in April, 1968, that their budget for the current year (1968-69) should be split region wise and the contributions of the states be spent solely and entirely on the campuses situated within the territory of the contributing states. Thus thought the contributions of the participating states will be

according to proportions laid down by the central Government, expenditure will not be on a pro rata basis.

7. It came to the notice of Government in November, 1967, that whereas the contribution of Haryana Government towards, the University was 39.50% the number of seats actually filled up in the admission to the Ph. D. Course held in October, 1967, from Haryana was 20.37% only. The matter was examined. It was found that although it is a fact that 39.50% of the seats for the Ph.D. programme did not go to Haryana, yet this was so because sufficient number of candidates belonging to Haryana and having the requisite qualifications did not apply for admission. Further application for Ph.D course was denied admission.

Statement by the Chief Minister

Mr. Speaker: On 18th July, 1968, the hon. Chief Minister promised to make a statement today, in regard to *Call Attention Notice no. 5 given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A. He may not please make that statement.

Chief Minister (Shri Bansi Lal): Sir, it is correct that the present building of the Government college of women, Rohtak, is located in a low lying area and the rainy water accumulates in the college premises during the rainy season. To overcome this difficulty, the education Department is taking immediate steps to provide storm water drainage

*Call Attention Notice No. 5 appears in H.V.S. Debate, Volume I, No. 3, dated the 18th July, 1968

Arrangement at a total cost of rs. 42,317. Apart from this, department is also considering a proposal for the counstruction of boundary wall for this college at an estimated cost of Rs. 20,000.

A decision has also beentaken to shift the College to a new building. The suitability of the District jail, Rohtak with such alterations and modifications as may be necessay, is being considered for this purpose. Necessary action is already being taken in this regar.

As regards the rusults of the Government college for women, Rohtak, it may be stated the during the last two years the results of the college were highter than the University pass percentage as the following statement will show:-

Year 1965-66

	College Pass Percentage	University pass Percentage
Pre University	78.1	52.6
Pre Medical	61.7	46.5
B.A. part-I	63.6	53.8

B.A. Part-II	80.6	46.4
B.A. Part-III	70.5	65.7

Year 1966-67

Pre University	64.7	40.6
Pre-Medical	55.5	46.1
B.A. Part-I	48.8	47.1
B.A. Part-II	77.3	67.1
B.A. Part-III	95.0	77.0

Election of the Deputy Speaker

Mr. Speaker: Next item on the Agenda for today is the Election of the Deputy Speaker.

Chief Minister (Shir Bansi Lal): Sir, I beg to move-

That Smt. Lehwati Jain, a Member of the Haryana Legislative Assembly, who is present in the House, be elected as Deputy Speaker of the House.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Sir, I second the proposal made by the Chief Minister.

That Shrimati Lekhwati Jain, a Member of the Haryana Legislative Assembly who is present in House, be elected a Deputy Speaker of the House.

Mr. Speaker: Motion moved by the Chief Minister and seconded by the Finance Minister is:-

That Shrimati Lekhwati Jain, a Member of the Haryana Legislative Assembly, who is present in the House, be elected as Deputy Speaker of the House.

Malik Mukhtiar Singh: Sir, I beg to move :-

That Shrimati Sharda Rani Kunwar, a Member of Haryana Legislative Assembly who is present in the House, be elected as Deputy Speaker of the House.

Shri Mangal Sein: Sir, I second the proposal made by Malik Mukhtiar Singh

श्रीमती शारदा रानी: मैं अपना नाम विदज्ञा करती हूँ।

Mr. Speaker: Is there any other proposal?

Since there is only one proposal before the House that Shrimati Lekhwati Jain be elected as Deputy Speaker, I declare her to have been elected as the Deputy Speaker, unanimously.

(At this state Shrimati Lekhwati Jain, escorted by the Leader of the House and the Leader of the Opposition occupied the seat meant for the Deputy Speaker).

(Thumping from the House)

मुख्य मंत्री: स्पीकर साहिब, मैं श्रीमती लेखवती जैन को उनके डिप्टी स्पीकर पद पर चुने जाने के लिए बधाई देता हूँ। जनबा, यह तो सदन का मालूक ही है कि वह इस पद के लिए नई नहीं है इससे पहले भी वह पंजाब विधान परिषद् में डिप्टी चेयरमैन के पद पर रह चुकी है। मुझे उनसे पूरी आशा है कि वह अपने काम को अच्छी तरह से सरअंजाम देती रहेगी। अन्त में मैं उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ।

राव बीरेन्द्र सिंह: जनबा स्पीकर साहिब, इतने ऊंचे पद के लिए चुने जाने पर मैं अपनी लायक बहन को हृदय से बंधाई देता हूँ। यह सबके लिए एक फखर की बात है उनका इस पद का ग्रहण करना हम सबसे लिए और हाउस के लिए इज्जत अफजाई का बायस है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब को भी मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत लायन बहन को और बहुत तजुरुबेकार बहन का इस हाउस की कार्यवाही चलाने के लिए आपके डिप्टी की तजवीज की।

बहन लेखवती की खिदमात से सारा हाउस वाकिफ है। वह 40-50 वर्ष पहिले हमारे पिता जी के साथ मैम्बर रह चुकी है। वह उस वक्त पहले पंजाब में भी पहली महिला सदस्या थी जो कांग्रेस ने चुनकर भेजी थी। इस लिहाज से वह हमारे सब के दम्यान सब से सीनियर मैम्बर है। ऐसी सीनियर मैम्बर का चुना जाना हाउस के ऊपर अच्छा असर रखेगा। और इस हाउस के डैकोरम को मेनटेन करने में मदद होगी। इन शब्दों के साथ मैं

आपोजीशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहन लेखवती जैन को मुबारिकबाद पेश करता हूं।

मलिक मुख्तियान सिंह (सोनीपत): जो हाउस की तरफ से बहन लेखवती जैन का डिप्टी स्पीकर के औहदे पर चुनाव हुआ उसके लिए मैं अपने ग्रुप की तरफ से उनको बधाई देने में एसोशिएट करता हूं। इनके पीछे की हिस्ट्री ओर उनका तजरूबा राव साहिब ने बतला दिया है। मुझे खुशी है कि पंजाब में जो पहली डिप्टी स्पीकर महिला थी, उनसे ही इन्हें भी यह औहदा विरासत में मिला है। (विघ्न) वह इन औहदे की निश्चय ही मुस्तहक थी और कुछ मैमबर साहबन तो यहां तक कह रहे थे कि वह डिप्टी स्पीकर रहते हुए भी स्पीकर का काम करेंगी। उनकी लियाकत से सभी वाकिफ है। मैं उनके इस पद पर चुने जाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): स्पीकर साहिब, मैं अपने जिले अम्बाले की तरफ से और अपनी कंस्टीचुएसी की तरफ से बहन लेखवती जी को मुबारिकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से वह पहले कौंसिल में बतौर डिप्टी चेयरमैन अपना फर्ज निभाती रही है उसी तरह अब भी अपना फर्ज खुशअसलूबी से सरअंजाम देगी। इसक साथ ही मुझे आशा है कि जो हमारा नारायणगढ़ का पिछड़ा हुआ इलाका है इस को ऊपर उठाने के लिएहाथ बटाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी मौजूदगी में हमारी तरक्की जरूर होगी।

चौधरी राम प्रकाश (मुलाना): स्पीकर साहिब, मैं श्रीमती लेखवती जी के मुबारिकबाद पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम एक ही जिले के रहने वाले हैं और वह मेरी बहुत पुरानी साथी रही है। हमें बहुत अरसा इकट्ठे काम करने का मौका मिला है वह बहुत की काबिल लेडी है और होना भी चाहिए। स्पीकर साहिब जहां तक मेरे भाई मलिक मुख्तियार सिंह जी ने फरमाया है कि शायद बहनजी आप की जगह ले लें वह मैं समझता हूँ कि नामुमकिन बात है क्योंकि आप एक फौजी जरनेल हैं, आप से आगे वहकैसे निकल सकती हैं। हां एक बात मैं में मानता हूँ कि वह आप की गैरहाजरी में सारा काम पूरा कर सकती है। इन शब्दों के साथ मैं तमाम अम्बाला जिला की तरफ से इनको बधाई देता हूँ।

चौधरी नेकी राम: स्पीकर साहिब, चूंकि जिलावार सिलसिला शुरू हो गया है इस लिए मैं आपने जिला जींद की तरफ से बहन जी को मुबारिकबाद पेश करता हूँ। यह बहुत पुरानी ओर तजरुबेकार सदस्य है। जब ज्यायंट पंजाब होता था तो उस वक्त होता मैंने इनको असैंबली में सुना था। मैं समझता हूँ कि इनका चुनाव बिल्कुल मुनासिब हुआ है। इसलिए मैं अपने जिले की तरफ से इनको फिर एक बाद बधाई देता हूँ।

सूबेदार प्रभु सिंह (भिवानी खेड़ा) : स्पीकर साहिब, बहन जी का डिप्टी स्पीकर चुना जाना कोई नही बात नही है यह तो पुरानी तजरुबेकार मैम्बर है और पहले भी कौंसिल में डिप्टी चेयरमैन के पद पर रह चुकी है। इसलिए इनका इस पद पर चुना

जाना जरूरी था। राव साहिब ने इनकी तारीफ अभी की है। यह बहुत काबिल और लायक मैम्बर है। एक मौका हमारे देखने में आया, जब जमीर फरोशो का मीना बाजार गर्म हुआ था तो इस बहन ने अपनी जमीर को बचा कर रखा और यह बिकी नहीं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि बहन जी के इस किस्म के कैरकुटर से सभी बहनों और भाइयों को सबक खीखचना चाहिए और इनके नकषे कमद पर चलाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं बहन जी को एक बार फिर मुबारिकवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम इनका पूरा सहयोग देंगे।

चौधरी नारायण सिंह (जुलाना): स्पीकर साहिब, मैं बहन जी को डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर अपनी ओर से बधाई पेश करता हूँ। इनको सदनका काम चलाने का काफी तजरूबा है? मुझे आशा है कि इस सदन के सदस्यों के जो अधिकार हैं वह इनके हाथों में सुरक्षित रहेंगे। औरतें तो वैसे ही बहुत कोमल हृदय और निष्पक्ष तरीके से काम करने वाली होती हैं। यह इनके अच्छे गुणों का नतीजा ही है। जो हाउस ने इनको एक मत से अपना डिप्टी स्पीकर चुना है। इसलिए मैं इन को बधाई देता हूँ।

Mr. Speaker: I also associate myself with the feelings expressed in the House and congratulate you on your election as Deputy Speaker. I am more happy because you have got the necessary experience and you will take a considerable load off my shoulders.

श्रीमती लेखवती जैन (अम्बाला शहर): स्पीकर साहिब मैं आज इस सदन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूं जिस ने मुझ इस पद के लिए चुना है। स्पीकर साहिब, मैं सदन के सामने एक ही बात कह सकती हूं कि मैं बतौर डिप्टी स्पीकर अपने फरायज जो अच्छी तरफ निभाने की कोशिश करूंगी और इस सदन के डैकोरम को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूंगी। स्पीकर साहिब, आप की विसातित से मैं अपोजीशन के मैम्बरों को भी यकीन दिलाना चाहती हूं कि मैं एज डिप्टी स्पीकर दोनों आंखों से दोनों तरफ बराबर देखा करूंगी (प्रशसां) स्पीकर साहिब, मेरे बारे में बहुत कछ कहा गया है, मैं उसे कल यह कह सकती हूं कि शायद मुझ में यह खूबियां न हो। यह तो उनकी अपनी शुभ भावनाएं है जिसके लिए उन्होंने इतनाकुछ मेरे बारे में कहा है। मैं यकीन दिलाना चाहती हूं जिस तरह के विचार आप ने मेरे प्रति रखे है मैं उसी तरह से अपनी फर्ज निभाने की कोशिश करूंगी। स्पीकर साहिब, जब मैं बम्बई में प्रीजाईडिंग औफिसर्ज कानफ्रेन्स में गई थी तो वहां पर मुझ यह प्रश्न किया गया कि आप अपोजीशन के साथ किस तरह से काम निभाते है, क्या आपको उनकी तरफ से मुश्किल पेश तो नहीं आती। तो मैंने उनको कहा कि मुझ दाएं हाथ वाले मेम्बर सहयोग तो देते ही है और जो बाएं हाथ वाले अपोजीशन के मैम्बर है वह भी सहयोग देते है और मैंने बताया कि मुझे शाजीनादर ही किसी के खिलाफ शिकायत का मौका मिला है। मेरी रूलिंग को अपोजीशन ने भी बहुत अच्छी तरह से माना और मुझ पूरा पूरा सहयोग दिया। अब भी मैं आशा रखती हूं

कि मुझ सारे हाउस से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा जिससे मैं हाउस को सुचारू रूप से चला सकूंगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन का धन्यवाद करती हूँ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Finance Minister (Shrimati Om prabha Jain): Sir, I beg to lay on the the Table a copy of the First Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation as required under section 38(3) of the State Financial Corporation Act, 1951

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Mr. Speaker: Before the House takes up the next item on the Agenda I want to make an observation. According to the present schedule two days, i.e., 22nd and 23rd July, 1968, have been allotted for the general discussion on the Budget for the year 1968-69. During these days the Members are at liberty to discuss the Budget as a whole or any question of principle involved therein. But such discussion/speech should be strictly relevant to the matter before the Assembly. I also feel that a large number of Members did not get an opportunity to speak on the Governor's Address. I, therefore, do suggest that they may be given an encouragement to participate in the debate.

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET FOR THE YEAR 1968-69

राव बीरेन्द सिंह (अटेली): स्पीकर साहिब, हरियाणा में नई कांग्रेस सरकार बनने के बार हरियाणा के प्रदेश के लिए जो बजट हाउस में पेश हुआ है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हरियाणा छोटी सी लेकिन आगे बढ़ती हुई स्टेट है और इसकी तरक्की में कुछ कारणों से अब तक काफी रुकावटें पड़ती रही। हब मिडटर्म पोल के बाद कांग्रेस 48 मेम्बर हाउस में लेकरआई तो उम्मीद कर सकते थे। कि एक मजबूत स्टेबल सरकार बनेगी और वह इस स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ कदम उठाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बजट हमारी सरकार ने पेश किया है उसमें कोई पोजेटिव एप्रोच इस सरकार ने नहीं रखी और मालूम होता है कि स्टेट की तरक्की के मामला में भी कई बात सोचते हुए इन्होंने डर नहीं छोड़ा और इन्हे डर लगता है। मैं समझता हूँ कि यह बेहतरीन मौका था कि कोई सरकार अगर उसे जनता का विश्वास हासिल हो तो मजबूती के साथ आइंदा पांच साल में यह क्या करना चाहती है उसकी कुछ झलक अपने इस पहले बजट में दिखाती लेकिन इस ने सब को अन्धेरे में रखा है और ठोस बात इन्होंने नहीं बताई। इस सरकार ने स्टेट के बजट में आठ करोड़ रूप्य का खसारा दिखाया है लेकिन यह खसारा किस तरीके से पूरा किया जाएगा इस के बारे में कोई इशारा नहीं दिया है छोटी छोटी बातों

में निहायत सस्ती शुहरत हासिल करने की कोशिश की है। इतना बड़ा घाटा होते हुए कोई ठोस कदम इन्होंने इस खसारे को मीट करने के लिए और स्टेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं उठाया और यह नहीं बताया.....

मुख्य मंत्री: यह आमदनी कैसे बढ़ सकती है इसके बारे में आप अपनी स्पीच में हमें कोई सुझाव दे देना।

राव बीरेन्द्र सिंह: जब आप पूछेंगे तो सुझाव भी बता दूंगा।

मुख्य मंत्री: मैंने तो पूछ लिया है आप बता दें अपनी स्पीच में।

राव बीरेन्द्र सिंह: इस बार मैं फिर बाद में आप से बात डिटेल में करूंगा पहले आपकी कार्यवाही देखूंगा कि आप क्या करते हैं।

मुख्य मंत्री: जो कुछ करना था वह तो करी दिया अब आप सुझाव दे।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहिब, हमारा हरियाणा एक जरई प्रदेश है और इस सरकार ने ऐग्रीकलचर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें इसे फो देने के लिये सोची है कि क्राप्स सप्र करेगे, बीज और खाद देगे और इनसैटिव प्राईस देने और कुछ छोटी छोटी स्कीमों के बारे में जिक्र किया है? मैं समझता हूँ कि

यह बातें हमारी ऐग्रीकल्चर को हमेशा के लिये सुधारने के लिये नाफ़ी है। इन्होंने एतराफ़ किया है कि तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम हरियाणा के जरई मैदान में 1967-68 के साल में उठाया गया था। तो इसका सारा क्रेडिट संयुक्त दल की सरकार को जाता है जिसके वक्त में यह कदम उठाया गया कि उस एक साल में अनाज की पैदावार 25 लाख टन से बढ़कर 31 लाख टन हो गई। अब भी यह उस पालिसी की हिमायत करते हैं जो संयुक्त दल की सरकार ने बनाई थी। उस वक्त बड़ा शोर डाला गया कि मोटे अनाज की बरामद क्यों खोल दी गई लेकिन अब यह हमारी उस पालिसी का मानते हैं और इन्होंने खुद बरामद खोल दी है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक साल में छः लाख टन की पैदावार कैसे बढ़ गई और मैं चाहता हूँ कि इस के पीछे जो बातें हैं उनके बारे में इस सरकार को गौर करना चाहिए। इस एक ही साल में इतनी पैदावार बढ़ जाने के पीछे यह बात थी कि किसान यह समझता था कि यह सरकार उसकी है और इस वजह से उसे दिल में जोश था उमंग थी और किसान ने जमीने साथ प्यार दिखाया (इस समय मुख्य मंत्री बाहर जाने लगे) अभी चल पड़ें..... (शोर)।

मुख्य मंत्री: अभी आता हूँ।

राव बीरेन्द्र सिंह: तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक साल में छः लाख टन पैदावार में इजाफ़ा हुआ। इस बारे में मैं मानता हूँ कि हमारे पास किसान के लिये दिल खोल कर खर्च करने के लिए रूपया नहीं था और हमने किसान की कोई खास इमदाद नहीं की

लेकिन किसान को तसल्ली थी कि यह सरकार उसकी है वह उसे पीछे नहीं रहने देगी और उसकी मेहनत का उसे जरूर मुआवजा मिलेगा। इसलिए उसने मेहनत से काम किया और पैदावार में इजाफा किया। सरकार जो मौका के मुताबिक कर सकती थी वह उसने किया और उन्हें वक्त पर बीज पहुंचा दिया, खाद दे दी और उसे कुओं के लिए सीमेंट उसको पहुंचा दिया लेकिन अब हालत यह है कि उसे कुओं की मरम्मत के लिए सीमेंट नहीं मिलता हालांकि वही कारखाने है और वही पैदावार है मगर एक-एक बोरी के लिये धक्के खात है। जितने दिन यह संयुक्त दल की सरकार रही किसी किसान को इसके लिए बी०डी०ओ० के दफतर में नहीं जाना पड़ा। उन्हें घरों में सीमेंट पहुंचाया गया और पंचायतों के जरिये सप्लाई किया गया। लेकिन आज एक एक बोरी के लिये परचियों को लिये बैठे हैं कि रैंडक्रास का चन्दा दो और अब ता लाटरी सिस्टम चला रहें कि लाटरी का पहले टिकट लो हब बोरी मिलेगी.....(विध्न) हमने किसान को हर किस्म का इनसैटिव दिया और फेयर प्राईस एश्योर की। चाहे गन्ना हो, मक्की हो, कपास हो या गेहूं हो हर जरई पैदावार के लिये किसान को फेयर और इनसैटिव प्राईस दिलाने की पूरी कोशिश की जिससे किसान को तसल्ली हुई और उसे अन्दर विश्वास पैदा हुआ जिसकी वजह से उसने दिल लगा कर जमीन को कमाया को कमाया उसका नतीजा यह निकला कि उस एक साल में ही 6-7 लाख टन पैदावार बढ़ गई जितनी कि पिछले बीस साल में इस पार्टी की सरकार नहीं बढ़ा सकी थी। हब फिर इनकी कांग्रेस सरकार बनी

है और उसके बनते ही किसान पर ओले पड़े। फूड कार्पोरेशन के अफसर मण्डियों में घुस पड़े और किसी को नजदीक नहीं आने दिया। व्यापारियों से पूल कर लिया। किसान का माल मण्डियों में सड़ता है औ फूड कार्पोरेशन के अफसर किसान के अच्छे से अच्छे माल को रिजैक्ट कर देते हैं। किसान बेचारे सुबह से शाम तक गर्मी में ओर सर्दी में मरते रहते हैं। वे हर तरह के कष्ट बर्दाश्त करते हैं लेकिन जब वे मण्डियों में आते हैं तो उनके साथ बड़ी बेइन्साफी होती है। वे आते ही मण्डी में व्यापारियों और फूड कार्पोरेशन के औफिसरों के हाथ पड़ जाते हैं किसान का जो बढ़िया माल होता है उसको वे रिजैक्ट कर देते हैं और बाद में ढेरियां लगाकर अच्छी क्वालिटी का बना कर बेचते हैं। इसमें जितना मुनाफा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। यह सब कुछ किसान की जेब काटने के लिए होता है। आज बड़े अफसोस की बात है कि फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई है। संयुक्त दल के राज में जो राहत उनको मिली थी अब नहीं मिलेगी। स्पीकर साहिब, पिछले इन्वैक्शन में कांग्रेस ने इलैक्शन जीतने के लिये बहुत सी गिलतियां की, लोगों को गलत रास्तें दिखाये गये इस तर छल कप से उन से वोट छीने लेकिन वे लोग जानते हैं कि इनका इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ावा देने के लिए किसान के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब, अच्छे वकील भी हैं। और किसान भी। पैदायशी किसान भी हैं। वे किसानों की दिक्कतों से और उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी से वाकिफ हैं। उन्हें देहाती

जिन्दगी का व्यक्तिगत तजरूबा हैं इस सम्बन्ध में संयुक्त दल की सरकार ने जो कुछ अच्छी बातें की हैं उन पर इनको अमल करना चाहिए।

मुख्य मंत्री: मुझे अफसोस है कि इसमें अमल की कोई बात नहीं है। इसमें एक भी अच्छी बात नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह: इसमें एक यही बात अच्छी है चौधरी साहिब, कि संयुक्त दल की मेहरबानी से आप और आपके अन्य साथी यहां परि विराजमान हैं। (शोर)

मुख्य मंत्री: ठीक है, बड़े भाई का इतना सुख तो होना ही चाहिए। आप कोई गैर, नहीं है, अपने ही है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: आप की मेहरबानी से बाहर भी कुछ मेम्बर बैड़े हुए हैं (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह: ठीक है वे बैठे हुए हैं, उनके बैठने में आपका उतना हाथ नहीं हैं जितना कि मेरा है।

मुख्य मंत्री: उन्होंने भी तो आपके हाथकी है बात की है।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहिबा, हाउस में रोजाना डिफैक्शन का जिक्र होता है। कांग्रेस इस लिये नहीं जीती कि लोग इसे पसन्द करते हैं। पता नहीं यह किस मुंह से कहते हैं हम लोगों ने डिफैक्शन की हैं कांग्रेस पार्टी पहले भी डिफैक्शन करती

आई है। और अब भी इसी ने की है। जहां तक हमार ताल्लुक है, हमने डिफैक्शन नहीं की है, हमने अगर की है तो बगावत की थी और यह बगावत किसी लालच के लिए नहीं थी।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, जब राव साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय अखबार में एक कार्टून निकला था कि चूजे देकर भी कुछ इनाम मिलता है।

राव बीरेन्द्र सिंह: वे चूजे तो हब खाये गये हैं, उनको अब छोड़ दे। स्पीकर साहब, हमने असूल की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर और लोगों के जजबात को मदेनजर रखते हुए बगावत की है। हरियाणा प्रांत के लोगों के हकूक के लिये, चण्डीगढ़ और भाखड़ा को बचाने के लिए हमने खुली बगावत की और अब जब दुबारा चुनाव हुए तो उसमें भी हम जीते हैं। हम अपने इरादे पर कायम रहे और कांग्रेस हाइकमांड से टिकट लेने के लिए लुढ़के नहीं, जिस तरफ चौधरी बन्सी लाल जी ने किया। इस किस्म के लोगों ने हरियाणा नाम बदनाम किया है।

मुख्य मंत्री: आया राम और गया राम तो गुडघगांव जिले के थे।

राव बीरेन्द्र सिंह: इस इलैक्शन में जनता ने बड़ा इन्साफ किया। वे लोग इधर से उधर डिफैक्शन तो जनता ने अपने आप को छांट दी हैं सिर्फ कुछ कांग्रेसी भाई हमारी अपनी फूट की वजह से आ गये। और मैं समझता हूँ कि यह कांग्रेस की जीत

नहीं है क्योंकि कांग्रेस की जीत के लिए सारे भारतवर्ष की ताकत लगी हुई थी। कांग्रेस पार्टी की ताकत, पुलिस की ताकत और कुछ अपोजीशन पार्टी में फूट, इस तरह तमाम शक्तियाँ जुटी हुई थी। इतनी ताकत होने के बावजूद भी यह 48 सीटें लेकर सामने आई। विशाल हरियाणा पार्टी ने 30 सीटें लड़ी और 16 मेम्बर जीत कर आये। वे अपनी ताकत से ओर जनता का ताकत से आये, गलत तरीके इस्तेमाल करके नहीं आये। हमने सारे हिन्दूस्तान की जीपें तथा पूंजिपतियों से मदद नहीं ली। आपने 28 लाख रायों में से 10 लाख राय ली होगी लेकिन हमारी विशाल हरियाणा पार्टी ने कोई 15 लाख राय ली और 16 आदमी जीतकर आये और इस शान के साथ जीते कि आपका इलैक्शन पर खर्चा हुआ सारा पैसा बेकार हो गया। दस आदमी हमारे ऐसे हैं जो केवल चार चार छः छः सौ वोटों से हारे हैं।

चौधरी लाल सिंह: राव साहिब, आप को यह भी तो पता होगा कि मेरे इलाके के तमाम उम्मीदवारों की जमानते जब्त हो गई हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह: उन को समझ ही नहीं थी कि क्या करना है। वहां पर आप जैसे ही आदमी होंगे। (शोर)

श्रम मंत्री: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मेम्बर साहिब को केवल बजट पर ही बोलना चाहिए, यह तो इलैक्शन पर बोल रहे हैं, इन्हें इलैक्शन पर नहीं बोलना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह: बात तो आप ही शुरू करते हैं। मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ।

Mr. Speaker: I think Rao Sahib is quite reasonable to make observations when interruptions are made during the course of his speech. May I request hon. Members not to interrupt him.

चौधरी रणबीर सिंह: मानयोग अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मानयोग राव साहब ने मैम्बर के प्रति चूजे का शब्द इस्तेमाल किया है वह कार्यवाही से हटवा दिया जाना चाहिए?

Mr. Speaker: You are too late.

चौधरी रणबीर सिंह: उन्होंने अभी दो मिनट पहले ही कहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह: चन्द्रावती जी ने कहा, तब तो आपने इतराज नहीं किया लेकिन जब मैंने कहा तो इतराज कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: मैंने तो चूजोंके बदले इनाम देने की बात कही थी।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि यह बजट ऐसा अन्धेरा बजट है जिस में हर सैक्शन यह सोचता रहेगा कि पता नहीं घाटा किस तरह से पूरा किया जाएगा, ने मालूम किस के सिर पर य बिजली पड़े और मुझे तो यह डर है

कि कही ये सारा घाटा एक एग्रीकल्चर के सैक्टर से ही पूरा करने की कोशिश न करें।

मुख्य मंत्री: आप कृपया यह घाटा पूरा करने के लिए कोई सुझाव दे दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह: सुझावों की ओर मैं आ रहा हूँ। तो स्पीकर साहिब, कहां तो माल गुजारी माफ करने की बात हो रही थी और कहां इसे बढ़ाने की सोच रहे हैं। मुझे तो डर है कि कही ये एक रूपए की माल गुजारी को बढ़ाकर बीस या पच्चीस रूपए न करे दे। स्पीकर साहिब, यह एक डर है जिसे कलिएमैं आज से ही परेशान हूँ। बजाय इसके कि कल हमें एजिटेशन करने पर उतरना पड़े, मैं आज ही यह बात सरकार का बता देना चाहता हूँ कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

स्पीकर साहिब, इन्होंने फीस माफ करने की एक छोटी सी चीज करके बड़ी तारीफ हासिल करने की कोशिश की है। फीस सिर्फ मालदार आदमियों के ऊपर लगी हुई थी। फीस माफ होने से श्री मंगलसेन तो जरूर खुश होंगे क्योंकि संयुक्त दल की सरकार के समय में भी ये इस चीज के हम में थे। लेकिन मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ मैं तो चाहता हूँ कि हरिजनों से फीस नहीं ली जानी चाहिए और जिनकी आमदनी अठारह सौ से कम हो उनसे फीस नहीं ली जानी चाहिए, पन्द्रह फीसदी लड़कों से और तेतीस फीसदी लड़कियों से मैरिट के लिहाज से फीस नहीं ली

जानी चाहिए परन्तु जो लोग दे सकते हैं। उनसे अगर फील ले ली जाए तो कोई अन्याय की बात नहीं। इस फीस माफी से तो स्पीकर साहिब ज्यादा फायदा कस्बों के अन्दर, शहरों के अन्दर रहने वाले बड़ी आय वाले लोगों को होगा।

गरीब को इससे कोई फायदा नहीं। फिर स्पीकर साहिब यही नहीं, इन्होंने एक तरफ तो फीस माफ कर दी लेकिन दूसरी तरिकों से देहात वालों की जेबों से पैसे निकलाने की कोशिश की है। संयुक्त दल की सरकार ने स्कूल अपग्रेड करने के लिए किसी पंचायत से कभी किसी किस्म का कन्ट्रीब्यूशन नहीं लिया था परन्तु यह सरकार अब यह करने जा रही है कि यदिकही मिडल स्कूल से हाई स्कूल बनवाना हो तो 63,000 रूपए देने पड़ेगे और यदि प्राइमरी स्कूल को मिडल स्कूल अपग्रेड करवाना हो तो 93,000 रूपये देने पड़ेगे। मुझ स्पीकर साहिब, इस बात का बड़ा एतराज है। बड़े शौक से ये फीस माफ करें मगर संयुक्त दल सरकार ने पंचायतों से जो कन्ट्रीब्यूशन न लेने को फैसला किया था उस पर हमारे मुख्य मंत्री जी खयाल करें। अगर ऐसा ये करें तब तो मैं इनका शुक्रगुजार हूंगा, इनकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन एक तरफ तो यदि ये फीस माफ कर दें और दूसरी तरफ दूसरें तरिकों से गरीब लोगों से पैसे इकट्ठे करें तो यह कोई रिलीफ की बात नहीं, यह तो धोखा-धड़ी है, फरेब है।

स्पीकर साहिब, और भी चन्द चीजें हैं जिनके मुताल्लिक मैं मुख्तसर तरीके से जिक्र करूंगा। जिस तरीके से हमारी कांग्रेस

सरकार और चौधरी बंसी लाल जी ने स्टेट का सर्विसिज को भी बरबाद करने पर ये तुल हुए है। अपनी पिछली स्पीच में चीफ मिनिस्टर साहिब ने बड़े दावे किए कि वे पिछली सरकार की तरफ मुकदमें आदि वापिस लेने के गलत काम नहीं करेंगे। मुझ बड़े अफसोस क कहना पड़ता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए, हाउस के लीटर होते हुए और साथ ही एक वकील होते हुए, स्पीकर साहिब, चौधरी बंसी लाल जी ने धारा 376 वाल केस को वापिस लिए जाने की बात बिल्कुल गलत कही। संयुक्त दल की सरकार ने ऐसा कोई केस वापिस नहीं लिया था लेकिन इन्होंने बड़े जोर के साथ, फाइल हिला हिला कर, यहां कहा कि केस वापिस लिया गया।

मुख्य मंत्री: अगर कहें तो फाइल फिस से ले आऊं।

राव बीरेन्द्र सिंह: मै, स्पीकर साहिब इस बात को चैलेंज करता हूं और अर्ज करता हूं कि कोई केस 376 को किसी की मिनिस्टर बनाने की खातर वापिस नहीं लिया गया। वे केस तो अदालत से डिसचार्ज हुआ था। हालांकि अफसर साहिबान की यह रिपोर्ट थी कि यह केस पिछली कांग्रेस सरकार ने दुश्मनी की वजह से गलत बनाया हुआ, हमने इन्कार किया कि कुछ भी हो हम केस को वापिस नहीं करेंगे। कसम लेने के वक्त जब मुझ पता लगा कि फलां आदमी के खिलाफ इस किस्म का मुकदमा है, मैने उसे कसम नहीं लेने दी, उसे कसस लेने से यह कह कर हटा दिया कि यदि हम ऐसा करेंगे तो यह हमारे नाम पर एक धब्बा

होगा। जब अदालत से केस डिसचार्ज हुआ, तभी हमने उन्हें मिस्टर बनाया। स्पीकर साहिब, पता नहीं हमारे मुख्य मंत्री साहिब को कौन गुमराह करता है। मेरी इनसे विनती है कि बजाय दूसरों की बातों में आने के वे स्वयं कागज पढ़ लिया करें। (विरोधी पक्ष में प्रशंसा) स्पीकर साहिब, यह एक ऐसी गलत चीज है जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी आ सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी साहिब अभी नए नए जनरल है, इसलिए इनको माफ कर दिया जाए। (विरोधी पक्ष से प्रशंसा)। खैर इस चीज में ज्यादा न जाता हुआ मैं इनको एक सुझाव देना चाहूँगा कि इस तरह से सर्विसिज को डिमोरेलाईज करने से, केवल उनकी तनख्वाह या भत्ते बढ़ाते रहने से कुछ नहीं बनता। हरियाणा तो तरक्की तभी करेगा जब कि सर्विसिज गैर जानबदार, ईमानदार और मेहनती होगी और उसके लिए सरकार को और सब से पहले सरकार आपको (मुख्य मंत्री की तरफ इशारा किरते हुए) कुछ मिसालें कारम करनी पड़ेगी, कुछ रास्ता दिखाना होगा ताकि आपको देखकर बाकी लोग भी ठीक रास्ते पर चलें।

मुख्य मंत्र: आप आराम से बैठे रहिए, हम बड़े अच्छे ढंग से काम करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह: फिर कोओप्रेटिव मार्किटिंग फ़ैडरेशन क लिए इन्होंने लिखा है कि ये बहुम कुछ करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, स्पीकर साहिब, कि इस सरकार के बनते ही उस मार्किटिंग फ़ैडरेशन पर, जिस के इलैक्टिड चेयरमैन इस

हाउस के ही एक मैम्बर है, सबसे पहले नजला गिरा। मैं तो इस कोओपरेटिव मूवमेंट से दूर ही रहता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या क्या इसमें होता है, परन्तु मुझे पता लगा है कि इस मार्किटिंग फ़ैडरेशन को क्लास बी० का दर्जा देकर चेयरमैन को खत्म करके अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। स्पीकर साहिब, इस तरीके से इंस्टीच्यूशननज को और इलैक्ट्रिडटड रीप्रैजेंटेटिवज को ये हटायेंगे तो यह स्टेट के लिए कोई बेहतरी की बात नहीं होगी।

अभी म्यूनिसिपल कमेटियों के इलैक्शन हुए। हमारे नौजवान साथी बड़े जोशी भाई गुड़गांव के, खास तौर पर हरियाणों की सेवा के लिए, श्री खुरशीद अहमद जी ने आते ही एक अजीब सिलसिला शुरू कर दिया और एक कचूमर निकालने की पालिसी समझी। सबसे पहले उन्होंने करनाल म्यूनिसिपल कमेटी को सुपरसीड किया फिर सोहना म्यूनिसिपल कमेटी को भी नोटिस दे दिया है। और भी कई कमेटियों है वे कहते हैं जब तह हम एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं जितनी भी मुखालिक कमेटिया है ओर कोओपरेटिव सोसाइटियां है। सबको उड़ा देंगे।

स्पीकर साहिब, आप को क्या बताऊ नारलौल की म्यूनिसिपल कमेटी है वहां पर तीन वर्ष से प्रेजिडेन्ट की जगह पर वाईस प्रेजिडेंट काम चला रहा हैं इनैक्शन उस कमेटी का ड्यू था, दूसरी कमेटियों के साथ ही होना था, लेकिन इन लोगों ने इलैक्शन पोस्टपोन कर दिया। पता नहीं क्यों और किसलिए किया। वहां पर जो वाईस प्रेजिडेन्ट है उनके खिलाफ करप्शन की

इन्कवायरी भी हो चुकी है लेकिन फिर भी इन्होंने इलैक्शन पोस्टपोन कराये यह सोचते हुए कि इलैक्शन में जनता की मर्जी होती है पता नहीं वह सि को चुनती। इसके नतीजे के तौर पर वह अपनी कुर्सी पर दो साल से विराजमान है। मैं तो समझता हूँ कि यह सिर्फ इस लिए किया गया क्योंकि वहाँ जो वाईस प्रेजिडेंट है वह मेरी पेटिशन में गवाह है और सिर्फ गवाह होने की वजह से, उनके कहने पर म्यूनिसिपल कमेटी के इलैक्शन पोस्टपोन करवा दिये गये हैं। तो यह सरकार स्पीकर साहिब, इतनी ज्यादातियों कर रही है कि अगर इनकी एफिशिएन्सी के बारे में अर्ज करूँ कि 9 तारीख को झगड़ा होना है तो 8 तारीख को इनकी पुलिस मूव करना शुरू कर देती है। इसके इलावा ये लोग एक तरफ तो एज्युकेशनल इन्स्टीच्यूशनज को बढ़ावा देना चाहते हैं और दूसरी ओर स्पीकर साहिब, आपको यह जानकारी अफसोस होगा कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने कीकमई से प्राइवेट इन्स्टीच्यूशनज खोल रही है उन सब पर ये लोग ताला लगवा रिहे है। जिन लोगों ने चालीस चालीस लाख रूपए से कालेज खड़े किये हुए हैं उनको ये बन्द कर रहे हैं। स्पीकर साहिब, हरियाणा एक बैकवर्ड स्टेट है। इस स्टेट में तालीम की बहुत कमी है। यहाँ पर लोगों ने अपनी हिम्मत से इन्स्टीच्यूशनज खो रखी है। लोगों ने अपनी खेती की जमीन स्कूल ओर कालेज खोलने के लिए दी है। मगर इन सब बातों को इनका कोई ध्यान नहीं। ये उनका चलता हुआ नहीं देखना चाहते। स्पीकर साहिब एक इन्स्टीच्यूशन एम०इ०एड० का रिवाड़ी में है। वह अकेला हरियाणा में एम०ए०एड० का कालेज

है और मेरे नाम पर चल रहा है लेकिन वहां पर इन लोगों ने जो कुछ किया वह बड़ा दुखदायी है। वहां से वायरलैस करते हैं कि हमें एन्टी डेक्वायट के लिए पुलिस चाहिए। उसी समय पुलिस का एसी०पी०डी०आई०जी० जाते हैं और सीधे जा कर कालेज के रवाजे बन्द करवा देते हैं। स्पीकर साहब, यह तो इस सरकार की हालत है कि ये चलती हुई संस्थाओं को बन्द करना, लोगों पर झूठे मुकदमें बनाना, चाहे वह दफा 107 के हो, चाहे 150 के हो, या दफा 151 के हों सबसे जरूरी काम समझते हैं। अफसरान के ट्रांसफर किये जा रहे हैं जिधर जो लोग इन्हें सूट करते हैं उधर उन्हें लगाया जाता है। ये लोग एक एस०पी० तका को बुला कर कहते हैं कि आपको यह काम करना होगा और यह काम नहीं करना होगा। स्पीकर साहिब बदकिस्मती तो यह है कि अपोजीशन पार्टीज के लोगों से जो सम्बन्ध रखते हैं इन्हें ज्यादा तंग किया जा रहा है इसके लिए एक उदाहरण तो मैं एक एस०पी० साहिब को दे सकता हूँ। उन्हें केवल इसलिए हैरेस किया जा रहा है उनका भाई हमारी पार्टी में शामिल है।

मुख्य मंत्री राव साहिब, आप पहले से ही नाकाबन्दी कर रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह: ऐसी बात नहीं, ला है अदालतें हैं, हाईकोर्ट है, सुप्रीमकोर्ट है। धानधलेबाजी तो वक्ती चलती है। कानून अपनी जगह लेगा और इन्साफ मिलेगा। हमें कानून को नहीं तोड़ना है। जब तक कानून है, हम टोटे में नहीं रहेगे।

स्पीकर साहिब जो ये दावे बढ़ चढ़ कर चीफ मिनिस्टर साहिब करते हैं काश कि इन में सच्चाई होती ये हरियाणे की भलाई चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि हरियाणा एक बढ़ती हुई स्टेट है, इसकी भलाई अकेली कांग्रेस नहीं कर सकती, अकेले चौधरी बन्सीलाल जी नहीं कर सकते और न ही उनकी बालीबाल की टीम हर कर सकती है। (विधन)।

श्री ओमप्रकाश गर्ग: स्पीकर साहिब, राव साहब क टाइम में तो फुटबाल की टीम थी।

चौधरी लाल सिंह: यह बालीबाल की टीम नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की टीम है।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहिब, हरियाणा के बच्चे से, जिसको हरियाणा से प्यार है इन्हे कन्धे से कन्धा मिला कर चलना चाहिये। कम से कम हरियाणे की तरक्की की खातिर तो हम लोगों के साथ हो कर ये चलें। बहुत बातों में हमारे साथ बेइन्साफी हुई है और आयंदा भी होती रहेगी इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो च चंडीगढघ मिलेगा और न भाखड़ा ही मिलेगा चाहे चौधरी बन्सीलाल जी कितना ही कहें कि पिछले दोनों चीफ मिनिस्टर जो कुछ नहीं कर सके उसे वे कर के दिखाएंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँकि अगर वे इनको हासल करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको पूरा पूरा सहयोग देंगे। हरियाणे के साथ और भी बड़े धक्के हुए हैं उन्हें भी सही

करने के लिए इस सरकार को को कोशिश करनी चाहिये। हरियाणा एक डिफिस्टि स्टेट है इसको पंजाब से इसका पूरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिये। पंजाब की तो पहले ही डिवाइलपमेंट बहुत थी। इस का लिए एक कमेटी बैठायी जाय जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने अपनी सारी बातों को पेश करें। दो एक अफसरों को छोड़ कर सिकी भी अफसर ने आज तक हरियाणे का हिस्सा लेने की आवाज नहीं उठायी और जिन दो एक ने अवाजा उठायी भी उनकी आवाज सुनी गयी। हमें अपने केस को फिर से पेश करना चाहिये, क्योकि अब फाइनेंस कमीशन बैठा है। जिस प्रकार से गुजरात महाराष्ट्र से दस करोड़ अपनी डिवाइलपमेंट के लिए री-आर्गेनाइजेशन होने के बाद ले सकता है, क्या वजह है कि हरियाणा पंजाब से या सैन्टर से न ले।

स्पीकर साहिब, इनको अपने नुकसान को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें हम भी इनका साथ देंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब, से कहूंगा कि यह उस सम्बन्ध में लड़ाई लड़े। हम इनका साथ देंगे। जब पंजाब और हरियाणा का डिवाइलपमेंट हुआ था तो एक ही कलम से यह फैसला कर दिया गया कि जितनी भी प्रापर्टी पंजाब की पंजाब से बाहर है वह सारी की सारी पंजाब को जायेगी। इसकी क्या वजह थी? अगर असेट्स और लायबिल्टीज 60 और 40 की रेशों में डिवाइड हुई है या होनी है तो उसी रेशो में से बाहर की प्रापर्टीज है डिवाइड होनी

चाहिए थी। हम ने बड़ी मुश्किल से, लड़कर देहली का कैनाल रेस्ट हाउस लिया था.....

मुख्य मंत्री: इसके बारे में भी तो चिट्ठी मैंने लिखी थी।

राव बीरेन्द्र सिंह: बड़ी मुश्किल से लड़ कर शिमला में एक रेस्ट हाउस लिया थां दिल्ली में भी बड़ी मुश्किल से एक प्लॉट मिला ताकि वहां पर हरियाणा का कोई रेस्ट हाउस बन सके। दिल्ली, मथुरा, बिन्दावन, हरिद्वारा, ऋषिकेश, वगैरा में जितनी सांझे पंजाब सरकार की प्रापरटीज थी वह सह मौजूदा पंजाब के हवाले कर दी गई। शिमला में, जो कि हरियाणा ओर पंजाब के पैसे से बना था, जितनी प्रापरटी थी वह भी पंजाब को दे दी गई। आप इन प्रापरटीज को क्लेम कीजिए। अगर आप को भाखड़े का लोन 60 ओर 40 की रेशों में देना पड़ता है और पानी और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी रेशों में हानी है तो मैं कहूंगा कि हर चीज को जिसमें हरियाणा का शेयर बनता है इसी रेशों में क्लेम किया जाये। रीआर्गेनाईजेशन के वक्त पंजाब एक सरप्लस स्टेट था ओर इसके पास खजाना भरा हुआ था लेकिन हरियाणा जब बना तो वह एक डिफिसिट स्टेट था। अगर आप यह डिफिसिट पंजाब से पूरा नहीं करते तो आप उस को सेंटर से क्लेम कीजिए। आप जोर लगायें हम आप का साथ देंगे। अगर आप को डर लगता है तो आप प्राइम मिनिस्टर और देसाई साहिब

के कमरे के बाहर खडत्रे हो जाइये और हम उनसे बात कर लेंगे...
.....(हंसी)

मुख्य मंत्री: उस वक्त भी तो मैंने दिलाया था।

राव बीरेन्द्र सिंह: आप और कुछ रक के दिखाए लेकिन उल्टा न करना। मैं तो आपोजीशन के नुमाइंदे के तौर पर अज्र करता हूँ कि आप उन चीजों के लेने के लिए पूरा जोर लगाएं। हम भी आप का साथ देंगे। त्वार की लड़ाई तो होती रहती है, इन्वैक्शन में भी लड़ाई रही ओर आगे भी होगी। अगर जनता ने चहा ता हम पावर में आयेंगे और हो सकता है जल्दी आयें.....
....

मुख्य मंत्री: इसका इनको ज्यादा दर्द है।

राव बीरेन्द्र सिंह: लीडर आफ दी आपोजीशन का भी एक औहदा था जो मैंने नहीं देखा था। मिनिस्टर भी रहा, चीफ मिनिस्ट भी बना और मैं एम.एल.ए. और एम.एल.सी भी रहा। लेकिन मैं लीडर आफ दी आपोजीशन की जो जनता के लिए रिसर्पोसिलबिल्टीज है मैं उनको अच्छी तरह से निभाऊंगा। मैं आपकी तरह तखरीबी कारवाइयों में पडूंगा.....(विघ्न) जो करतूतें आप करते जा रहे या आप की सरकार आयंदा करेगी उनको, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जनता ब्रदाशत नहीं करेगी। यहां एक एजीटेशन सा होगा। अगर आप असेम्बली में भी बने बैठे रहे तो जनता आप को बाहर नहीं धूमने देगी।

मुख्य मंत्री कल ही कर लें।

राव बीरेन्द्र सिंह: यह भी करके दिखाएंगे। एक एक हारे हुए कांग्रेसी के हल्के में कितनी ही मुकदमें बनाये जा रहे हैं। जिस सरपंच ने उसको वोट नहीं दी उस के ऊपर मुकदमा बनाया जा रहा है। ऐसे आप को कई गांव मिलेंगे जहां पर यह सब कुछ हो रहा था। मैं चीफ मिनिस्टर साबि से अर्ज करूंगा कि वह ब्यान दे कि एक हारे हुए हम एल.ए. और मनिस्टरज क हल्कों में कितने 107 और 151 के केस बनाये गये हैं हरिजनां से झूठी शिकायते लेकर कि उनको पानी नहीं भरने दिया गया, खेती में नहीं जाने दिया गया, पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है। मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसी चीजोंसे बा आये। सरदार प्रताप सिंह कैरो जैसे भी रहे गये। भगवत दयाल भी रह गये। मैं भी रह गया हूं तो चौधरी बंसी लाल जी क्या चीज है.....(विधन) सरदार प्रताप सिंह कौरो, जो एक जबरदस्त आदमी कहलाते थे, के लिये एक सुप्रीमकोर्ट का जज काफी साहिब हुआ था मगर चौधरी साहिब, आपके लिये तो एक सैशन जज भी काफी है। इसलिए आप इन चीजोसे परहेज करें। आप वकी होते हुए कानून को समझे। इनकी बातों में आप को नहीं आना चाहिए। आपकी टीम तो ज्यादा अनपढ़ों की है, इसलिए आपको ही सोचना है जिम्मेदारी ता आप ही पर है।

स्पीकर साहिब आपने हुक्म किया था कि मैं जल्दी करूं। मैं आपकी विसातित से सिरफ इतना ही कहूंगा कि इनको

मौका मिला है और सुनहरी मौका मिला है, भगवान की तरफ से, इन को चाहिये कि हरियाणा की तरक्की के लिए कोई काम करें।

मुख्य मंत्री: रेवैन्यू बढ़ाने के लिये भी कोई कंस्ट्रक्टिव सुजेशन दे। घटाने की बात तो आपने कर दी। चीप पापुलैरेटी लेने की बाजय कोई रेवैन्यू बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्टिव सुजेशन दे।

राव बीरेन्द्र सिंह: जो सरकार का फर्ज है वह जनता देखेगी कि वह पूरा करती है या नहीं। जो लीटर आफ दी आपोजीशन का फर्ज है वह भी जनता देखेगी कि मैं पूरा करता हूँ या नहीं। शुक्रिया (विघ्न)

मलिक मुख्तियार सिंह: जिस तरह सरकार ने अपनी पालिसीज बताई है उसी तरह से इन्होंने भी क्रीटिसाइज कर दिया है।

श्री मंगल सेन (रोहतक): स्पीकर साहिब, आज सदन में जो बहन ओम प्रभा जी ने 1968-69 का बजट पेश किया है उस पर विचार हो रहा है। बहन जी ने इस वर्ष 8.23 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया है और उन्होंने अपने भाषण कर हरियाणा की जनता निगाहे डाल कर बैठी थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि सरकार अवाम को राहत देने की कोई बात इसमें कहेगी। जगह जब उसने रेडियों पर सुना और अखबारों को इस बारे में पढ़ा तो उसे मायूसी हुई। हां सरकार ने यह जरूर किया है कि अब स्टेट में जुआ भी शुरू कर दिया है। मैं ओमप्रभा बहन जी का बड़ा

सम्मान करता हूँ। वह एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है और उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं। स्पीकर साहिब, पहले इस गांधीवादियों ले लोगों को शराब दी। इन्होंने टेकों को बेच कर पैसा भी लिया और लोगों को शराब भी दी। और अब जुआ भी शुरू करवा दिया है। इन्होंने स्टेट लाटरी की स्कीम शुरू करने का फैसला किया और इससे 50 लाख का घाटा कवर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि अगर वह यह स्कीम न भी चलाते, तब भी काम बन सकता था। स्पीकर साहिब, इस चीज का जनता पर बहुत बुरा इम्प्रेसन पड़ा है।

वैसे तो स्पीकर साहिब, हम बंसीलाल जी के बड़े ऋणी हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि आप उस वक्त की बार्डर पर किसी अच्छे काम पर लगे होंगे, जब हमने पिछले चुनाव के बाद मुख्य मंत्री पद पर बैठे हुए पंडित भगवत दयाल जी को अपदस्थ किया तो इन की शुभकामनाएं हमारे साथ थी। यही नहीं श्री दयाकृष्ण जी को परास्त करने में भी इन्होंने हमारा साथ दिया। यह पहले हाउस में हलफ लेने नहीं आए लेकिन जब वह अपदस्थ हो गए तो हाउस के अन्दर आ गए। (विघ्न) लेकिन अब जब मेने इनकी बतौर चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहिब के भाषण पर तकरीरों के जवाब में स्पीच सुनी तो मुझे लगा कि अब यह हमारे साथ नहीं है। यह जानकर हमें बड़ी मायूसी हुई। यह कहने लगे कि पुलिसका जो काम होता है वह काम पुलिस करेगी.....

मुख्य मंत्री: हां, अब पुलिस स्मग्लिंग नहीं होने दूंगी।

श्री मंगल सेन: मै, स्पीकर साहिब, चलेंज करता हूं कि अगर मै या मेरी पार्टी के किसी सदस्य ने कही स्मग्लिंग की हो और वह साबित हो जाए तो मै सदन से इस्तीफा दे दूंगा (आपोजीशन की तरफ से प्रशंसा)

मुख्य मंत्री: इनक्वायरी करा दूंगा।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, यह बंसीलाल जी मेज स्कैंडल के नाम पर भोली जनता को बहकाते है। मै ने कहा कि परमानेंट विजललैस बाडी कायम हो। अगर कही कोई इस तरह की बात होती है तो उसकी पड़ताल हो। और जो बात समने आए वह जनता के सामने पेश हो। यों बैठे बैठे स्पीपिंग रिमाक्स पास कर देना बहुत आयान बात है। लेकिन मै कहना चाहता हूं कि भूत वह जो सर चढ़ बोले। अच्छा हुआ ये बोल पड़े। जनाब स्पीकर साहिब हरियाणा राज्य के लोगों ने चुनाव के बाद कुछ आशा लगाई थी कि चुनाव के बाद कुछ विकास का कार्य टेक अप किया जाएगा, कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी लेकिन इन्होने आते ही ऐा कैओस खड़ा कर दिया है जिसकी हद नही। चंडीगढ में जिस धांधली के साथ ट्रांसफर हुई उसकी हिस्ट्री में कोई मिसाल नही मिलेगी। एक अफसर जनबा इनके लिहाज से रवैन्यू की अपील तो सुनेगा लेकिन उनका डजिगनेशन फाइनेंशल कमिश्नर नही होगा। कैसी अजीब बातें इन्होने आते ही करनी शुरू कर दी है? मेरी जमीर तो काम नही देती कि इनके बारे में सारी बातें कहूं और यह भी बतलाऊं कि इनके पूर्वज सरकार प्रपात सिंह कैरों जो बाते

किया करते थे वही इन्होंने करनी शुरू कर दी है। औ रवही रवैया इन्होंने अख्तियार किया है। इन्होंने ऐसे सेक्रेटरीज रखे हैं जो कभी पाकिस्तान गये थे और पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि ऐसे अफसरों को न भेजा करों जिनका चरित्र अपनी काबू में नहीं है.....

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जो अफसर यहां हाउस में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके क्या एक आनरेबल मैम्बर उसके बारे में ऐसी बातें कर सकता है?

Ch. Chand Ram: Sir, He is not naming anybody. If any officer is named then objection can be raised.

Mr. Speaker: The hon. Member should avoid that; otherwise it will lead to pinpricking.

Ch. Chand Ram: Sir, the Hon. Member is taking full responsibility for what he is saying. He exposing the hollowness of the officer.

Mr. Speaker: All the same we should avoid such references.

Ch. Chand Ram: Sir, I have every respect for your rulings and observations but let us consult the rules which govern the discussion in this House. The rules are that the administration and those who carry on the administration should be exposed.

Mr. Speaker: The ruling has been given and you should abide by that.

Ch. Chand Ram: All right, Sir.

श्री मंगल सेन: जनबा, मै आपकी रूलिंग की कदर करता हूं। मै इस विषय में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर यह मुझे मौका दे दें तो मै उस अफसर के बारे में इनडिटेल् बताना सकता हूं। आजके मौजूदा चीफ सैक्रेटरी से पूछ लिया जाये कि आया मेरी इन्फर्मेशन कुरैक्ट है या नही?

जनबा स्पीकर सहिब, सरकारी कर्मचारी ही ऐसे होते है, जो सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते है लेकिन उनके साथ इस सरकार ने क्या रवैया अपनाया हुआ है वह भी आपके सामने बयान किये देता हूं। पिछली फरवरी को 9-10 तारीख को हरियाणा राज्य के कर्मचारियों ने एक बात कही कि हम पंजाब से आए है और हमें बगैर हमारी मर्जी के यहा भेजना गया है जब कि पंजाब और हरियाणा का बटवारा हुआ लेकिन जब हम इधर आ गए तो फिर हमारे साथ भेदभाव का सलूक क्यों किया जा रहा है। अभी हम यहां चण्डीगढ़ में अपने पुराने साथियों के पास ही बैठे है, एक ही बिल्डिंग में काम करते है, एक ही जगह रहते है, एक जैसा महंगाई का असर हमारे ऊपर है लेकिन बंगल में बैठे हुए साथियों को पंजाब में तनखाहों के रेट सेंटर के हो गए और वह पहली मई 1967 से मिले मगर जब इनको पैसा मिला तो कही बार में और एक महीने पीछे यानी कि जून से और इसी तरह से जब फिर सेंटर के रेट पंजाब में परिटी पर लाए गए तो हरियाणा में भी सेंटर के महंगाई के रेट लागू हुए लेकिन उसमें काफी गैप

रहा। इस प्रकार के व्यवहार के लिये कर्मचारियों ने प्रोटैस्ट किया और उनके दिलों में काफी मायूसी हुई। इस तमीज को दूर कराने के लिये और अपने रूपये की मांग को पूरा कराने के लिये कर्मचारियों ने चहा पर 22 सैक्टर में 3 महीने लगातार तम्बू गाड़ कर भूख हड़ताल की मगर इनकी पापुलर गवर्नमेंट के आते ही, जनबा हमारे खुरशीद साहिब उनके पास आए और वायदा किया तुम भूख हड़ताल बन्द करो हम मेज पर बैठेगे और तुम्हारी मांगों पर हमदर्दना गौर करेंगे। लेकिन आज इस बजट को देखकर हरियाणा राज्य के 95 हजार इमप्लॉईज का दिल टूट गया और उनकी आशाएं मिट्टी में मिल गई। जनबा स्पीकर साहिब यह भली प्रकार अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी आदमी ने वायदा किया हो और फिर वायदा खिलाफी करें तो उसके प्रति नाराजगी पैदा होना बड़ा स्वाभाविक है। मैं बहन ओमप्रभा जी को कहना चाहता हूं कि वह भूल को ठीक कर ले। और जब बजट पर बोले तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि कर्मचारियों की मांग बिल्कुल जायज है, और यह सिद्धान्त रूप में सरकार को मान लेनी चाहिए।

इसके बाद मैं, स्पीकर साहिब, कहना चाहूंगा कि यह हमारे मुख्य मंत्री सहिब सोचते होंगे कि वही पवित्र आदमी है और वही नेक आदमी है और बाकी तो सभी अपवित्र आदमी है उनकी बाबत मैं बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में यह कहा था कि मेरे गुरु जी तो नन्दा जी है और नेता श्री

भगवत दयाल है। मैंने इस तर कहा कि कोई बात नही किसी का कोई भी गुरु और कोई भी नेता हो सकता है लेकिन मुझे मायूसी हुई उस वक्त जबकि इन्होंने अपनी सरकार बना कर वही काम करना शुरू कर दिया जिससे इनके गुरु को हमेशा नाकामयाबी होती रही (विघ्न)

मुख्य मंत्री: तुम्हें तो मंगल सेन जी अमर भर नाकामयाबी ही नसीब होगी।

श्री मंगल सेन: जनबा मुझे पता है कि यह अपनी कामयाबी के लिये बहुत पहले से नन्दा जी की मालिश करे रहे, खुशामद करते रहे.....

मुख्य मंत्री: जनबा मालिश करना और खुशामद करना यह अलफाज आनरेबल मैम्बर वापिस ले।

Mr. Speaker: I suggest that he should not use such expressions.

श्री मंगल सेन: अच्छा जनबा, मैं कहूंगा कि यह चाहे तो उनकी प्रशंसा करें, नाजायज प्रशंसा करें लेकिन इनके कारनामों को देखकर कर मुझ प्रताप सिंह कैरों के कारनामों की याद आ गई है कि जिस तरह से वह कहा करते थे कि हम यह कर देगे वह कर देंगे मगर इनक को पता होना चाहिये कि उनके कारनामों हमने नहीं चलले दिये.....

मुख्य मंत्री: मंगल सेन जी क्या बातें कर रहे हो? सबाको पता है उनके आगे तुम्हाने कारनामे दबे रहे कि आपने उने काम में रूकावट डाली।

श्री मंगल सेन: जनाब, अब यह भाषण देने लगे कि हम बातों में विश्वास नहीं करते हम तो ऐक्शन में विश्वास करते हैं। बंसीलाल जी, आप बोलने में जितने होशियार हैं। उतना शायद ही कोई हो.....आपने सैट्रल हाल में बैठ करके माइक में बोलना ही तो सीखा है। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि राज्य के अंदर अगर आप मुख्य मंत्री बने हैं, ठीक है आप एक पार्टी क लीडर हैं, लेकिन आप पर भी कायदा कानून लागू होता है। यह नहीं कि मुख्य मंत्री बनते ही अपने गांव के सरपंच को सस्पेंड कर दिया और रणिया के अंदर वहां के सरपंच को गुण्डों से पिटवाय जाए, और अगर एस०एच०ओ० के खिलाफ शिकायत आए तो वह फरमाते हैं कि आदमी तो बड़ा शरीफ है। इसका क्या यह मतलब है। कि अफसर अगर शरीफ होते वह गैरकानूनी काम करता रहे। स्पीकर साहिब, इन्होंने हम को धमकाने की बातें कही थी लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमने इनसे कई गुणा ज्यादा खतरनाक आदमी देखे हुए हैं जिन्होंने हम को बाजारों में पिटवाया। जब उस किस्म के आदमी चले गये और उनका वह हशर हुआ जो आप सब को पता है तो फिर श्री बंसी लाल जी आप तो क्या चीज है, आपको तो एक मामूली झोंका ही उड़ा ले जाएगा। स्पीकर साहिब, जो भी उठता है कहने लगता है कि डीफैक्शनिस्ट है मगर अपने

गिरेबान में मुह डाल कर नहीं देखते। यह तो ट्रैयरी बैचों पर बैठे मैम्बर भिवानी से सफल हो कर आए है वह चौक में खड़े हो कर कहा करते थे कि कांग्रेस शोषणकर्ताओं की संस्था है और जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में दगा करके कांग्रेस का टिकट ले लिया तो उसी मुंह से कहने लग गए है कि कांग्रेस समाजवादी है इस किस्म के गोल पेदे के लोग किस मुंह से बात कर सते है। अगर इस बार आपका सिप्पा लग गया तो इतना उछलों न, जरा सब्र और चैन से बैठो।

महंत गंगा सांगर: स्पीकर साहिब, मै प्रार्थना करूंगा कि अगर आनरेबल मैम्बर कुछ बजट पर बोलें तो बेहतर रहेगा क्योंकि यह डिस्कशन तो कई दिनों से चला ही आ रहा है।

Mr. Speaker: I would expect the hon. Members to confine themselves to the discussion on the Budget. There may be a little variation here and there, but, by and large, they should try to be relevant to the Budget.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहिब, शायद मेरे लायक दोस्त डिफैक्शन का अर्थ नहीं समझते। मै इन की वाकफ़ियत के लिये अर्ज करता हूं कि अगर किसी पार्टी के टिकट पर इलैक्ट होने के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे डिफैक्शन कहा जाता है।

श्री मंगलसेन: श्री बनारसी दास जी मै शिक्षा में आपस कम नहीं हूं जो मुझे समझ नहीं आ सकती। आप शोषित

वर्ग के नेता कभी थे। आप आज इनके साथ मिल गये हैं। हम आप के दिमाग और नीयत को भी भली भांति जानते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहिब, जींद स्टेट के अंदर प्रजा मण्डल को सबसे पहले शुरू करने वाली श्री बनारसी दास जी ही तो थे।

Mr. Speaker: No interruptions, please. On the one hand some hon. Members suggest that the Members should not be irrelevant, whereas on the other, they rise of Points of Orders, which are not strictly relevant. This should be avoided.

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहिब, जुमा जुमा सात दिन तो हुए हैं यहां मैम्बर बन कर बैठे हो, यह हमें क्या समझायेगे, मुझे तो 15 साल हो गये हैं लगातार मैम्बर बनता चला आ रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर भगवान ने इन को गद्दी दी है तो इन्हें जरा संभल के चलना चाहिए। असल में आदमी गुरबत के दिन तो निकाल लेता है लेकिन जब उसे पा सधन और दौलत आ जाए तो वह दीवारों को टकरें मारता है फैंक्ट्स कहने लगे तो वह उल्टा अकड़ने लगे। स्पीकर साहिब, मुझे पता है कि श्री भगवत दयाल जी मुझे कहा करते थे कि मन्दिरों में तुझे भगवान मारेगा और बाहर हम मारेगे, वह आज राज्य सभी में जा रहे हैं।

Ch. Ram Parkash: On a Point of Order, Sir,.....

(Interruptions)

Mr. Speaker: No interruption please. I want to make certain observations. As I said earlier, irrelevant Points of Orders and interruptions should be avoided, as they cause irrelevant speeches and provoke other members unnecessarily, I would, there suggest that there should be less interruptions. They may be here and there, but not in the manner as we are having them during the last about half an hour.

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहिब, मैं बड़े अदब से आप के जरिये कह रहा था कि गद्दी पर बैठ कर टौलरेंस होनी चाहिये। डैमोक्रेसी में तो आपोजीशन होती ही है। इस लोकतंत्र में सरकार की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कि अपोजशीन को खत्म कर दे और आज तक जो तानाशाही करने वाले पैदा हुए वे खत्म होते रहे और रहेगे, वे रह नहीं सकते। जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पुलिटीकल विक्टेमाइजेशन करने के लिये करनाल की म्यूनिसपल कमेटी को तोड़ दिया और यह मेरे अजीज मंत्री महोदय वहां पर कहने लगे कि करनाल के लोगों ! सुनों चंद दिनों में करनाल की कमेटी की खबर सामने आने वाली है। राव साहब भूल गये उस बात को, जो उन्होंने यह नहीं बताया कि नारनौल की कमेटी के चुनाव की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और 27 तारीख को जून के महीने नौमिनेशन पेपर फाइल होने थे, इनकां 2 जुलाई को हुक्म जारी होता है कि वहां का चुनाव मुल्तवी किया जाता है। जो लोग अपने नौमिनेषन पेपर फाइल करके जनता से वोट मांगते फिर रहे थे उनके साथ यह क्या माज नहीं है? मैं समझता हूँ कि यह जमहूरियत के कफन में कील मारने की बात की गई हैं मैं चीफ

मिनिस्टर साहिब से कहता हूँ मुझे कौन हिलाने वाला है मैंने तो कैरों साहिब के दिनदेखे। सन् 1957 में जब इनमें से कई मैम्बर उनके पावों पर हाथ लगाया करते थे।

Chief Minister: On a Point of Order, Sir, The hon. Member always speaks irrelevant. There is not occasion at all the refer to late Sardar partap sigh Kairon, who is no more in the world and is dead since long. He should be advised to speak on the Budget.

Mr. Speaker: Let us confine ourselves to Budget, please.

श्री मंगल सेन: रैफरेंस तो आएगा ही, स्पीकर साहिब, मैं इनको कह रहा हूँ कि वह अनडैमोक्रेटिक न हो। अनडैमोक्रेटिक तो हुए, उनका जैसा हाल हुआ, उवह बता रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो जगह जगह पर सिक्योरिटी के नाम पर अपने मुखलफो को 107-151 में अंदर दे दिया और अपोजीशन के मैम्बरों के खिलाफ भी इसी तरह की एप्लीकेशन ले कर कार्यवाही करना चाहते हैं। कम से कम मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से ऐसी आशानही करता। श्री बंशीलाल जी, जो कभी नन्दा जी की प्रशंसा में हमें मुग्धर कर दिया करते थे तो उनकी तरफ से अगर आज ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाए तो कि असूल के विरुद्ध हो तो इससे बड़ा बेअसूली का सबूत और क्या हो सकता है? मैं आप को बताना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री के चक्कर में आप ने रहना, यह न सोचना कि आपके पासपुलिस है, जेले है, झूठे गवाह है, हमने

बहुत सी बड़ी बड़ी बातें देखी हुई हैं हमने जिन्दगी में बहुत बातें देखी हैं और सच पूछे तो आप कभी जेल नहीं गए। जिस पार्टी की हकूमत है इसके नेताओं ने जरूर जेल यात्रा की हुई है कुरबानियों की है, मारे खाई है, ओर चक्की पीसी है। और उसके कारण ही जानता के दिल में सौ किस्म की बातें करने बाद भी श्रद्धा है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आगे आप की मर्जी है। माने या न मानें। बेशक धांधली चलाओं जनता खुद आप से निपट लेगी।

तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि रोहतक में एक मैडीकल कालेज है और सारे हरियाणा प्रदेश में यही एक कालेज है लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि उसका बंदोबस्त निहायत ही खराब हैं पिछली दफा वहां के खिलाफ शिकायत आई थी और उसकी जांच के लिये एक कमेटी बैठी थी और उसने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट भी दी थी लेकिन उस रिपोर्ट का क्या बना उसका कुछ पता नहीं। वहां जो पचास साठ साल से सिविल हस्पताल चल रहा था उसके बार में वहा के प्रिंसिपल साहिब कहने लगे कि इसे मैडीकल कालेज में मर्ज होने दो नहीं तो आल इंडिया मैडीकल बोर्ड डीएफिलिएट कर देगा। हम लोगों की खूब चढ़ कर सेवा कर करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचों कि “अब सईया भये कातवाल डर काहे का” और फोर्थ फिफथ ईयर के स्टैंडैट्स का जो अनट्रेंड होत है हाउस सर्जन बनाना बेहतर समझ लिया। कोई एमरजेंसी का केस आ जाए

चाहे औक्सीजन देनी हो यही स्टूडेंट्स डाक्टरी करते हैं। हालत यह है कि लोगों का मैडिकल कालेज का नाम सुनते ही दम टुट जाता है। और मरीजों की रूह कांपती है कि अगर एक दफा वहा चले गए तो जिन्दा वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता (हंसी)। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह उस इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामन रखे और जो लोग वहा पार्टीबाजी करते हैं उन्हें उससे हटाना चाहिये और और अगर वह नहीं हटते तो उन्हें रिटायर कर दो ताकि कम से कम वहां की जनता का तो उनसे पीछा छूटे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहन जी ने जो बजट हाउस के साने पेश किया है वह बड़ा कनफियूजिंग है.....

वित्त मंत्री: क्या कनफियूजन है वह बता दे?

श्री मंगल सेन: सारी रात राम की कहानी करते रहे और पीछे से यह बात निकली अगर अब भी आपको पता नहीं लगा तो पहले जो आप के बारमें मैं अच्छी राय थी वह बदलनी पड़ेगी। (हंसी) आप यह बात हाउस को बताएं कि आठ करोड़ का घाटा आप कैसे पूरा करने वाली है? क्या हाउस से फ़ारग होते ही गवर्नर साहिब से आर्डर जारी कराकर टैक्स लगाने का इरादा है। कई भाई कहते हैं कि हिन्दूस्तान की जनता ने अपोजीशन पार्टियों को राज करने का मौका दिया और हरियाणा में भी दिया गया लेकिन वे नहीं कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि जनता ने तो अभी मौका दिया लेकिन आप के साथी ही आपकी ज्यादातियों से

तंग आकर हमारे साथ शामिल होने के लिये भागे और यह ठीक है कि जैसी गवर्नमेंट हम चाहते थे वह नहीं बना पाए। ओर बातों के अलावा इसकस एक कारण यह भी था कि सैट्रल गवर्नमेंट हमें फल करने के लिए सिरधड़ की बाजी लागाने में लगी रही। अब कह रहे कि चीनी का कोटा बढ़ा देंगे लेकिन जब हम कहते थे तो कहा जात था कि नहीं बढ़ा सकते। अब आठ करोड़ रूपये का खिसारा अनकवर्ड छोड़ा गया और उनके सिर पर जू नहीं रेगी लेकिन उस वाक यहां पालियामेंट में फाइनेस मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि पापुलर सरकार आएगी तो इन कमियों को पूरा करने के रास्ते सोचेगी। उस वक्त के हमारे फाइनेस मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहिब ने काफी गवर्नमेंट आफ इंडिया पर दवाब डाला कि आपने जो भाखड़ा को पैसा नहीं है वह किशतों में ले लो और हमारी सहायता कर दो तो उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह चाहते थे कि इनका फाइनेसली नमदा कस दो ताकि यह जनता में अनपापुलर हो जाएं और फेल हो जाए। लेकिन आज वही नेतागण उसी बात को कहे तो इस बजट में शामिल हो तो यह नीति देखकर कर अफसोस होता है कि.....

श्री अध्यक्ष: आपने काफी टाइम ले लिया है, और कितना समय लेगे? अब आप वाईड अप करे।

श्री मंगल सेन: मैं आपका हुक्म मानता हूँ और अभी वाईड अप कर देता हूँ। तो मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे प्रदेश की हालत है जो कि आपने बजट में

खिसारा दिखा कर बातई है उसे देखते हुए अपने अखराजात में कमी कद दी और कुड ऐसे महकमे जो सफेद हाथियों की तरह आपने पाल रेख है उन्हे तोड़ दो। हमने कुछ महकमे तोड़ने चाहे लेकिन स्टेट रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट बीच में आ गया। अध्यक्ष महोदय, आप भी जातने है और आप जब छुट्टी आते होंगे तो आपने देखा होगा कि यह जो बी०डी०ओज० का महकमा है इससे ग्रामीण जवीन पर कार्ई फर्क नही पड़ा और यह तो सिर्फ जनता के ऊपर बोझ हैं जब सारा पंजाब इकट्ठा था तो उस वक्त सारे कांग्रेस ओर अपोजीशन के मैम्बरों ने एक स्वर में कहा था कि इस सफेद हाथी को तोड़ दो लेकिन गवर्नमैण्ट आफ इंडिया अड़ गई। अब मै फिर सलाह दूंगा कि यह महकमा तोड़ दो। * * * इसका कोई लाभ नही है इसे तोड़ रो और भारत सेवक समाज को जो ग्रांट दे रखी है.....

वित्त मंत्री: आपने बजट को देखा है या नही। यहां कहा है यह ग्रांट, जिसका आप जिक्र कर रहे है?

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहिब, * * * *
इन्हे यह शब्द वापिस लेने चाहिये।

Mr. Speaker: I think this expresson should be expunged.

श्री मंगल सेन: मै समझता हूं कि यह खामखाह का बोझ है जो जनता के ऊपर लाद रखा है इन्हें तोड़ दो। जो फजूल के महकमे खोल रखे हैइन्हें खत्म करों जिससे खर्च में

कमी हो और आप लोग राज्य की आय के मुताबिक अपने पावं फ़ैलाओ। अब मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप धरती पर पावं रख कर चलने की कोशिश करें। हम भी इस हाउस के मैम्बर हैं। हो सकता है कि आप 700 वोट से जीत कर आये हैं और मैं 66 वोट से जीत का आया हूँ ओर इस बात के बावजूद आ गया हूँ कि सारी सैट्रल लीडरशिप मेरी जान की रोती रही और मुझ ही उस ने खासतौर पर टारगेट बनाए रखा था। जनता ने अब इनको मौका दिया है कि यह उनकी सेवा करें लेकिन अगर यह इस मौका से चूक जायेंगे तो फिर इन्हें मौका नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश की उन्नति के लिये खर्च को कम करें ओर जो पिछड़े हुए लोग हैं, बुरी तरह इफ़ैक्टिव हैं, उनकी सुध ले।

मुख्य मंत्री: इसमें आपकी मदद चाहिए।

श्री मंगल सेन: अगर आप हमसे सहयोग मांगेंगे तो हम जरूर देंगे अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे और अपोजीशन का रोल अदा करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

**Expunged as ordered by the Chair*

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहिब, वित्त मंत्री महोदय ने जो हरियाणा प्रांत का बजट पेश किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करती हूँ क्योंकि उन्होंने स्टेट की वेलफेयर के

लिए एक अच्छा बजट पेश किया है। इसके लिए वित्त मंत्री साहिबा बधाई की पात्र है अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, कुछ खास चीजों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं) सब से पहले मैं डिप्टी स्पीकर महोदया, आप की मारफत कृषि और लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं मुझे खुशी है कि सरकार ने लघु सिंचाई योजना के लिए 104 लाख रूपए की रकम रखी है और 4,100 नलकूप और 600 पम्पिंग सैट लगाने का प्रस्ताव किया गया है। भू-बन्धक बैंक से लघु सिंचाई कर्जों के लिए 52 लाख रूपए की रकम जुटाई है। यह प्रोवीजन जो बजट में रखा गया है इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदया का बधाई देती हूं क्योंकि हरियाणा प्रांत की सारी इकौनोमी खेती पर ही निर्भर है इस खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। हरियाणा में जब तक सूखे खेतों और बंजर जमीन को पानी नहीं दिया जाता तब तक हरियाणा हरा भरा नहीं हो सकता। इसके लिए जमुना में एक बांध बनाया जाना चाहिए क्योंकि जमुना का पानी ही हरियाणा प्रान्त को मिल सकता है।

इसके अलावा सघन कृषि की उन्नति के लिए हवाई जहाज से दवाई छिड़कवाने के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, उसे लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद करती हूं। मैं अभी अपने इलाके में होकर आई हूं। वहां पर कातरा बहुत मात्रा में पैदा हो गया है, उसे मारने का इन्तजाम सरकार को करना चाहिए। यक

काटरा एक छोटा और मुमलायम कीड़ा होता है जो बाजरे को खत्म कर देता है। इस कीड़े को कृषि मंत्री साहिब मारने का प्रयत्न करे। ताकि फसल का नुकसान न हो।

इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट में विलेज इकानोमी के लिए कोई जिक्र ही नहीं है। हरियाणा प्रांत में ज्यादा बड़े बड़े शहर नहीं है, यारी की सारी पापुलेशन गांवों में बसती है। गांवों में जो टैक्निशियन्ज है उनको कोई काम ही नहीं मिलता। गांवों में जो बढ़ई है वे बेकार बैठे रहते है। अगर किसी ट्रैक्टर का कोई पुर्जा टूट जाता है तो उस पुर्जे को लेकर या ता उन्हे दिल्ली जाना पड़ता है या रोहतक। वैसे जनरली वह पूजा दिल्ली में ही मिलता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है की गांवों में छोटी छोटी वर्कशाप होनी चाहिए ताकि पुर्जे मिल सके। अगर एक चलती फिरती वर्कशाप हो ता उससे भी किसानों को राहत मिल सकती है।

अब मैं औरतों की तकलीफों के बारे में अर्ज करता चाहती हूँ। औरतों को विशेषकर बरसात के दिनों में चूल्हा जलाते हुए अधिक तकलीफ होती है। चूल्हा फूंकते फूंकते उन की आंख चालीस साल में ही खराब हो जाती है। गांवों के मुकाबिले में यह शहरों में बिजली के चूल्हे तथा गैस के चूल्हे आ गये है लेकिन गांवों में कोई इन्तजाम नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस तरह की कोई योजना होनी चाहिए जिससे औरतों को राहत मिले।

इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, गांवों के नौजवान शहरों की तरफ ज्यादा भागते हैं क्योंकि गांवों में उनके करने के लिए कोई धन्धा नहीं होता है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई इन्जाम नहीं है इस तरह जो भी गांव को इंटैलीजेंसिया है वह शहरों की तरफ भाग रहा है इसके अतिरिक्त गांवों में सैन्टिशन की कोई योजना नहीं है बच्चों के खेलने तथा मनोरंजन के लिए कुछ नहीं है। जितना रूपया चण्डीगढ़ और दूसरे बड़े बड़े शहरों में खर्च होता है उसका चौथा हिस्सा भी गांवों पर खर्च नहीं होता है इसलिए गांव के लोगों को स्टैंडर्ड ऊंचा रखने के लिए कोई न कोई प्लैन अवश्य होनी चाहिए। गांवों के जमीन एक ही साधन है जिससे लोग गुजारा करते हैं जमीन का एक फायदा है कि जितने टुकड़ें होंगे पैदावार उतीन ही कम होगी। कई जमींदार ऐसे हैं जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन है। जमीन कोई रबड़ तो है नहीं जो बढ़ाये से बढ़ जायेगी, इसलिए जिन गांवों में एकस्ट्रा पापुलेशन है वहां लघु उद्योग खोले जाये। जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं हमें तो मशीनों से ज्यादा आदमी के लिए काम चाहिए।

अब मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहती हूँ। शिक्षा में आठवी क्लास के लिए फ्री एजुकेशन देने का जो काम हमारी सरकार ने दिकया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। शहरों में जो धनी मानी लोग हैं, उनके बच्चों की फीस अगर माफ नहीं होती तो वह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनके

पास आमदनी के ज्यादा साधन होते हैं। धनी व्यक्तियों के बच्चों के लिए शहरों में पब्लिक स्कूल हैं जो कि देहाती बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जिस ढंग से गांवों के स्कूल हैं और जिस ढंग से उनको शिक्षा दी जाती है उस से शहरों में पाये जाने वाले पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर जितना खर्च होता है उतना प्राइमरी स्कूल का बजट होता है जिसे मैं सौ से लेकर डेढ़ सौ तक लड़े पढ़ते हैं। इतनी डिस्पेन्डिचर है देहाती और शहरी स्कूलों में और फिर सरकार जो इक्वैलिटी का नारा लगाती है यह बस ढोंग ही है। इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहूंगी कि देहातों में भी कोई तरह का बढ़िया स्कूल खोला जाना चाहिए जिसमें लियाकत के हिसाब से लड़के और लड़कियों को आम स्कूलों में आठवीं की परीक्षा पास करने के पश्चात् दाखिला किया जाए ताकि अच्छे अच्छे लड़के और लड़कियां आगे आ सकें और हमारा राष्ट्र कुछ बन सकें। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकते हैं। आज आप देखती हैं कि सब जगह चर्चा आती है कि पब्लिक लाईफ पौल्यूट हो गई है, सरकारी मशीनरी कुरप्ट है, आदि आदि। मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, शिक्षा की तरफ ठीक तरह से ध्यान न दिया जाना ही इन सब बातों का कारण समझती हूँ। पहले जैसा आप जानती हैं बाकी शिक्षा के साथ साथ धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, परन्तु आज वह बात नहीं। धर्म की शिक्षा के कारण लोगों के मान के अन्दर कोई बुरा काम करने का डर रहता था परन्तु आज ऐसी

कोई बात नहीं है। इसलिए सरकार से मेरी यह भी प्रार्थना है कि स्कूलों में "एथिक्स" के नाम से कोई विषय जरूर होना चाहिए।

उपाध्यक्षा: श्रीमती चन्द्रावती जी, बूढ़ों को पेन्शन दिए जाने क बारे में आप क्या सोचती है।

श्री चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो इस विषय पर बोलने का मेरा विचार नहीं था परन्तु आप ने क्योंकि मेचेर विचार जाने चाहे है इसलिएकुछ अर्ज किए देती हूं। बुढ़ापे में पैन्शन दिए जाने की बत बड़ी अच्छी बात है बशर्ते कि इसे ठीक ढंग से दिया जाए। अभी तक तो ऐसा ही देखने में आया है की यह उन्हें लोकों को मिलती है जिनकी कोई सिफारिश हो जाती है क्योंकि आपके इलाके में तो अभी तक किसी को नहीं मिली हालांकि वहां काफी डिजविन्ग हैन्डज है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि यह पैन्शन देने हो, तो एक खास उमर के बाद बिना किस धर्म, जातपात और सिफारिश का ध्यान रखते हुए सबों दी जानी चाहिए। यदि ऐसा हो जाये तब तो बड़ी अच्छी बात है वरना इसका कोई फायदा नहीं।

उपाध्यक्षा: वैसे तो आप सोचती है कि मिली चाहिए?

श्रीमती चन्द्रावती: जरूर मिलनी चाहिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर आप ऐसा सोचती है (हंसी)

एक सदस्य: उपाध्यक्षा महोदया, अभी इनके बुढ़ापे के दिन दूर है इसलिये यहा हां नहीं कर रही है।

उपाध्यक्षा: इनके कोई रिश्तेदार तो होंगे, जिनके पास न तो आमदनी होगी, न आदमी होंगे और न शरीर की काम करता होगा।

श्रीमती चन्द्रावती: इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, 15,000 नलकूपों को बिजली देने वाली योजना के लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ और इस बधाई के साथ साथ मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि, आज के विज्ञान के युग में जब कि लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बिजली एक मुख्य आवश्यकता की वस्तु बन गई है, अन्य आवश्यकताओं के लिए भी से काफी मात्रा में लोगों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा सरकार को यह भी सुझाव है कि बिजली फ्लैट रेट पर दी जानी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो बिजली की चोरी कम होगी दूसरे हर क्षेत्र में पैदावार बढ़ेगी क्योंकि ऐसा होने से हरेक कारखानेदार और किसान बिजली खर्च करना चाहेगा और परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ने की गुंजायश रहेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी मारफत किसानों की एक ओर दिक्कत सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूँ उनके उत्पादन के खरीद के ढंग में सरकार के ध्यान देने के बावजूद भी कुछ सुधार करने की गुंजायश है। आज भी उनको सब चीजों को बोली दे कर खरीदा जाता है जब कि जूता बनाने वाली अपने जूते को अपनी मर्जी की कीमत लेना है, एक कपड़ा बेचने वाला कपड़ा अपने भाव से बेचता है। इसलिए कम से कम यह बोली

वाली बात जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। और जो उसने भाव रखा हो या सरकार की ओर से निर्धारित किया गया हो उसी के ऊपर किसान की चीजों को खरीदा जाना चाहिए। (तालियां) अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझती हूँ कि किसान और देश के प्रति न्याय की बात नहीं है अगर किसान की चीज कम भाव पर बिकती है तो उसको उत्साह नहीं मिलता और वह उत्पादन बढ़ाने की बजाय उत्पादन कम देता है।

एक बात जो बजट में रह गई उसकी और भी डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत वित्त मंत्री साहिबा का ध्यान दिलाना चाहूंगी। वह बात है वेयर हाउसिज की। वेयर हाउसिज किसानों के लिए बड़े उपयोगी है क्योंकि मन्दे के समय या मार्केट में लागत न होने की वजह से अनाज का खराब होने से बचाने के लिए और समय आने पर ठीक भाव पर बेचने के लिए इनमें वे अपना अनाज रख सकते हैं इसलिए वित्त मंत्री महोदया से मेरा निवेदन है कि या तो डिमांड द्वारा पैसा लेकर और यदि ऐसा नहीं हो सकते अगले बजट में पैसा रखकर राज्य में वेयर हाउसिज का इन्तजाम जरूर होना चाहिए।

मैं आप का, डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज्यादा समय ने लेती हुई एक दो बातें अपने हल्के के बार में भी कहना चाहती हूँ। मुझे खुशी है है हब की बार पीने के पानी की सप्लाई के लिए 80 लाख रूपए की अतिरिक्त रकम रखी गई। लेकिन मैं आप के द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यह पैसा पहले

उन इलाकों में खर्च किया जाए जाहां पीने के पानी की बड़ी दिक्कत हो। मेरे हल्के में सिवानी नामक जगह में आज के युग में इस वक्त भी ऊंटों पर लाद कर घड़ो से सात सात मील की दूरी से पानी लाया जाता है। अगर एक घड़ा भी लाते लाते टूट जाये तो एक तो घड़ा जाता है, दूसरे उसकी मेहनत बेकार जाती ओर तसीरे व्यक्ति को पानी के बिना बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुछ देर पहले वहां के लिए एक स्कीम भी बनी थी, कुछ सामान्य भी वहां पहुंचा था परन्तु काम शुरू न होने की वजह से वहा लाखों रूपए का सामान खराब हो रहा हैं इलैक्शन के दिनों मे घूमते समय मैने देखा कि कोई नालिया कही पड़ी हेई थी तो कोई कही पड़ी हुई थी। कुछ घोड़ों के पैरों के नीचे आकर टूटी पड़ी हुई थी, कई जगह बचचे उनसे खेल रहे थे। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे इलाके की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए चाहे वह शिवानी का इलाका, या तोशम का हो या कोई और हो।

इसके इलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, कस्टोडियन लैन्ड के मसल को मै बहुत अहम मसाला समझती हूं आजादी मिलने के 20साल बाद भी इस लैन्ड की सप्लाई ठीक ढंग से नही हो रही हैं दो दो सौ साल से जो मुजारे इस लैण्ड पर कब्जा किए हुए थे उनसे इसे छुडज़कर नीनाम किया जा रहा है। कल ही मै कुछेक जगह जाकर आई हूं अब्बदूखां की ढानी एक ऐसा गांव है जिसमें एक भी स्वर्ण नही है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोकल

हरिजनों को जमीन ने देकर चहां लगे हुए यू०पी०, मध्यप्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अफसरों को दे दी जाती हैं बेचारे हरिजन तो समझते थे कि यह जमीन उनकी मुफ्त मिल जाएगी और यदि मुफ्त नहीं तो तीन चार सौ रूपए एकड़ तक मिल जाएगी परन्तु अढ़ाई हजार और चार हजार रूपए प्रति एकड़ की बोली पर मिलते देखकर उनकी आशाओं पर पानी फिर गया हैं मौजूदा सरकार का, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई दोष नहीं है। ये बातें तो इसे धरोहर के रूप में मिली है और मुझ आशा है कि वह इनकी ओर ध्यान देगी। इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सरकार से यह भी कहना चाहती हूं कि लोगों को न सिर्फ जमीनों से हटाया गया है बल्कि उने रिकार्ड को भी टैम्पर विद किया गया हैं कभी गिरदावरी एक भाई के नाम कर दी गई ओर कभी गिरदावरी दूसरे भाई के नाम कर दी गई। पटवारी अपनी मन मर्जी करता रहत हैं पटवारियों के बारे में यह शिकायत तो बड़े पहले स चलती आई इसलिए तो उर्दू में कहा जाता है कि ऊपर तो अल्लाह ताला है और नीचे पटवारी। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए।

उपाध्यक्षा: अब आप अपनी स्पीच जल्दी खत्म करें।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये शब्द कह कर कि इस कस्टोडियन लैनड का फ़ैसला होना चाहिए, मैं बजट की तार्ईद करती हुई अपना स्थान लेती हूं।

श्रीमती प्रसनी देवी (इन्द्री): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस के सामने जो बजट पेश किया गया है वह देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं फाईनेन्स मिनिस्टर जी को इस बात के लिए बाधाई देती हूँ कि स्कूलों के अन्दर फीस माफ करने को जो कदम सरकार की ओर से उठाया गया है वह बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हरियाणो के गरीब मजदूर ओर गरीब किसान, को यह महसूस हुआ है कि गरीबो की भी सुनने वाली कोई सरकार आयी है। फीस लगने के बाद मो बहुत से लोगों ने जैसा कि मैं अपने इलाके में देखती हूँ ओर जहां बहुत ज्यादा गरीब लोग है, अपने बच्चों को स्कूल में भोजना ही बन्द कर दिया था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और सरकार इस बात के लिए बाधाई की पात्र है।

उसके साथ ही मुझे एक बात और महसूस हो रही है कि किसानों के लिए जितना ध्यान रखा जाना चाहिए था उतना नहीं रखा गया। पिछली सरकार ने जो कि अपने को किसानों की सरकार कहती थी, उसने तो बिल्कुल ही ध्यान रखा था। मगर आज जब हमारी सरकार आई तो वही लोग कहने लगे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है ओर किसान को पूरी मेहनत नहीं देते। पता नहीं डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब किस मुंह से ऐसी बातें करते है। खैर, हमारी सरकार तो लोगों की भलाई की बातें हर तरफ से सुनने की तैयार रहती है लेकिन इस बार मुझे भी यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ है कि किसानों की मण्डियों में बड़ी

दुर्गति हुई है। उनका अनाज कई कई दिन तक वहां पड़ा रहा। यह ठीक है कि सरकार ने अच्छा इन्तजाम करने की बड़ी कोशिश की और हेराफेरी करने वाले कुछ अफसरों को सस्पैन्ड भी किया। लेकिन आज किसानों को इसके बावजूद भी पूरी कीमत नहीं मिल रही है। अगर हम पूरा हिसाब किताब लगा रक देखें तो किसान को आज बिल्कुल बचत नहीं होती है। वह घाटे में जाता है उसकी पैदा की हुई चीजों को तो सस्ते दामों में खरीद लिया। जाता परन्तु उसकी जरूरत की चीजें जैसे खाद, औजार और बीच आदि उसे मंहगे दामों पर मिलते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसानों को पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर उसका उत्पादन ठीक कीमत पर खरीदा जाए ओर खाद वगैरह की कीमत उससे ठीक ली जाए, ता जिस तरीके से इस साल उपज हुई है इसी तरह से, इसी हिसाब से आगे भी होती रहेगी।

दूसरी बात किसानों के विषय में मैं ट्रैक्टरों की करना चाहती हूं। आज बहुत से लोग दूसरी स्टेटों से ट्रैक्टर लाते हैं। और उन पर रंग रोगन करके ब्लैक में हमारे यहा जाते हैं यह बुरी बात है क्योंकि एक तो किसान को पैसे बहुत देने पड़ते हैं और दूसरे चीज अच्छी नहीं मिलती। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उसे कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सस्ते नहीं तो ठीक कीमत पर ट्रैक्टर मिले सके चाहे गवर्नमेंट सेंटरल गवर्नमेंट से लेकर लोगों को ट्रैक्टर दें या किसी ओर जरिए से दे परन्तु

दिए जरूर जाने चाहिए ताकि किसान अनाज की पैदावार बढ़ाने में समर्थ हो सके और आज जो मुसीबतें हमें सहन करनी पड़ती है उनसे हम बच सकें।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ट्यूबवैलों के बारे में जिक्र करना चाहूंगी। कुछ इलाकों में जैसा आप जानती है सरकारी ट्यूबवैलों से पानी लेकर सिंचाई की जाती है। पहले सरकारी ट्यूबवैल आठ पैसे यूनिट बिजली के हिसाब से पानी का खर्च लेते थे लेकिन आज पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए 25 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली का खर्चा लिया जाता है जो कि नहरों के पानी से पांच गुना ज्यादा पड़ता है नहरों से सिंचाई का रेट तो पहले और भी कम था मगर जबसे बिजली वाले ने अपना रेट बढ़ाया तो इन्होंने भी बढ़ा दिया इससे किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि यह बिजली के रेट को कम करें। बिजली के घाटे को पूरा करने के और बिजली की चोरी होती है आपने बड़े बड़े कारखानेदारों को कनेक्शन किये हुए है। सरकार को चाहिए कि उनके रेट बढ़ाए जाये। किसान को तो उसकी मेहनत और मजदूरी को भी पेरा पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए वैसे तो बिजली आदि के रेट बढ़ने नहीं चाहिए परन्तु यदि बढ़े भी जये तो बिजली के रेट नहरों के रेटों से दुगने हो जाये, ढाई गुने हो जाये मगर पांच गुने हो जाये तो वह अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि जहां इस तरह के ट्यूबवैल है वहां पिछली सरकार ने जो

रेट बड़ा दिये थे उनकों कम करने की कोशिश की जाये वरना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अगर एक किसान को अपने खेत में चार पानी देने हों तो वह दो में ही काम चलाने की कोशिश करेगा। इससे उत्पादन में कोई फर्क आएगा जो कि न ता किसान को फायदे की बात आगे और न हरियाणा के हित की बात होगी। हमारे देश की इकौनोमी भूमि वाला पर ही तो निर्भर करती है इसलिए इन लोगों को सब सहूलियतें मिलती चाहिए।

अब डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं स्कूलों के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि पिछली सरकार ने काफी ज्यादा तादाद में स्कूल बन दिये थे। जो पांचसालों में स्कूल अपग्रेड होने थे वह उन्होंने पांच सात महीने में ही कर दिये थे पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय से मैंने एक हैडमास्टर को कहते सुना था कि आपने यह क्या किया है कि एक एक मील पर दुकाने सी खोल दी हैं उन्होंने स्कूलों का नाम दुकानों में लिया। लेकिन मैं अपने इलाके का जिक्र करना चाहती हूँ। वहाँ पर 70, 70 मील के एरिया में आपको दो हाई स्कूल नजर आयेगे। वहाँ पर मिडल स्कूलों को भी यही हाल है। मेरा इलाका ऐसा है जाह पर तीन नाले हैं, तीन ड्रेन बड़ी बड़ी हैं, और लिंक ड्रेन्ज बहुत है उन पर पुल नहीं है। जहाँ पर 15 मील के अन्दर मिडल स्कूल भी नह हो, वहाँ हाई स्कूलों का तो कहना ही क्या? तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहाँ ऐसी हालत हो वहाँ के बच्चे क्या तरक्की करेंगे ओर क्या आगे बढ़ेंगे।

यही हमारे यहां सड़कों का हाल है पचास पचास मील इलाके में चले जाइये आपको कोई सड़क नहीं मिलगी। सरकार क्यों नहीं इस इलाके की ओर ध्यान दे रही है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे तो यह हल्का डेढ दो साल से मिला है लेकिन मुझे अफसोस होता है इस इलाके को हालत को देखकर। यह इलाका ऐसा लगता है कि जैसे हिन्दूस्तान से एक तरह से अलग से रखा गया है।

उसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, फल्ड्ज के लिए जो राशि सरकार ने रखी है वह बहुत थोड़ी है। जहां पर बहुत से इलाकों में चार चार महीन पानी खड़ा रहता हो वहां इतने थोड़े पैसे के क्या बनता है। इसलिए यह जो फलड की रोकथाम के लिए राशि रखी गयी है इसको बढ़ाना चाहिए। हमारी जो जमीन पानी के अन्दर पड़ी हुई है उसके लिए हम किसी भी खर्च की कटौती करनी पड़े तो करनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए सरकार से यह भी अर्ज करना चाहती हूं कि एक कमेटी भी बैठायी जाय जाज यह देखे कि हरियाणे में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कौनसा है और जब यह पता लग जाएतो सरकार को उस इलाके की तरक्की के लिए पहले ध्यान देना चाहिए एक तहसील में मो 18, 18 स्कूलों को 22, 22 स्कूलों को अपग्रेड किया जाता हपरनत किसी जिले में 5-7 स्कूलों का अपग्रेड करने का नम्बर नहीं आत है (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी सरकार को बने हुए केवल दो महीने ही

हुए है लेकिन विरोधी दल के लोग आज ही हमें कहते हैं कि यह सरकार बेइन्साफी कर रही है। मैं तो समझती हूँ कि पिछली सरकार ने जो बे-इन्साफी की थी उतनी हिन्दूस्तान की हिस्ट्री में कही नजर नहीं आती। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कहां के इन्साफ की बात है कि हाउस का एक मैम्बर को उसका साथ बुरा व्यवहार किया जाये वह अपनी जान बचाना फिरे किसी ओर ढंग से उसके ऊपर प्रेशर डाला जाये। जब उसके वक्त में ऐसी बातें हुई हो तो वह स्वयं किस मुहं से कह सकते हैं कि उन पर जुल्म हो गया है उन्होंने माकिटिंग कमेटी वबैरा का जिक्र किया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड है जिस की टर्म दो साल की होती है। मैं उस बोर्ड की एकटिंग चैयरमैन थी मगर क्योंकि राव साहब ने अपनी बहन को उसका चैयरमैन बनाना था, उसे दस महीने में ही खत्म कर दिया हालांकि उसका समय दो साल का था। फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ सड़के बनानी शुरू हुई थी ओर उन पर बीस बीस हजार रूपया खर्च भी हो चुका था किन्तु उन्हें भी बन्द कर दिया गया। तो मेरी प्रार्थना है कि जो इलाके तरक्की नहीं पाये हैं सरकार उनकी तरफ खास ध्यान दे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं प्रार्थना करूंगी कि सरकार कस्टोडियन की जितनी जमीन है। उसको निकाल कर देखे ओर उसे सस्ते दामों पर भूमिहीन लोगों को दे जिन में हरिजन और दूसरी बैकवर्ड क्लासिज के लोग भी शामिल हैं। मेरे ख्याल में काफी जमीन पड़ी हुई है आज कल जो बोली का सिस्टम है उसमें

गरीब आदमी जमीन को नहीं खरीद सकता क्योंकि ज्यादा कीमत देने की उस में हिम्मत नहीं होती। मेरे इलाके में बहुत से ऐसे केसिज है जहां लोग तीस चालीस साल से बैठे हुए है मगर वह जमीन को नहीं खरीद सकता क्योंकि ज्यादा कीमत देने की उस में हिम्मत नहीं होती। मोरे इलाके में बहुत से ऐसे केसिज है जहां लोग तीस चालीस साल से बैठे हुए है मगर वह जमीन को नहीं खरीद सकते क्योंकि कानून के अनुसार वह सिर्फ हरिजन का ही मिल सकती है। मेरी प्रार्थना है कि इस जमनी में बैकवर्ड कालसिज के भी कुछ परसैंटेज की जाये जिस से वह गरीब लोग भी अपना काम चला सकें। आपके साथ ही मेरा एक सुझाव यह है कि भूमिहीन मजदूरों तथा पिछड़े हुए लोगों के लिए जिनका और कोई चारा नहीं है कुछ इन्डस्ट्रीज लगाई जायें। जैसे दूध का प्लांट, शूगर मिल, चमड़ा मिल, इत्यादि जिसमें वे लेग काम करके अपना गुजारा कर सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट के अन्दर बहुत सी चीजें ऐसी आईं जिन को हमें जरूरत थी। मैं उन के लिए सरकार का धन्वाद देती हूँ। मुझे आशा है कि हरियाणा के अन्धर अब वह हालत पैदान नहीं होगी जो पहले को गई थी और जिसकी वाजह से हमारी स्टेट तरक्की नहीं सकी थी। यहां पर 'आया राम और गया राम' और 'गया राम' के नाम की चर्चा चलती थी। और मैम्बरोंकी कीमत डाली जाती रही और इसी वजह से जनता यह विश्वास खो बैठी थी कि सरकार उन के भले के लिये कोई काम

करेगी लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सरकार है वह जनता में विश्वास पैदा करेगी और इसकी रहनुमायी में हरियाणा तरक्की करेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया है वह उन पर ध्यान दें।

चौधरी अब्दुल रजाक खां (फिरोजपुर झिरका):

मोहतरिम, डिप्टी स्पीर साहिबा, आज 1968-69 के बजट पर बहस हो रही है। हाउस के दोनों तरफ के मैम्बरान ने अपने अपने हल्कों के बारमें में सरकार के सामने मशवरा रखा। मैं भी अपने हल्के के आरे में सरकार को कुछ मषवरा देना चाहता हूँ। हमारे इलाके में 1958 से फलड्ज इस कदर मुतासिर है कि लोगों को रोटी भी नसीब नहीं होती। जिन लोगों की उस वक्त दो या चार किले जमीन खदने की हिम्मत थी वे आज सड़कों पर मिट्टी डाल रहे हैं। हम सरकार के तथा अफसरान के नोटिस में बक्तन फवक्तन यह बातें लाते रहे हैं। मगर मुझे अफसोस है कि हमारी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह वहा पर जाकर खुद हालात को देखे तो उसे पता चलेगा कि हरियाण मे अब भी कई ऐसी जगहे जहां पर लोग जिन्दगी से मौत को बेहतर समझते हैं हमारा जो इलाका है वहां बीस बीस मील तक पानी बराबर रहता है और वह इलाका एक झील लजारा देता है। मुझे अफसोस है कि आज तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं अर्ज करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और हालात को ठीक करें ताकि वह लोग भी देश की पैदावार

को बढ़ाने में हिस्सा डाल सकें। हर साल वहां फलड्ज आते हैं चन्द अफसर वहां पहुंचते हैं, कुछ रिलीफ का काम होता है कुछ दिनों के लिए लोगों को राशन भी दिया जाता है। तकावी और ग्रांटस की शकल में लोगों की मदद की जाती है। पिछले साल भी तकरीबन डेढ़ लाख की तकावी और ग्रांटस दी गई। मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को भीख नहीं चाहिए चाहे वह तकावी की शकल में ही गया ग्रांटस की शकल में। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बन्दोबस्त किया जाये जिससे लोग इज्जत से अपनी रोटी खा सकें। वहां पर कोई कन्स्ट्रक्टिव वर्ग शुरू किया जाये। कोई दस्तकारी कायम की जाये जिसमें लोग एम्पाइएमेंट ले सकें।

दूसरा हमारे इलाके में सड़कें भी बहुत कम हैं आपको वहां ऐसा इलाका भी नजर आयेगा जाहं पर दस दस मील तक कोई सड़क नहीं है वहां सिर्फ दो तीन सड़कें हैं। एक सड़क नूस से फिरोजपुर झिरके तक, दूसरी बूढ़ी कोठी से लेकर लहगा कलां होती हुई जमालगढ़ तक और तीसरी जमाल गढ़ से पुन्हाणा पीरू होती हुई कोट तक है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह इनकी तरफ भी ध्यान दें। जैसा मैंने पहले कहा है हमारे इलाके में फलड्ज से बुरी हालत है। पचास पचास गांवों की आबादी हर वक्त पानी से घिरी रहती है। फलड्ज को कन्ट्रोल करने के लिए छोटी छोटी स्कीमें शुरू की जायें ताकि उस इलाके को राहत मिले और जो लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं। वे ऐसा न करके पैदावार बढ़ाने में देश की मदद करें और अपना फर्ज अदा करें। इसके

साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा कि उस इलाके में एक नहर निकली है, उसका नाम तो मुझे इस वक्त याद नहीं लेकिन उस नहर पर 4-4 मील के फासले पर पुल बने हुए हैं। इसकी वजह से जमींदारों की जमीनें हालांकि गांवा के बिल्कुल पास हैं लेकिन वह नहर की दूसरी ओर तब तक नहीं जा सकते जब तक कि पुल पर से न गुजरें और ऐसा करने में उन्हें 4 मील इस पार चलना पड़ता है पुल तक और फिर उधर से 4 मील पुल पार करके फिर वापिस आना पड़ता है। इस तरह सारा समय खेत तक पहुंचने में ही निकल जाता है। और फिर इसी तरह उन्हें वापिस घर आना पड़ता है। इससे बहुत लेबर और समय जाया होता है जिस का असर पैदावार पड़ता है और जमींदार लोग और कोई काम ही नहीं कर सकते। इसलिए इस तरफ सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए और गांव के हर शाहरा पर पुल वगैरह नजदीक बनवाने की कार्यवाही करवानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके बाद मैं इस बजट में ऐसी कोई नुमाया फैसिलिटीज नहीं देखता हूँ जो सियासी मुसीबतजदा लोगों के परिवारों के लिए या उनके लिए इसमें रखी गई हो। जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम सबसे लोग आजाद हुए बैठे हैं उनके लिए हमें फैसिलिटीज देनी चाहिए और इस तरह कुछ करके बाज नुमाया मौकों पर उनकी ठजजत करनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे उस इहालक में 19 गांवों ने ऐनब्लाक सिविल नाफर्मानी अग्रेजों के खिलाफ की थी जिसकी वजह से

उनकी जायदादें जब्त कर लगी थी और आपको यह जानकार ताज्जुब होगा डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि उनकी जायदार आजादी मिलने के 21 साल के बाद भी जब्त ही पड़ी हुई है। आज तक किसी ने उन्हें यह नहीं पूछा कि आपके हकूक माकान कैसे सलब हुए थे औ आपने क्या जुल्म किया था। एक गांव दाह जो झिरका तहसील में और रैसाना गांव जो गुडगांव तहसील में है, वहां के लोग ने जाने कब से मूलक आजाद करने के लिए अपना कदम उठा चुके थे और अंग्रेजों से टक्कर ले कर अपने हकमूम मालाकन जब्त करवा बैठे थे आज इस अम्मीदें में अपना बक्त काट रहे हैं कि आजाद मुल्क के रहनुमा आयेंगे ओर उनकी आंखे हमारी तरफ होगी ओर उनके हकूक मालकान बरकारार होंगे या आल्टरनेटिव होलिडंग दी जायेगी मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरी इस सरकार से गुजारिश है कि उन्हें या उनकी जमीनें वापि दी जायें या आल्टरनेटिव लैंडज दी जाये व कम्पेनसेशन दिया जाए। जिनकी कुर्बानियों से, खुददारियों से मुल्क आजाद हुआ हो, तो उनकी तरफ ख्याल किया जाना लाजिमी है।

मैं यह बातें हाउस में कहना चाहता था और बहुत दिनों से ये मेरी तमन्ना थी कि मैं उनका केस सरकार के सामने ब्यान कर सकूं और इसके लिए 1957 में मैंने इलैक्शन लड़ा, फिर 1962 में इलैक्शन लड़, उसे बाद 1967 में भी पेपर दाखिल किए थे मगर कम्प्रोमाईज करके बैठ गए लेकिन अब 1968 में चुनाव लड़ने के बाद यह ख्याल जाहिर करने का मौका मिला है जो मैं

मन्त्री महोदय के सामने, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके जरिए रख रहा हूं। अब यह अउनका फर्ज बनता है कि वह उन लोगों की तरफ गौर करें।

इसके अलावा फिरोजपुर झिरका की एक और समस्या मैं आपके जरिए हाउस में पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि फिरोजपुर झिरका में पहाड़ है, उस पहाड़ के दामन में जमीन दोज नहरें बहत है, वहां से चाहे जितना पानी चाहे निकाला जा सकता है। अगर सरकार ट्यूबवैल लगाए तो। इस लिए मुरी गुजारिश यह है कि चूंकि वहां के आदमी बहुत गरीब है उनकी हाल दुरूस्त करने के लिए सरकार को पानी निकालने के लिए ट्यूबवैल लगाने चाहिए। इससे हजारों एकड़ जमीन में आबपाशी हो सकती है और जिस से कि लोगो की इमदाद होगी और मुल्क की पैदावार बढ़ेगी।

तहसील नूह में ,जहां पर मेजर पापुलेशन मेओं की है, जो कि जमीन पर गुजारा करते है पैदावार हो जाए तो गुजारा हो जाता है ओर नह हो तो दूसरों से उधार ल ले कर जिन्दगी बसर रकते है। वहां की हालत ऐसी है कि कभी फलड से जमीन बरबाद हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं वहां जमीन पर खेती करने वालों का मुद्दत से यही हाल है। इसलिए उन्हें तालीम की तरफ बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह पढ़ लिख कर और कोई काम करके अपने परिवारों का गुजारा कर सकें। इसके लिए वहां पर एक कालेजा होना चाहिए और कम से कम दो तीन स्कूल मिडल

से मैट्रीक होने चाहिए और बिछोह ओर मलाई के जो स्कूल है उनको अपग्रेड करना चाहिए। यह मेरी छोटी सी दरखास्ता है। सरकार इसको कबूल करें। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए उस बैबर्ड ऐरिया के लिए यह शर्त न रखी जाय कि इतना पैसा जमा किया जाए या बिल्डिंग बनाई जाए तो ही अपग्रेडिंग होगी। सरकार को सीधे तौर पर उस इलाके की मदद करनी चाहिए। अगर किसी को यकीन नह हो कि वह इलाका गरीब है तो कोई मैम्बर या मिनिस्टर हमारे साथ चला चले और खुद जा कर वहां की हालत देख ले। कई बार लोग जाते तो है और उनकी बड़ी हिम्मत अफजाई करते है हौसला बढ़ाते है लेकिन प्रैक्टिकली होता कुछ नहीं सिर्फ ब्यानात दिए जात है ओर वह वही झाड़ दिए जाते हैं हर कोइ उनके आंसू पोंछ कर चला जाता है।

उपाध्यक्षा: जरा शार्ट करें तो अच्छा है।

चौधरी अब्दुल रजांक खां: बहुत अच्छा जी। एक जगह आकेड़ा कोटला के अन्दर सरकार एक झील बनाने का प्रोग्राम रखती हैं इसकी पोजीशन इस तरह है कि वहां पर साल दो साल बराबर पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से लोग अपनी जमीनों पर खेती नहीं कर पाते लेकिन जब कभी वहां पानी सूखता है तो उस जमीन में इतनी जरखेजी आ जाती है कि बेतहाशा पैदावार होती है और वहां के जमींदारों की पिछली कसर पूरी हो जाती है। अब अगर सरकार वहां पर परमानेंट झील बना देगी तो मैं

पूछना चाहता हूं कि उन जमींदारों के गुजारे के लिए क्या आल्टरनेटिव जरिया देगी और वह लोग कैसे अपनी जिन्दगी बसर करेंगे? इस पर सरकार रोशनी डाले।

हमारे इलाके में महकमा जंगलात ने बहुत से मैदान मे जंगलात खड़े किए हुए है जिनसे किसी किस्म की आदमनी न तो सरकार को और न वहां के लोगों को कोई फायदा है। उल्टा सरकार को 60-70 हजार रूपया सालाना खर्च हो जाता है और गरीब आदमियों को यह दिक्कत है क्योंकि उनके मवेशियों को उसमें पहले तो हाक दिया जाता है और फिर उनस पैसा वसूल किया जाता है। यह लोगों को हार्डशिप बनी हुई है ओर दूसरी ओर सरकारको बरबार घाटा हो रहा है। तो इसके मुताल्लिक मेरा सुझाव यह है कि अगर जंगल काट दिए जायें तो वह जमीन जो कि काबिलें काश्त है, अनाज की पैदावार के नीचे लाई जा सकती है। इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह काबिलेंकाश्त जंगत सरकार को रिलीज कर देना चाहिए।

इस तरह काले पहाड़ की बाबत है जो 60-70 मील लम्बा है उस पर हर साल लाखों रूपए खर्च तो होते है ओ ओ एक धेले की भी उससे आमदनी नहीं है। पिछले बीस सालों से उन पर खर्चा हो रहा है लेकिन नफा एक पैसे का भी नहीं हुआ। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे पहाड़ और ऐसे जंगलात जो है उनको रीक्लेम करके लोगों की काश्त के लिए दिया जाएं और सरकारी खजाने से बाझ कम किया जाए।

चौधरी राम प्रकाश (मुलाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपनी बहन ओम प्रभा जैन को मुबारिक पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने थोड़े से अर्से में हरियाणे का शानदार बजट पेश किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मौजूदा कैबिनेट की रहनुमाई में हरियाणा बहुत तरक्की करेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपोजिशन के दास्तों की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गईं जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। अगर वह जाति कीचड़ उछालने की बजाए हरियाणे की डिवैल्पमेंट के लिए कुछ सुझाव देते तो अच्छा होता। खासकर राव साहिब, जो यहां पर इस वक्त बैठे हुए नहीं हैं, और मंगलसेन जी ने यहां पर अपनी स्पीचों में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहा जो कि रैलेवेट हो।

श्री मंगल सेन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह 1952 से मैम्बर चले आ रहे हैं। इन को इसबात की समझ होनी चाहिए कि इरैलेवेट यह है या मैं था।

चौधरी राम प्रकाश: हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, इसलिए हम आपकी की तरफ बोलना नहीं चाहते। (विघ्न) अभी तो तू बचा है जरा बैठ जा।

Mr. Mangal Sein: Madam, Deputy Speaker, it is not proper for the hon. Member to use the word "Bacha".

Health Minister: This is a very innocent expression.

Shri Mangal Sein: Then, Madam, I say that this expression is chilis. (Interruption).

चौधरी राम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट तो बड़ा शानदार है लेकिन मैं अम्बाला की तरफ से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप भी इसी जिले के हैं, इसलिए आप जानती हैं कि जब ज्वारंट पंजाब था तो उस वक्त पंजाब वाले कहते थे कि जिला अम्बाला हमारा नहीं है और हरियाणा वाले कहते थे कि हमारा नहीं है। इसलिए हम पर मुश्किल यह आ गई कि हम पंजाब में जाएं या हरियाणा में। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सन् 1954 से चण्डीगढ़ अम्बाला जिला में वाक्या है और यह राजधानी रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ चण्डीगढ़ को ही लोग देखकर कहते थे कि अम्बाला बहुत तरक्की कर रहा है। परन्तु जहाँ तक हमारे अम्बाले के देहाती इलाकों का ताल्लुक है वहाँ बहुत बुरी हालत है, न कहीं सड़के हैं, न स्कूल, न हस्पताल, न बिजली, और न ट्यूबवैल्ज ही लगाए गए हैं। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर वाइंग वह समझते हैं कि अम्बाला हरियाणा में शामिल है तो लाजमी तौर पर इनको हरियाणा की तरक्की के लिए खासतौर पर सोचना पड़ेगा। जहाँ आप करनाल, रोहतक और हिसार की तरफ तवज्जुह देते हैं वहाँ अम्बाले की तरफ भी खास वज्जुह देनी चाहिए। जब कैरो साहिब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय भी और उसके बाद श्री राम किशन, पंडित भगवत दयाल और राव साहिब की सरकारों के समय भी मैंने एक सजैशन दी थी कि अगर आप मारकंडा, सरस्वती

ओर जो चार पांच और नदियां है। उनके ऊपर बांध बांध दे तो हर साल जो हरियाणा में फलड आते है और उन पर जो करोड़ों रूपया खर्च होता है वह सारा बच सकता हैं इसके इलावा जो पानी है वह आबपाशी के काम आ सकता है और उससे लोग खुशहाल हो सकते है। लेकिन मुझे हैरानी होती है खास करके इरीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरों पर कि उन्होंने आज तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पिछले इस सालों से यह मैं कहता चला आ रहा हूं लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब, देहली जाते रहते है ओर वह जातने है कि रास्ते में सवा मील का टुकड़ा हमेशा पानी में डूबा रहता है। बराड़े के अन्दर आप जा कर देखें वहां पर पानी का कोई निकास नहीं है। मेहरबानी करके वहां से पानी किलें वर्ना वहां पर बीमारी पड़ने का खतरा है। मेरी आपकी खिदमतमें अर्ज है कि अम्बाला की डिवैल्पमेंट की तरफ आप को खास ध्यान देना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब बड़े नेक आदमी है, मुझे आशा है कि वह मारे पिछड़े हुए जिला की तरफ खास ध्यान देंगे।

जहां तक तालीम का ताल्लुक है आपको पता है कि पिछली दफा जब स्कूल अपग्रेड करने का सवाल आसा तो हमारे स्कूल गुड़गांव और रोहतक के ही अपग्रेड हुए। आज राव साहिब कहते है कि उन्होंने हरियाणा में किसी के साथ बेइन्साफी नहीं की लेकिन क्या वह भूल गए कि उन्होंने प्रण कर रखा था कि किसी कांग्रेसी मैम्बर के हलका में कोई काम नहीं हाने देना है और उन्हे

कुचल कर रख देना है। उनकी उस तबाही का खासतौर पर हम अम्बाला वाले शिकार हुए। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे साथ जुल्म किया हुआ है वह दूर होना चाहिए। हमारे पावड़ी से सरहा की सड़क मन्जूर हुई थी लेकिन जब उसे कागजात राव साहिब के सामने आए तो उन्होंने फौरन पीछे कर दिया। इसी तरह से मुलाना से नारायणगढ़ वाली सड़क है जो ऐसे ही पड़ी है और ध्यान नहीं दिया गया। तो अब मैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहिब से कहूँगा कि जो जुल्म हमारे साथ उन्होंने किया है उसे दूर किया जाए और हमारी यह सड़क फौरी तौर पर बनाई जाये।

मंडियों के बारे में भी अर्ज करता हूँ कि एक मैम्बर साहिब ने कहा कि काफी अनाज मण्डिरुमें सड़ता है लेकिन आप देखे कि जहां पर मंडी ही नहीं है वहां क्या हाल होता है। हमारे यहां कोई मंडी नहीं है। वहां पर करनाल और दूसरे इलाकों से अनाज आता है लेकिन वहां पर कोई शौड नहीं है जिसकी वजह से बारिश आने पर सारा अनाज खराब हो जाता है लाखों मन गल्ला महज मंडी नह होने की वजह से खरबा हो जाता है। जमींदार मजब है। उन्हें खर्च के लिये पैसा चाहिए। इसलिए उन्हें अनाज बेचने आना पड़ता है। इसी तरह से मुलाना में भी मंडी की जरूरत है मैं सरकार से अर्ज करता हूँ कि जब मंडियों के बनाने का सवाल आए ता मुलाना और बराड़ा में मंडियां बनाई जाए ताकि हमारे इलाका के लोगों को राहत मिल सकें।

तालीम के बारमें मै अर्ज करता हूं कि मेरे इलाका में कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने का वायदा किया गया था। मिसाल के तौर पर तन्दवाल और सराहों के स्कूल है। उनकी इमारते बनी हुई है लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान ही दिया गया है। भगवत दयाल मिनिस्टरी की जितनी स्कीमें थी वह पता नहीं इन्होन कहां फैंक दी हुई है। इसलिए सरकार से अर्ज करताहूं कि उन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। जहां तक बिजली का सवाल है। करनाल में बहुत ट्यूबवैल लग हुए है और वहां बिजली भी काफी ज्यादा है अम्बाला से जागाधरी का जो पहाड़ी इलाका है वह हर मामला में इगनोर्ड है न वहां बिजल है और न कोई ट्यूबवैल ही है। कहते है कि दो हजार की आबादी वाली जगह बिजली देते है लेकिन मै पूछता हूं कि क्या इससे कम आबादी वाले गांव के लोग क्या इस आजाद देख के बाशिदे नहीं है? वह कहां जाए अगर उनको कुछ नहीं देना है। मै आई.पी.एम. साहिब से कहूंगा कि अगर कम नहीं तो दो साल के अन्दर अन्दर हर गांव में बिजली गई ही नहीं है और अगर कही गई है ते आप बेशक जाकर देख लें हरिजन बस्तियों में बिजली का कोई खम्बा तक नहीं लगाया गया। इस सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और गरीब हरिजनों के घरों में भी रोशनी देने का इन्तजाम करना चाहिए। मेरे इलाका में लोग ट्यूबवैल के लिए तड़पे है जब वह दूसरी जगह करनाल रोहतक जा कर सह सारीचीजे लगी हुई देखते है है तोउनहें अफसोस होता है कि हमें कोई नहीं पूछता। हमारे जिले की जमीन शानदार है और किसान मेहनती है लेकिन पानी न होने के कारण

पैदावारनही होती है। मै दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप जिला अम्बाला को ट्यूबवैल्ज दे तो वह सारे हरियाणा को फीड कर सकता हैं माकंडा के इलाका में कोई 150 गावों है न वहां कोई सड़क है न हस्पताल है, न स्कूल है और न बिजली वगैरा कुछ है। उनसे एक तरफ मारकंडा बहता है और दूसरी तरफ टांगरी और घग्गर बहते और वे गांवों टापू बने हुए है। इतने साल हिन्दूस्तान को आजाद हुए हो गए है लेकिन इस इलाका की रिफ आज कि किसी का ध्यान नहीं गया है और वह लोग परमात्मा के रहम ही पर है, क्योकि सरकार ने कोई फैसिलिटी उनकों देने की कोशिश नहीं की है।

एक बात है हरिजनों के बरें में भी करना समझात हूं। आप सब जातने है कि यह जो सरकार बनी है यह हरिजनों ने बनाई है। सारा हिन्दूस्तान जानता है कि सोर देश में सिर्फ हरियाणा में 80/85 फीसदी वोट हरिजनों के पोल हुए है तब जा कर सह सरकार बनी है। अगर हरिजन वोट ने देते तो यह कांग्रेस सरकार नहीं बन सकती थी। जो भाई यह कहते है कि बंसी लाल जी ने यह कर दिया और ओम प्रभा जैन ने यह कर दिया वह बकवास करते है.....

श्री मंगली सेन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। यह वैसे तो बड़े सयाने मैम्बर है लेकिन यह जो इन्होने बकवास शब्द का प्रयोग यिका है यह ठीक नहीं है इसे वापिस कराएं तो अच्छा है।

उपाध्यक्षा: आप यह बकवास लफज वापिस ले ।

चौधरी राम प्रकाश: मैं आपका हुक्म हर वक्त मानने क लिये तैयार हूं और वापिस लेता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि आप सब जानते है कि सरकार हरिजनों के बलबूते पर बनी है लेकिन फिर भी जब हरिजनों के साथ ही बेइन्साफी होती है तो बड़ा अफसोस होता है। मैं यह नहीं कहता कि पिछले 20 साल में हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ लेकिन.....

उपाध्यक्षा: आप अभी और कितना समय लेंगे?

चौधरी राम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मुझ सिर्फ पांच मिनट और दें। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ अब भी वही बेन्साफी हो रही है जो पहले होती थी। हम खुश हुए थे कि एक जालिम सरकार खत्म हुई जिसने कि लोगोंको और खासतौर पर हरिजनों कको तंग किया हुआ था। हम तो कहते थे कि हरिजनों से पिछले बीस साल से बेन्साफी हो रही है। लेकिन जो गंद इन्होने 9 महीने के अपने अहद में डाल उसका हिसाब नहीं है? और हम हैरान है वह कैसे दूर किया जाए? इस तरह अगर इन गरीब आदमियों पर बेइन्साफी होगी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार कोई ठीक काम नहीं कर रही है। यह ठीह है कि इसके लिए रूपया रखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह उतना नहीं जितना रखा जाना चाहिए। कम से कम एक करोड़ रूपया होना चाहिए। इसके इलावा डयरैक्टर वैलफेयर की

एक पोस्ट थी वह भी खतम कर दी गई है ताकि इन गरीबों को देखने सुनने वाला कोई न रहे। इसलिए मेरी अर्ज है कि इस पोस्ट को दोबारा क्रिएट कर दिया जाए।

अब मैं कस्टोडियन की जमीन के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। यह जमीन सरदार प्रताप सिंह की मेहरबानी से हरिजनों को मिलनी शुरू हुई थी। यह जमीन हरिजनों को सस्ते भावों पर मिलनी चाहिए। यह लोग भूखे हैं, ठीक तरह से गुजारा नहीं कर सकते मगर इन को आठ आठ छस दस हजार रूपया देना पड़ता है वे सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें इतना रूपया देना पड़ेगा। कुछ लोग किश्तें देते भी हैं और कुछ नहीं दे सके। जो दे सकते हैं उनकी किश्तों कुल लेट हो जाती है और इस बिना पर अधिकारी सारी कीसारी जमीनकी एलाटमेंट कैसिल कर देते हैं। इस प्रकार हैडक्वार्टर पर काम करने वाली अधिकारी उन गरीब हरिजनों के साथ रूखा व्यवहार करते हैं। अगर कोई आदमी अपील भी करना चाहता है तो उसे पास पैसा नहीं होतौ। बड़ी कठिनाई से उन लोगों ने जमीन मेंसे जंगल साफ किये, खाईयां को भरा। अगर उन्हें किश्त देने में थोड़ी देर भी हो जाये तो इस का मतलब नहीं कि उनकी जमीन ही छीन ली जाए। उनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए माफ कर देना चाहिए। इसलिए स्पीकर साहिब, आपके जरिए गवर्नमेंट के नोटिस में मैं यह बात लाना चाहता हूँ कि हरिजनों की इस मुसीबत को दूर किया जाना चाहिए। हरिजन कल्याण के लिए जितना रूपया रखा गया है वह नाकाफी है।

ज्वायंट पंजाब में एक रकम 6-7 करोड रूपया होती थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिये।

एक और खास बात, जिसे आप एप्रिश्िज़एट करेंगे वह यह कि जब किसी लड़के की नौकरी के लिए हरिजन होने सबूत देने के लिए सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ती है तो उसे कहते है तुम मैजिस्ट्रट से सर्टिफिकेट लाओ। उन बच्चों को मैजिस्ट्रट के पास जाना पड़ता है है तब कही नौकरी मिलने की उम्मीद होती है। अदालतों में तो प्रोसीजर यह है कि पहले किसी पटवारी या तहसहीलदार की तसदीक रवा कर मैजिस्ट्रट के पास जाये। इस प्रकार एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कम से कम सौ रूपया खर्च हो जाता है।

चौधरी लाल सिंह: डिप्टी स्वीकर साहिबा, एम.एल.एज. को भी अपना सर्टिफिकेट दूसरां से अटैस्ट करवान पडते है।

उपाध्यक्षा: आप बैठ जाएं।

चौधरी लाल सिंह : डिप्टी स्वीकर साहिबा, मैने प्वायंट आफ आर्डर उठाया हैं इन एम.एल.एल. हो भी अपने सर्टिफिकेट अटैस्ट करवाने िलिए दूसरों के पास जाना पड़ता है।

उपाध्यक्षा: आप बैठ जाइए यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधीर राम प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। कि शैड्यूलड कास्ट के बच्चों को अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जब बच्चा स्कूल छोड़ता है यानी जब वह स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लाता है तो उस सर्टिफिकेट में एक खाना होना चाहिए जिससे शैड्यूलड कास्ट लिखा हुआ हो। इसमें यह सबूत दे दिया जाये कि यह हरिजन लड़ा है। इस तरफ शैड्यूलड कास्ट बच्चे मजिस्ट्रेट के पास जाने की मुसीबत से बच जाएँ उनकी सारी सिरदर्दी खत् हो जायेगी। मेरा ख्याल है कि आप सब इस बात को एप्रिशिअट करेंगे (घंटी)। बस, जै ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिर मैं, मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का काफी टाईम दिया है।

चौधरी लाल चन्द्र खोद (ऐलनाबाद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस मिडटर्म इलैक्शन में भी श्री ओम प्रकाश को मैंने 5331 वोटों से हराया जबकि चौधरी देवी लाल ने और उनके साथियों ने 11 हजार नये वोट अपर्ली करवाये थे। जब इस धांधली का पता चला तो हमारी बड़ी कोशिश के बाद इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सपैसिफिट आर्डर किये कि हल्का ऐलनाबाद की लिस्ट को दोबार जांच की जाए। इस पर डी.सी. हिसान ने 24 आफिसर डियूटी पर लगाये जिन्होंने एक ही दिन के अन्दर 72 विलेजिज में जाकर मौके पर इन्क्वायरी की और 7 हजार वोट

कैसिल की। इस इन्क्वायरी में जो गिलटी पर्सन्ज थे उन के खिलाफ डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर आफ इंडिया, मिस्टर जैक्व, ने यह आर्डर यिथे कि इनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। लेकिन मुझ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने उन अपराधियों को सजा देने के लिएकेई इन्तजाम नहीं किया हैं उनके ये आर्डर काफी दिनों से पैडिंग पड़े है। इसलिए, मेरी सरकार से दरखास्त है कि सरकार इस तरह तवज्जुह दे। सरदार करनैल सिं, एस.एच.ओ. जिन्हे पहले जनरल इलैक्शन में भी राणिया में लगाया गया था। और क्योंकि पहले जनरल इलैक्शन में भी मैं चौधरी देवी लाल के सुपुत्र श्री प्रताप सिंह से लड़ा था जिन्हे पांच-सात दिन पहले सरकारने तबदील कर दिया था, उसे दोबारा इस मिडटर्म इलैक्शन में भी राणियों के थान में ही लगाया। इस थानेदान ने इलैक्शन में कांग्रेस की आट आफ दी वे जाकर मदद की। ये खुले तौर पर मदद करते रहे और लोगों को नाजायज तौर पर तंग करते रहे।

महंत गंगा सागर: आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम, आनरेबल मेम्बर साहिब, अगर बजट पर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम भी बजट पर बोलना चाहते है। बाद में हमें बोलने के लिए टाईम नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहिब, आप बजट पर बोले।

Ch. Chand Ram: The hon. Member is not speaking irrelevant, Madam. He is speaking on General Administration, which is included in the Budget.

उपाध्यक्षा: आप इलैक्शन का ही जिक्र कर रहे हैं, बजट पर बोले।

Ch. Chand Ram: There is a provision of funds in the Budget for elections. So, the hon. Members is quite relevant.

चौधरी लालचन्द खोद: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा था कि ये एस.एच.ओ. चौधरी देवी लाल के इशारे पर चलते रहे। 107 और 151 की एकतरफा कार्यवाही बेगुनाह लोगों के खिलाफ की जा रही है और लोगों के असलाजात पुलिस ले नहीं है। इसका एक कारण यह भी कि चौधरी देवी लाल ने बोगस ऐलीगेशन लगाकर खिलाफ पैरिसीशन दायर की हुई है श्री रामजी दास सरपंच राणियां, को पिटवाने में भी उनका हाथ है। इस तरह इस पैरिसीशन का लोगों पर नाजायज तौर पर रोक डाल कर तंग किया जा रहा है इस थानेदार को तबदील करने के लिए लोगों के कई डेपुटेशन सरकार को मिले हैं लेकिन अभी तक उस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए, सरकार से मेरी अपील है उसे फौरन तबदील करें ताकि लोगों कुछ इन्साफ मिल सकें।

खैर, इन बातों में ज्यादा न आता हुआ मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि बिजली की तरफ हमारे इलाकों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ 87 गांवों में से केवल 3 गांवों में बिजली

है। क्योंकि बिजली की लाईन वहां पहुंच चुकी है और बाकी गांव को भी बिजली देने में ठीक जयादा खर्च नहीं आएगा इसलिए सरकार की बड़ी कृपाहोगी यदि व बचे हुए बाकी गांवों में भी जल्दी से जल्दी बिजली देने की कोशिश करेगी।

इसी तरह, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सड़कों की भी हमारे इलाके में बहुत बुरी हालत है। एक सड़क सरस एलनाबार माधो शिधाना तक बनी हुई है। इसे माधो—शिधाना से एलनाबाद तक बनाना, है दूसरी सड़क मुन्नावाली से एलनाबाद बरासता जंगमलेरा भी अभी अधूरी पडत्री है। इसे बना कर पूरा कर दिया जाय तो डबवाली से बलनाबाद क लिक हो जायगा जो दो मंडियां है। माधों सिधाना ऐलनाबार सड़क के लिए गवर्नर साहिब ने इसके बनाने की मंजूरी भी दे दी थी परन्तु अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया। इसलिए मैरी प्राथना है कि इसे जल्दी बनाया जाना चाहिए। तीसरी सड़क सरसा से ऐलनाबाद वाया जगमलेरा बननी है। जोकि लगमलेरा से एलनाबाद तक बाकी पड़ी है इसे भी जल्दी बनवाया जाना चाहिए क्योंकि इन सड़कों के बगैर लोगों को बड़ी दिक्कत है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमार एरिया फ्लड अफैक्टिड है और फ्लडों को रोकने के लिए पिछले कुछ अरसे में सरकार ने जो काम किया है उससे मैं बड़ा प्रभावित हूं मगर इसमें अभी भी काफी कुछ करने की गुंजायश है। हमारे यहां बाढ़ की वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी परन्तु सरकार ने वहां बांध बांध

करबाढ़ को अने से रोका है और पानी की काबिले आबपाशी कर दिया है परन्तु बांध अभी तक पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुए हैं इसलिए सरकार को इन्हे भी मुकम्मल करवाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

ट्यूबवैल तो वैसे हमारे इलाके में काफी है और पानी भी बड़ा मीठा है परन्तु बहुत से लोग अभी ट्यूबवैल लगाना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि काफी खुदाई के बाद जब उन्होंने कहीं खरा पानी मिलता है तो बड़ी निराशा होती है। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि यदि वे मशीनरी के द्वारा बोरिंग का काम खुद करें और यदि पानी मीठा निकले तो लोगों से बोरिंग चारिजज क लिये जावें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लोग ऐसा करने को तैयार हैं। इससे न सिर्फ लोगों की मदद होगी बल्कि देश का उत्पादन बढ़ेगा। अगर पानी खारा निकले तो उस हालत में जमींदार से कोई पैसा चार्ज न किया जावे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ट्रांसपोर्ट का सिलसिला भी हमारे यहां ढीला ही है ; सरसा से माधो सिधाना तक पक्की सड़क है माधो-सिधाना से आग्र ऐलनाबाद तक 18 मील का कच्चा टुकड़ा है लेकिन इस परभी बस बड़े आराम से चल सकती परन्तु अफसोस है कि कोई बस नहीं चार्ड गई। जब राजस्थान में बहुत बड़े बड़े टीबों पर भी बचे चल सकती हैं तो हमारी इस सड़क के ऊपर भी बस चलाई जानी चाहिए इससे लोगों को आने जाने में काफी आराम हो जाएगा।

इसी तरह से, डिप्टी स्पीकर साहिबा, नहरों की ओर भी आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ओटू से एक नई शोरावली पैरेलल चैनल नाम नहर निकाली गई है। यह पूरी तो हो गई है। मगर ओटू से पांच चार मील तक इस नहर की बैक (पटड़ी) पर मिट्टी न डालने की वजह से बड़ी कमजोर रहती है और पूरा पानी ओटू में होने के बावजूद भी नहर को फूल नहीं चलाय जा सकता जिसकी वजह से जमींदारों को अेल तक पूरा पानी नहीं पहुंच सकता। इसकी ओर भी सरकार को जल्दी ध्यान देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे हल्का में कुछ माइनों और नहरों को और एक्सटैन्ट किया जा सकता है। जिससे काफी रकबे को पानी मिल सकेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एलानाबद, किसनपुरा माइनर (घग्गर साऊथ कैनल) को एक्सटैण्ड करने की स्कीम एक्सीयन-सरसा के पास पैडिंग पड़ी है। अगर इसे एक्सटैण्ड कर दिया जावे तो कुछ और रकबे में आबपाशी हो सकती हैं इसी तरह से न्यू शोरावाली पैरेलल चैनल में 29,000 बुर्जे से एक नया माइनर और लिकाजा जासकता है जिससे चिलकनी ठाब, भूरखाला पौहडका, सुरेरां, कर्मसाला तक के गांवों के अनकमांडिड रकबों में पानी ओर लग सकेगा। पैदावार में बढ़ावा होगा ओर लोग भी खुशहाल होंगे। इस तरह की स्कीमों को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार को कमद उठाने चाहिए (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अन्त में मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल जी से यह कहूंगा कि यह

बड़े सौभाग्य की बात है कि हिसार के एक भाई मुख्य मंत्री बने हैं परन्तु जरूरी बातें कहनी हैं मेरे इलाक़ों में दो तीन गांव बह गए हैं।

उपाध्यक्षा लाल सिंह जी आप बैठ जाइए (चौधरी लालसिंह जी खड़े रहे) लाल सिंह जी मैं कहती हूँ कि आप बैठ जाइए। आन नहीं बोलेंगे, अब चौधरी नेकी राम जी बोलेंगे।

चौधरी नेकी राम (नरवाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो सबसे पहले बजट पर बोलना जरूरी है परन्तु पूर्व इसके कि मैं बजट पर कहूँ, अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं हल्का नरवाना से शमशेर सिंह जी, जो स्टेट मिनिस्टर होत थे, को 6,208 वोटों से हराकर यहां आया हूँ (कांग्रेस दल की तरफ से प्रशंसा) तो यह तो रहा मेरा परिचय। अब मैं बजट की ओर आता हूँ। बहन जी ने जो बजट पेश किया है उसमें इन्होंने माहिरनी के मशवरे से हर पहलू के ऊपर रोशनी डालने की वैसा तो पूरी कोशिश की है। मगर कुछेक सुझाव मैं भी देना चाहूँगा। एक तो आठ करोड़ के ऊपर का जो घाटा दिखाया गया है, वह समझ नहीं आता कि कैसे पूरा होगा। खैर, फिर इस बजट के अन्दर किसानों के मुताल्लिक बहुत कम हहा गया है। कोई एण्सेली बात मेरी समझ में नहीं आई जिससे पता लग सके कि किसानों की तरक्की बेहतरी और बहबूदी के लिए कोई खास तवज्जुह दी गई हो या कोई खास प्लान रखी गई हो। किसान अपने देश की ओर इस छोटे से हरियाणा प्रांत की रीढ़ की हड्डी है और इनको खुशहाल रखना और इनको

तरक्की देन निहायत जरूरी है। जबकि किसान खुशहाल नहीं होंगे, जब तक उनको ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक मैं कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि हमारा सूबा खुशहाल नहीं होगा। जो किसान मुसीबत के वक्त देश की रक्षा करता है, अमन के वक्त देश में अनाज पैदा करता है, जो हमेशा देश की सेवा में लगा रहता है और थोड़ी सी प्रेरणा के ऊपर सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर देता है, उसकी बेहतरी के लिए अगर कुछ नहीं किया जाए तो यह शोभा देने वाली बात नहीं। यह ठीक है कि लोगों को खाद दी जाती है और मशीनरी वगैरा में जो रियायतें रखी गई हैं वे भी दी जाती हैं मगर किसान को ये चीजें हासिल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट में कहा गया है कि ट्यूबवैल बढ़ाए जाएंगे। यह बड़ी अच्छी बात है। ट्यूबवैल जरूर बढ़ाने चाहिए। मगर लैन्ड रैवेन्यू का जिक्र करते समय उसके ऊपर एक बोझ है और बजाए लैन्ड रैवेन्यू को बढ़ाने के कम किया जाना चाहिए।

सड़कों को बढ़ाने का भी, डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट में जिक्र किया गया है। पहले भी बहुत बढ़ी है मगर इन्हे और बढ़ाया जाएगा।

इसके अलावा मैं अपने इलाके की कुछ जरूरतें अर्ज कर देना चाहता हूँ। जींद और नरवाना का इलाका महाराज पटियाला के वक्त भी ओर पैप्सू के वक्त भी बहुत पीछे रहा है। क्यों पीछे रहा है इसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता क्योंकि बात बढ़ जाएगी, मैं तो सिर्फ यह बात कह देता हूँ कि इसे जानबूझकर पीछे रखा गया था। अब भी मुझे कुछ ऐसी बात नजर आती है क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहां रोहतक, हिसार और गुड़गांव के बारम्बार में जिक्र आता है। इनके मुताल्लिक बड़ी लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं। बातें की भी क्यों न जाए ! इनके तो बड़े बड़े लीडर यहां हैं और रहे हैं। जो जो अच्छी चीजें होती हैं वे इन जिलों में चली जाती हैं। मगर, डिप्टी स्पीकर साहिबा आपके द्वारा सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि अब इस पिछड़े हुए इलाके की तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगर बाकी का हरियाणा बड़ा हरियाणा है तो यह छोटा हरियाणा है।

उपाध्यक्षा: वह तो ठीक है मगर तरक्की के लिहाज से दो बन गए हैं इसलिए सरकार से मेरी बार बार गुजारिश है कि इस पिछड़े हुए इलाके की तरफ जरूर ध्यान दिया जाए।

इस इलाकें में बहुत ही थोड़ी सड़कें हैं। और मैं समझता हूँ कि पानी की भी यहां किल्लत है हमारे इलाके की जमीन बड़ी जरखेज है। अगर मुनासिब तौर पर पानी देने का प्रबन्ध कर दिया जाए तो अनाज की दिक्कत काफी हद तक दूर हो सकती है।

एक बात मैं इस घाटे में, जो इस बजट में दिखाया गया है, कहूंगा कि हमारे यहां हरियाणा में कई फजूल किस्म के महकमें हैं, अगर उनको बन्द कर दिया जाये तो कोई हर्ज की बात नहीं। मैं खासतौर पर जो यह ब्लाकों को महकमा बना रखा है इसके बारे में कहूंगा कि यह बिल्कुल बेमाने है। इसका कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं और फजूल का सूबे पर बोझ है। इसको खामखह ही लाद रखा है। अगर इस महकमे को खत्म कर दिया जाये तो बहुत अच्छी बात है। उनको फजूल एक जीप दी हुई है वे उससे ऐशो इशरत करते हैं और पब्लिक को कोई काम नहीं करते और मौज उड़ाते फिरते हैं।

सरकार ने इस बजट में फीस माफी का जिक्र किया है बड़ी अच्छी बात है फीस तो माफ होनी चाहिए, चाहे कोई हरिजन है, चाहे वह किसान है, चाहे दूसरे हो। लेकिन आपने जिस तरह से हरिजनों को रियायतें दे रखी हैं और देनी भी चाहिए। पिछले काफी दिनों से उनको इन रियायतों की जरूरत भी थी। उसी तरह से जमींदारों को भी ये रियायतें मिलनी चाहिए क्योंकि बगैर रियायतें दिये उन्हे बच्चे भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब आग्र नौकरी में जाने का सवाल पैदा होता है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है और अच्छी जगह पर नहीं जा सकते। उनका भी से सारी सहुलियतें मुहैया होनी चाहिए जो हरिजनों के बच्चों को है। और नौकरियों में लेते वक्त भी उनके बच्चों का खयाल रखा जाना चाहिए।

हमारे सूबे में इलैक्शन हुआ। यह ठीक है। कि कांग्रेस सरकार के आने से लोगों को बहुत खुशी हुई है और लग यह समझते हैं कि पिछली सरकार ने जो कुछ गलत काम किये हुए हैं वे कांग्रेस सरकार के आने से दूर हो जायेंगे। इसलिए मैं एक सुझाव देता हूँ। यह एक पालिसी की बात है और दूसरे किसिम की बहुत बातें कही गयी हैं लेकिन एक बात किसी ने भी नहीं कही जोकि अमन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे सारे हरियाणों में असला के लाइसेंस जो दिये जा रहे हैं वे बड़े गलत आदमियों को दिये जाते हैं। वे रातों रात डकैती करते और बहुत बरे से बुरा काम करते हैं और दिन के अन्दर वे लाइसेंस-दार सड़कों पर घूमते हैं और अपने आपको बहुत अच्छे और ऊंचे दर्जे के नेता जाहिरकरते हैं अगर अच्छे तरीके से इन लोगों की छान बीन की जाये तो मैं समझता हूँ कि यह जो लाइसेंस इस तरह से जिन आदमियों को दिये गये हैं इनमें से कितने ही गलत आदमी होंगे तो डकैती कराते हैं और अमन में खलल पैदा करते हैं। इसलिए मैं सरकार से अर्ज करता हूँ और जरूरी समझता हूँ कि आर्मज के लाइसेंस का मिलना सिर्फ शरीफ आदमियों तक ही रहे ताकि पब्लिक में कोई बदअमनी न हो।

मैं ज्यादा तफसील में न जाता हुआ एक आत और कहता हूँ। यह बजट स्पीच से अलग है। यहां हाउस में कई बार गाली-गलोच और गलत बातों तक नौबत पहुँच जाती हैं यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। यह कोई शोभा देने वाली बात नहीं। जिस

तरीके से सरदार प्रताप सिंह कौरों के मुताल्लिक यहां हाउस में
।बतें कीगयी, मुझे ता खासतौर से दुःख हुआ। वे हामरे इतने बडत्रे
लीडर थे। पंजाब की एक महान् शख्सियत थे। उनकी शख्सियत
थे। उनकी शख्सियत का हमें एहताराम है, बड़ा फख्र है और
हमारे दिल उनके लिए इज्जत है ; किसान तबका उनका बहुत ही
अहसानमन्द है। यह सच्चाई ओर सफाई की बात है। मैं किसान
की आत नहीं करत है। वैसे तो सोर कांगेस वाले भी महसूस
करेंगेकि हम से कम इसबा कोकि हमारे लीडर के मुताल्लिक, जो
आज इस दिनिया में जिन्दा नहीं है, गलत बातें कही जाये। इतने
शानदार तरीके से उन्होने सरकारको चलया ओर उनके बारमें मैं
इतनी बैर जिम्मेदाराना बातें कहना मैं समझता हूं गलत चीज है।
अगर सर छोटू राम के बाद इस हरियाणों में या पंजाब में किसानों
को कोई बड़े से बड़ा नेता लीडर हुआ है तो वह सरदार प्रताप
सिंह कौरों था। इसी तरीके से हमारे लीडर पंडित भगवत दयाल
जी के बारमें मैं गलत बातें कहना भी ठीक नहीं। वे बडत्रे लीडर है,
और बड़ी भारी तादाद में लोग उनके साथ है। उनकी इज्जत ओर
एहताराम अगर हम बाहर देहात में जा करे देखें तो वहां सही पता
लगेगा यहां करने से कुछ नहीं पता लगता है। इसलिए जो इस
पैमाने के लीडर है उनकी शान क खिलाफ इस तरह से हाउस में
गलत बातें कहना मुनासिब नहीं है। (घंटी)

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज्यादा न कहताहुआ इतना
ही कहता हूं कि बजट पढ़ कर मालूम होता है कि बजट अच्छा है

ओर अच्छी कोशिश से और बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है इसके लिए मैं बहन ओमप्रभा जी को मुबारिकबाद पेश करता हूँ।

महंत गंगा सागर (झज्जर): डिप्टी स्पीकर साहिबा, सब से पहले तो मैं आपको आपके डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर बधाई देता हूँ। इसलिए कि मुझे उस वक्त बोलने का अवसर नहीं दिया गया था दूसरी बाधाई मैं आपको इस बात की देता हूँ कि इनते दिनों के बाद सेशन में आपने ही मुझे बोलने का वक्त दिया है और किसी ने भी नहीं दिया।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो बजट हमारी आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है उनका धन्यवाद करने के बाद मैं इसके मुतालिक कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। जिस समय हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय लोगों में इस किस्म की खुशी की लहर दौड़ गयी जैसे हजारों करोड़ों साल की गुलामी से छूटने के बाद किसी आदमी या किसी रियाया को होती है। लोग उनके खिलाफ थे और किसी हद तक जायज भी थे क्योंकि पंजाब के लोग हारे जायज हिस्से भी नहीं देते थे। इसलिए जब यह पंजाब से अलग हुआ उस वक्त हमारे हरियाणा के लोगों में एक बहुत ही बड़ी खुशी की लहर फैली है। 1 नवम्बर, 1966 के बाद जब यह खुशी लोगों में आयी और श्री भगवत दयाल शर्मा बतौर पहल चीफ मिनिस्टर के यहां रहे लेकिन चन्द्र दिनों के बाद फिर इलैक्शन का लोगों को सामना करना पड़ा ओर उस इलैक्शन के बाद कांग्रेस की मनिस्ट्री थोड़े ही दिन रही क्योंकि वह सरकार

कुछ लोगों ने मिल कर बदल दी। यह हरियाणों के लोगों की बदकिस्मती है कि कोई भी स्टेबल सरकार रह कर यहां काम नहीं कर सकी। उसके बाद यहां पर संयुक्त दल की सरकार आई मगर आठ महीने के बाद उसको भी जाना पडत्रा ओर जब चौथी आर इस सरकारो काम करने का मौका मिला है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै अर्ज करूं कि हरियाणा एक छोटा या प्रांत है और छोटा प्रांत या छोटा घर, छोटी फ़ैक्ट्री, छोटी दुकान या छोटी कोई भी चीज हो उसकी तरफ अगर पहले से ही ध्यान दिया जाए तो अकलमन्दी रहती है और अगर उसको जरा ढील देकर या गलती से बिगाडघ दिया जाय तो वह इतना बिगड़ जात है कि काम चलना चमुश्किल हो जाता है। इसलिए मै अर्ज करूंगा कि हरियाणा एक छोटा या प्रांत है और हमं इसकी ओर अभी से पूरा ध्यान देने की जरूरत है। एक आनरेबल मेम्बर ने जिक्र किया था कि स्टैट के बजट का 42 प्रतिशत इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है। इसमें संदेह नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च जितना इकट्ठा रहने में था उसे रेशों से कुछ ज्यादा मालूम पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल कुछ इस साथी की निस्बत डिफरेंट है। अगर हम किसी चीज को देखरेख और उसक इंतजाम ठीक नहीं करते तो हमार इंतजामिया तरीका भी बिगडता है। इस मं शक नहीं कि स्टेटे की तरक्की के लिए पैसेकी जरूरत है। या तो एक्पैसिज को घटाकर खर्च पूरा किया जा सता है या फिरआमदनी के रिसोजिस्ज को बढ़ाने के बार तरक्की की स्कीमों को कामयाब किया जा सकता है। मै समझता हूं कि इस वक्त अगर हम अपने रिसोर्सिज को डिवैल्प

करने की तरफ ध्यान दें तो ज्यादा अच्छी बात हैं इन वर रिसोर्सिज को कैसे बढ़ाया जाये, यह सवाल पैदा होता है। इसके मुताल्लिक कुछ तसवीजें पेश करना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि सरकार यहां पर मौजूद नहीं है। हां सिर्फ श्री रामधारी जी मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहिब भी नहीं है और न ही वित्त मंत्री जी है। (विघ्न)

Deputy Speaker: I also feel that only one Minister is present which not enough. There should be more than one Minister. In any case, the Finance Minister should have been there.

महंत गंगा सागर: मैं स्टेट के रैवेन्यू को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। स्टेट में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगानी चाहिए ओर उनमें भी अगर प्रैफरेंस देनी है तो यह ट्रेक्टरज, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस, पैस्टीसाइडज और फर्टिलाइजरज की फैक्ट्री होनी चाहिए जिससे जमींदारों को फायदा पहुंचे ओर स्टेट की आमदन भी बढ़े। ट्रेक्टरज को यहा पर जिक्र हुआ है। सच बात है कि लोगों को ट्रेक्टरज की फैक्ट्री लगाई जाये तो पहले साल नहीं तो कम अज कम दूसरे साल ट्रेक्टरज असेम्बल करके लोगों को दिया जा सकत हैं इससे स्टेट की जरूरियात को भी पूरा किया जा सकत है।

दूसरी चीज रैवेन्यू को बढ़ाने की ट्रांसपोर्ट पर काफी खर्च होता है। वर्कशाप्स भी मेनटेन करनी होती है। चैकिंग स्टाफ

वगैरा भी रखना होता है। सिर्फ नई बसजि को खरीदने का सवाल रह जाता है मैं कहूंगा कि ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर नैषनेलाइज कर दिया जाये। इससे स्टेट को काफी आमदनी हो सकती है।

फिर इवैक्यू लैंडज का भी जिक्र किया गया हैं इनकी कई सालों से सेल शुरू हुई है। इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाये और इन जमीनों को अगर औक्शन करना है तो ज्यादा से ज्यादा कीमत हासिल की जाये। जैसा चौधरी नेकी राम जी ने कहा है। आर्म लाईसेंस की फीसको बढ़ाया जाये, इससे भी स्टेट की काफी आमदनी हो सकती है। आर्म लाईसेंस कोई आम नसैस्टी की चीज नहीं है। यह मैंने कुछ सुझाव स्टेट के फाइनेंसिज को डिवैल्प करने के बारे में पेश की है। ओर मुझ विश्वास है कि सरकार इन पर गौर करेगी।

अब मैं कुछ बातें अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा जा झज्जर का इलाका है वह अंग्रेजोंके वक्त सही बैकवर्ड चला आ रहा है। इसकी वजह यह थी कि झज्जर के नवाब ने जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सालिया था। उसको बाद में फांसी भी चढ़ाया गया था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने हिस्ट्री को पढ़ा होगा। इसलिए अंग्रेजों ने इस इलाके को बैकवर्ड रखा। वहां पर पानी भी कम दिया और नहरों को भी वहां पर शुरू न किया और वहां के लोगों को भी कुचल डाला। लेकिन आजादी आने के बाद कुछसुधार शुरू हुआ।

नहरे भी आइ और बिजली भी। लेकिन दूसरो इलाकों की निस्बत यह इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है। हमारे लोगों को मिल्टरी फील्ड में सर्विसज किसी से छुपी हुई नहीं हे। झज्जर ही ऐ ऐसा इलाका है जिसके आदमी ज्यादा फौज में है ओर सब ज्यादा लोग लड़ाई में शहीद हुए है। यह बात आंकड़ों से साबित भी हो सकती हैं मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस इलाके के लिये एक सैनिक स्कूल का बहुत देर से जिक्र हो रहा हैं सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इसे लिए पत्थर भी रखा था और आज भी तकरीबन एह हजार बीघा जमीन इस स्कूल के लिए पड़ी हुई लेकिन यह टी वहां नहीं खोला गया हैं मै आप के जिरये सरकार से दरख्वासत करूंगा कि वह इस इलाके की इस मांग को पूरा करें। लोग निगाहें उठागर आप की तरफ देख रहे है कि आप इन की इस मांग को कब पूरा करते है।

इसके अलावा इस इलाके में बेराजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहभी अंग्रेजों की ही दे है। इस के मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि इस इलाके मै छोटी-छोटी इन्डस्ट्री को शुरू किय जाये ताकि जो बेरोजगार लोग है, जि मै खासतौरपर हरिजन तबका ओर दूसरे छोटे छोटे मजदूर है, उनका एम्पलयामेंट मिले।

जहां तक बिजली का सवाल है, इस सम्बन्ध मै वै य कहना चाहता हूं कि अगर हरियाणा में कही क्रांति आई है ते वह बिजली के महमें मे आई हैं मै यह कोई सरकार की तारीफ नहीं कर नहा। यह सच्चाई की बात है और इसके लिए हमारी मंत्री

महोदय, जो इस वक्त हाउस मे बैठे है बंधाई के पात्र है। मेरा बिजली के मामले से कई सालों से सम्बन्ध नहा हैं मैंने कई गांवों में बिजली लगवाने के मामले में काम किया है। कई वक्तथा जब बिजली के महकमें वो किसी की बात नही सुनते थे मगर अब मैंने देखा है कि वही लोग रात के वक्त भी अपना सामान लिये कार कर रहे है। इसलिए, इस मामले में मैं अपनी मंत्री महोदय को बधाई दिये वगैर नही रह सकता।

जहां तक नहरों का ताल्लुक है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इनमें बहुत सुधार की जरूरत है। मैं एक नया मैम्बर हूं और मेरा नौलिज इस बारे में बहुत नही है। लेकिन कुछ ऐसा सुना जाता है कि पंजाब ओर हरियाणा में पानी का बंटवारा जमीन की रेशों के हिसाब से नही हुआ ओर हमें पंजाब की निस्वत पानी बहुत कम मिला है। मैं आप के जरिये सरकार से अर्ज करूंगा कि वह पानी के बंटवारे के केस को जरूर देखें और अपना पूरा हिस्सा लेने की कोशिश करे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे विश्वास है कि सरकार बजट में फौजी भाईयों के लिण भी कुछ सहूलते देंगी। जो उनके बच्चे है चाहे वह पब्लिक स्कूलज में पढ़ते है या दूसरे स्कूलों में उनको कुछ रियायतें दी जानी चाहियें।

फलड्ज के मुताल्लिक जनाब मैं अर्ज करूंगा कि झज्जर के इलाकं में 30-40 गांव हर साल फलड की जद में आ जाते हैं

और आप हैरान होंगे। अभी मैं इन छुट्टियों में भी जब वहां गया तो देखा कि साहिबी नदी में 7,400 क्यूबिकस पानी चल रहा है जब कि 3,000 क्यूबिकस ही जा सकता है। जब अभी इतनी तेजी से पानी नहीं आ रहा तब यह हालत है तो आप अन्दाजालगा सकते हैं कि जब आने वाले दिनों में पानी ओर तेजी से आएगा तो क्या हाल होगा। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार एक ओर समस्या है और वह यह है कि जब पानी उतरता है तो जो सेम के इलाके होते हैं वहां पर लिंक ड्रेन न होने के कारण कई कई हजार एकड़ कबा बरबाद हो जाते हैं। लेकिन अफसर यह कोशिश करते हैं कि लिंक ड्रेन बना कर पानी निकाल दिया जाए लेकिन बाज दफा जब कोई किसान अकड़ जाता है कि हमारी जमीन में से लिंक ड्रेन नहीं बनेंगी तो मजबूरी हो जाती है ओर उसक बहुत भारी नुकसान होता है। बात यह है कि अफसर भी कुछ नहीं पाते क्योंकि कानून कुछ ऐसा है और प्रोसीजर इतना लम्बा है कि जमीन एक्वायर करते करते महीनों लग जाते हैं। तो इस तबाही को रोकने के लिये कानून कुछ इस तरह से बनाया जाना चाहिये कि जब भी और जहां भी जरूरत पड़े तो जमीन एक्वायर करली जाए, बार में कानूनी कार्यवाही होती रहे। मेरा यह 4-5 साल का तजरूबा है और मैं बराबर यह मुश्किल देखता आ रहा हूं।

खेती बाड़ी के क्षेत्र में यह देखा गया है कि एसो कार्ड भी जमींदार नहीं है जो अपनी पैदावार ज्यादा न बढ़ाना चाहता हो लेकिन उसे साधनों की जरूरत है। जहां तक बिजली का मसला है, या नहर के पानी का मसला है मैं समझता हूँ कि वह ठीक है और ठीक हो जाएगा मगर जैसी कि मैकेनाईज्ड फार्मिंग की ओर तबदीली आ रही है ते मैकेनाईज्ड इम्पीमेंट्स की जरूरत है ओर अगर ट्रैक्टरों का मसला हल कर दिया जाए ता पैदावार एकदम बढ़ जाएगी। इसी तरफ फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है। उसमें अब दिक्कत यह हो रही है कि कोआपरेटिव के थरु उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई हैं इसमें कोआपरेटिव के मैम्बर को 3,000 रूपया तकाबी क तौर पर मिलगा। जिसमें से 1,500 रूपया उसे कौष मिलेगा ओर 1,500 रूपया का फर्टीलाइजर मिलेगा। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जो कोआपरेटिव का मैम्बर नहीं है वहा कहां से जाएगा? इसलिए सभी केलिये इस की सुविधा देने का इंतजाम किया जाए ओर जो रूपया तकावी के जरिये दिया जाता है उसकी रकम बढ़ा दी जानी चाहिये। वरना इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी मुझ जाती तौर पर तजुर्बा है।

इसी प्रकार इम्परूव्ड बीजों की बात है। यह बीज उस वक्त दिये जाने चाहिये जबकि फसल की बिजाई शुरू होती है वरना बाद में दिये जाने सेकोई फायदा नहीं होता है।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जैसा है उसी तरह इसके इन्तजमिया ढांचे को

और मजबूत बना दीजिए अगर रिसोसिंज की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो स्कीमें बनाई जाती है, उन पर पक्की तरह से अमल किया जाना चाहिये ताकि हरियाणा के लोगो ने इस मिनिस्टरी क अने से जो आशा बांधी है वह पूरी हो सकते और इस प्रकार प्रांत का भला हो सकें।

श्री सत्यानारायण सिगांल (सफीदों): जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहा जो बजट इस हाउस में पेश किया गया है उसमें 823 लाख रूप्ये का घटा दिखा गया है। किसी स्टेट की भलाई के लिये जय जरूरी है कि उसके बजट में घाटना न रहे लेकिन इस बजट में ऐसा कोई तारका नही बताया गया कि इस घाटे को किस तरफ पूरा किया जाएगा। सैट्रल गवर्नमेंट से जो 90 लाख रूपया मिलना है अगर वह मिल जाए तो भी 7 करोड़ का घाटा फिर भी रहा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा प्रांत के बन्दर बहुत ज्यादा डिवैल्पमेंट की जरूरत है। मुझ याद आ गया है कि अभी श्री नेकी राम जी ने फरमाया कि सरदार प्रताप सिंह एक बहुत बड़े लीटश्र थे लेकिन मैं उन्हे यह बताला देना चाहता हूं कि हरियाणा के लिय सरदार प्रताप सिंह से बड़ा और कोई दुश्मन ही पैदा नही हुआ।

वित्त मंत्री: जनाब, एक मरहूम व्यक्ति के लये ऐसे अलफाज इस्तेमाल करना शोभा नही देता है।

श्री सत्यनारायण सिंगोल: मै जनाब, यह कहना चाहता हूँ कि हरियाण के अन्दर जब तक एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जाजात तब कि हरियाणा सेल्फ सफीशियेंट नहीं हो सकता। इसलिए जमींदारों के लये ज्यादा से ज्यादा मिकदार में खाद, बिजली, ट्रैक्टर और जहां कही पानी की जरूरत हो वहां पर ट्यूबवैल्ज दिये जाने चाहिये। ट्यूबवैल्ज के बारे में मै अपने इलाके की बात बतलाना चाहता हूँ कि वहां पर भी ट्यूबवैल्ज लगे हुए है उनमें बिजली का रेट चार्ज करने के बारे में बड़ी भारी धांधली है ओर किसानों को, जो पानी है, वो बिजली के रेट से चार्जिज नहीं देने पड़ते बल्कि पानी चालने की सिलसिला कुछ बनया हुआ है। जिसकी नोटिंग ओर रिकार्डिंग कागजात में की जाती है जो किसानों को कुछ बताई जाती और आखिर में जब चार्जिज वसूल करने का वक्त आता है तो 5-5 एकड़ के मालिक को 500-500 रूपया बिजली का बिल देना पड़ता है इसलिए मै सी.एम. साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस तरफ गौर करे।।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्टेट के अन्दर खर्च कैसे हो रहा है, इसके बारे में मै भी मै थोड़ा या अर्ज करता हूँ कि सरकार का खर्चा अभी पूरा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी यह और ज्यादा खर्चा बढ़ाने की स्कीमें बना रही है। जिस वक्त हरियाणा बना तो यहां पर 72 आई.एस. अफसर थे लेकिन जब राष्ट्रपति का राज्य आया तो 79 आई.ए.एस. अफसर कर दिये गये और अब मैने सुना है कि कुछ और आई.ए.एस अफसर लाए जा रहे है और इस तरफ

से एडमिनिस्ट्रेशन को टाप हैवी बनाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत सी पोस्टों पर हरियाणा बनने से पहले ओर बाद में भी पी.सी.एस. पद के आदमी काम करते थे ओर अब उन पोस्टों को अपग्रेड करके आई.ए.एस. केडर बना दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उन पोस्टों को पी.सी.एस. केडर को ही रखा जाए और उनका ऊपर हमारी स्टेट के आदमियों को ही लगाया जाए।

अब मैं फलड्रज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इनका जो महकमा है यह जून और जुलाई में जागता है जबकि बारिश शुरू हो जाती है नतीजा यह होता है कि काम हो नहीं पाता और फलड्रज शुरू करना चाये ताकि फरवरी मार्च तक काम हो खत्म कर दिया जाए और बजट का सारा रूपया खर्च हो जाए। अगर इस तरह से काम किया जाए तो पूरा फायदा हो सकता है और अगले साल के लिये जो स्कीमें बनानी हो उनके लिये भी कोई दिक्कत नहीं हो सती। जो छोटी छोटी ड्रेन्ज पांच पांच मील से कम लम्बी है उनके लिये सरकार कहती है लोग खुद खोदे। लोग खोद ता लेते हैं लेकिन जहां जहा पर पुलिया बनाने की जरूरत हो वह सरकार को अपनी तरफ से बनानी चाहिये। इससे लोगों का भला हो सकता है।

बहन ओमप्रभा जी ने रेवैन्यूज को बढ़ाने के लिये सुझावों की मांग की थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सेल्ज टैक्स के महकमों में मेरे अंदाजे के मुताबिल चार करोड़ की कम से कम चोरी है और इसकी जिम्मेदारी इतनी पब्लिक पर नहीं

जितनी कि आप के डिपार्टमेंट पर है। आपके डिपार्टमेंट क आदमी लोगों से मिल कर चोरी करवाते है। मुझे पता है कि जब इनके नोटिस में भी कोई चीज आ जाए तो वह उस को दबाने की कोशिश करते है। इसलिए इस महकमें को टाईज करने की जरूरत है। जिस अफसर के खिलाफ कोई शिकायत आए उसकी इन्क्वायरी करनी चाहिये। ऐसा करने से गवर्नमेंट से खजाने में काफी रूपया आ सकता है।

श्री खुरशीद अहमद जी यहां नहीं है, मैं उनके महकमें की बात करता हूं। स्टेट में कहा जाता है कि डाक्टरों की बहुत कमी है, लेकिन मैं समझता हूं कि कमी नहीं मगर यह चीज खुद बनाई जा रही है। डायरेक्टोरेट्स में बहुत से डाक्टर लगा रखे है जाहं पर कि उने पास दस्तखत करने के सिवाए और कोई काम नहीं होता। इसी तरह बर्थ कंट्रोल के महकमें में बहुत से डाक्टर लगा रखे है जहां पर कि ऐं पैसे का काम भी नहीं होतौ। मैं समझता हूं कि इन सब डाक्टरों को इस्पतालों में लगाना चाहिए दफतरों में तो क्लर्कों का काम होता है। यह जा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर (सी.एम.ओ.ज.) लगाए गए है वहां पर उन की जगह पी. सी.एस. अफसर काम कर सकते है।

इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो जन्म से अंधे बच्चे हिम्मत करके तालीम हासिल कर लेते है उनकां रोजगार पर लगाना चाहिए ताकि जो दूसरे अंधे बच्चो हो उन में भी उत्साह पैदा हो और वह भी पढ़ने लिखने की हिम्मत करें।

अब मैं आइ.पी.एम. साहिब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा में बिजली का सबसे बड़ा सोर्स नंगल धूकोट बिजली घर है। दरअसल भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड में तीन मैम्बर है, हरियाणा का, एक पंजाब का और एक सैटर का। हमार मैम्बर जो है वह नहर के महकमें का है और पंजाब वालों का बिजली के महकमें का है उन्होंने लुधियाना और जालंधर में ठीक सपैसीफिकेशन की तारे लगा रखी है जिससे उनको पूरी बिजली मिलती है और हिसार के रास्ते जो बिजली लाइन जाती है वहां पर कमजोर तारें लगाई हुई जिससे हमें पूरी बिजली नहीं पहुंचती। इसलिए, मैं गुजारिश करूंगा कि वहां पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड की तारे लगवाईं ताकि बिजली की पूरी क्वांटिटी सप्लाई हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, भम्बेवा में पानी की वजह से हजारों एकड़ जमीन बरबाद पड़ी है। अभी चंद दिन हुए चौधरी शेर सिंह जी वहां पर आए थे, लेकिन आज तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर वहां से पानी निकाल दिया जाए तो वहां अच्छी खेती हो सकती है। इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए।

जहां तक सड़कों का ताल्लुक है मेरे इलाके में सड़कें बहुत कम हैं उनमें काफी गड़बड़ हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महकमें जितनी गड़बड़ हुई है उसको रोकने के लिए सख्त कार्यवाही की जाए। मैं इस मनिस्टरी की कार्यवाही का एक नमूना पेश करता हूँ। एक अफसर ने एक दुकान की पुरानी गेहूं को नई के बदले बचेते हुए पकड़ा और वह केस हो हशअप नहीं कर रहा

था, ता इस पर उस अफसर को टैलीग्राफीकली बदल दिया गया और उसकी जगह दूसरा अफसर भेजा गया जिसने उस केस को जते ही विदद्दा कर लिया। मै समझता हूं कि ऐसी चीजे नही होनी चाहिए।। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर वह गंदम चली जाती है तो उसे कितनी हरियाणे की बदनाम होती। पचपन साठ रूपये वाली गंदम 75 रूपये क्वंटिल के भाव पर खरीदी जा रही थी लेकिन फिर भी उस केस को हशअप कर दिया जाए तो कितनी बे इन्साफी की बात है। मै अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमैन्ट को ऐसे मामले में सट्रिक्ट होना चाहिए ओर कुरप्ट डीलरज को रियायत नही देनी चाहिये। मै फाइनेस मिनस्टर साहिबा से अर्ज करताहूं कि यह जो घटे का बजट पेश उन्होने किया है उसे बजाय हेरा फेरी सीधे तौर पर लाते तो ठीक था। मै इनसे यह भी कहना चाहता हूं कि वह अपनी टैक्सेन पालीस सोच समझ कर बनाएं। जरायती तबके पर पहले ही भारी अैक्स लगे हुए है। अब ओर इन पर बोझ डालने की कोशिश न करें और जो सरचार्ज लगाया हुउअ ळै इसे कम रकें हाउस टैक्स के बारमें मे कहां जाता है कि सिंगल सैल्फ आक्युपाइड हाउस ऐगजैमपिड है लेकिन यह बात सही नही है। ओर जगह का तो मै कहन नही सकता लेकिन मेरे साले जिला में तो ऐसा नही है और सब से जिन के पास सिगल मकान ही है। उनसे भी चार्ज किय जा रहा है।

वित्त मंत्री: कोई मिसाल दे कर बताएं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: सारे जिला में ही ऐसा किया जा रहा है एक जगह की बात नहीं है उनसे कहा जाता है कि पहले टैक्स जमा कराओं फिर साल के बाद ऐफीडेविट दो कि आपके पास सैल्फ आक्युपाइड सिंगल हाउस है। तब आप को रिफंड किया जाएगा ओर वह भी इतना सारा खर्च करके के बाद। सह तरीका ठीक नहीं है कि लोगों को इस तरह से तंग किया जाए। पहले ही जांच पड़ताल करके सारी बात की जाए और लोगों को खमखाह तंग न किया जाए कि वह ऐफीडेविट देते फिरे ओर सारा खर्च करे। इन अलफाज के साथ में कहना चाहता हूं कि अगर आप टैक्सो की चोरी रोक देगे ओर इनकी वसूली अच्छी तरह करेंगे तो नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओर लोग भी खुशहाल होंगे।

श्री दया कृष्ण (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सदन के सामने जो बजट पेश हुआ है मुझे खुशी है कि उसे कांग्रेस सरकार ने पेश किया है। जनरल इलैक्शन के बाद भी लोगों ने कांग्रेस के 48 मैम्बर भेज कर जाहिर किया था कि जनता चाहती है कि कांग्रेस ही उनकी सेवा करें लेकिन यह जो भाई आपोजीशन में बैठे हैं उन्होंने दल बदल कर अपनी हकूमत कायम की और उस सरकार ने आठ नौ महीन यह कारनामे किये कि जिससे जनता में हाहाकर मच गई जिसकी वजह से दोबारा इलैक्शन हुए, सरकार को करोड़ों रूपया खर्च हुआ ओर लोगों ने फिर कांग्रेस को ही सेवा करने के लिए भेजन और यह बजट

उन्ही की बनई गई सरकार की तरफ से पेश किय गया है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह न ज्यादा अच्छा हो और न ज्यादा बुरा है। इस सरकार के सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बड़े नेक भले और साहु है और यह साहु सरकार का साहु बजट हैं इस बजट में सबसे अच्छी बात यह की गई कि आठवी जमात तक बच्चों पर जो फीसों पिछली सरकार ने लगाई थी वह इन्होंने दोबारा माफ करदी है। राव सरकार ने बच्चों पर फीसों लगाई थी ओर बूढ़ों को जो पेन्शन दी जाती थी वह बन्दी कर दी थी। इस सरकार ने जिसतरह फीसों हटा दी है उसी तरह मैं अर्ज करता हूं कि बूढ़ों की पेन्शन बहाल की जाए। सबसे बुरी बात जो इसमें की गई है वह यह है इन्होंने लाटरी सिस्टम लागू किया है जिसे मैं ठीक नहीं समझता। हमारी सरकार जब दूसरी बुराइयां बन्द रकती है यानी जआ खेलना ओर सट्टा खेलना रोकती है तो यह अच्छा नहीं लगता कि सरकार खुद जुआ खेलना शुरू को। लाटरी एक किस्म का जुआ ही औ सरकार की तरफ से इसे शुरू करना अच्छी बात नहीं है? इसके अलावा इस रूप्ये की वसूली के लिये कितनी ही किस्म की ज्यादातियों होगी। सारे दफतरों में औरतहसीलों इकसे टिकटों की बिकरी जबरदस्ती की जाएगी। और लोगों को तंग किया जाएगा। इसिलए, अगर इसे बंद करे दें तो अच्छी बात होगी। हमारा हरियाणा प्रान्त सारे हिन्दूस्तान में मैं समझता हं कि सबसे अच्छा सूबा है लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें अब शराब का प्रचार हो रहा है जैसा कि इक्साइज रैवेन्यू बढ़ जाने से साफ जाहिर हो रहा है। हम तो समझते थे कि रोहतक के बाद अब

सारे हरियाणा में ही शराब की बंदश हो जाएगी बड़े अफसोस की बात है कि इसकी बजाए अब शराब का और ज्यादा, प्रचार हो रहा है और इस की खपत बढ़ती जा रही है। इस चीज को सरकार को रोकना चाहिये। हमारा यह बजट घाटे का है लेकिन इनके बावजूद सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया इस बात को मैं ठीक नहीं समझता हमारी यह लोगों की पापुलर सरकार है और हममें यह हिम्मत होनी चाहिये कि हम लोगों के लिये भलाई के काम करने के लिये टैक्स लगा कर रूपया हासिल करें आज देखते हैं कि हरियाणा में कितनी बुरी हालत है जब तक हम टैक्स नहीं लगायेंगे तब तक जनता की बहबूदी के कोई का नहीं किए जा सकते जै कि फिकरे में शेक्सपियर ने कहा है कि

“Diseases desperate grown by desperate applications, are relieved or not all”.

हमारी यह जो इतनी नागुफताबे हालत है ओर हम इतने पिछड़े हुए हैं। इसका कोई हल नहीं होगा जब तक हम टैक्स लगा कर अपने साधन नहीं बढ़ायेगे। इस प्रांत के खेती पर ही ज्यादा दारोमदार है और खेती के लिये सबसे पानी की जरूरत होती है लेकिन इस के बारेमें हमारी हालत खराब है। इस वाकत हमारी सारी जमीनको 20 फीसदी को पानी लगता है ओर अगर हम पचास फीसदी जमीन को ही पानी देना चाहें तो भी बेहद रूपया

हमें चाहिये और वह रूपया सिर्फ टैक्सों से हासिल किया जा सकता है। जब हम कोई टैक्स स्ट्रकचर है वह बड़ा खरबा है। आप देखेंगे कि इस बजट में इनडायरैक्ट टैक्स डायरैक्ट टैक्सों से ज्यादा है इसमें बात यह है कि इनडायरैक्ट टैक्स गरीबों पर लगते हैं और डायरैक्ट टैक्स अमीरों पर लगते हैं। आप देखेंगे कि हमारा 33 फीसदी रैवेन्यू सेल्ट टैक्स से वसूल होता है जो कि इनडायरैक्ट टैक्स है और गरीबों पर इस का ज्यादा भार पड़ता है। फिर आप यह भी देखेंगे कि हर सेशन में इस ऐक्ट को अमैड किया जाता है और हर साल हम इस टैक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं यह तरीका गलत है और सरकार को वह टैक्स जो इनडायरैक्ट है उनको इस तरह बढ़ाते नहीं चले जाना चाहिए। मैं वजीर खजाना साहिबा से अर्ज करता हूँ कि आइंदा के लिये उनहे इस तरफ ध्यान देना चाहिए और डायरैक्ट टैक्स ही लगाने चायें क्योंकि हरियाण में इनडायरैक्ट टैक्सों का इनसीडेंस बहुत ज्यादा है जिसे गरीब आदमी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं टैक्सों के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त हमें आजादी मिली थी हम ख्याल करते थे कि अमीर और गरीब के दरम्यान फर्क बहुत कम रह जाएगा लेकिनहाल यह है कि दिन ब दिन यह फासला बढ़ता चला जा रहा है। हम ख्याल करते थे कि अमीर से पैसे लेकर गरीब पर खर्च यि जायेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा नहीं सकते थे तो कम से कमयह जरूर कना चाहिये कि जो टैक्स है व अमीरों से वूसल करके अमीरों पर खर्च कर दिये लेकिन ऐसा भी इस वक्त नहीं हो रहा जब तक हम टैक्स नहीं

लगायेंगे किसी आदमी का भी हम भला नहीं सकेंगे। आप देखते हैं कि नहरों के पास कितनी सैलाबजदा जमीन पड़ी है। और सरकार को नहरों के पास कितनी सैलाबजदा जमीन पडती है। और सरकार का नहरों के साथ साथ जमीन है उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है अगर इज जमीन को ठीक करके पानी का इन्जजाम किया जाए और उसी जमीन से टैक्स लिया जाये ता इससे एक जमीन वालों का भला है, सरकार का भला है ओर देश के हर आदमी का भला है सैलाब से जो जमीन खराब होती है उस तरफ सरकारका कोई ध्यान नहीं है जब तक हम टैक्स वसूल नहीं करते, टैक्स इक्ठ्ठा नहीं करत जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा और हम उन लोगों का भला नहीं कर सकेंगे। अगर बरीब लोगों को छोड़ कर बड़े लोगों पर टैक्स नहीं लगाते और पैसा इक्ठ्ठा नहीं करते जब तक हम तरक्की नहीं कसते। इसके इलावा, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर टैक्स लगायें तो किस तरफ लगाने चाहिये। आज चीफ मिनिस्टर साबिन ओपनली कहा कि अपोजीशन की तरफ से टैक्सज लगाने के संबंध में कुछ सजैशन्ज आनी चाहिये। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वे कोई तजवीज बनाकर भेजे।

मलिक मुख्तियार सिंह: श्रीदयाकृष्ण जी, आप यह गुनाह हम से करवाना चाहते हैं?

श्री दयाकृष्ण: चौधरी साहिब, यह गुनाह नहीं है मैं यह कहता हूं कि जिसे टैक्स वसूल किया जाये उसी पर खर्च किया जाए, दूसरों पर नहीं। एक और अँक्स के बारे में मैं सुझाव देना

चाहता हूँ कि जिससे सरकार कुछ आमदनी हो सकती है। हम यह भी चाहते हैं कि शराब पर पाबन्दी हो। अगर शराब पर टैक्स ज्यादा लगाया जाये तो शराब पीने वालों की संख्या कम हो सकती और सरकार इससे आमदनी भी हो सकती है। चूंकि शराब पीने वालों को टैक्स अधिक देना पड़ेगा इसलिए शराब पर एक तरह की पाबन्दी भी हो जाएगी। वे शराब पर ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। इस तरह उनकी यह आदत कम होती जायेगी।

इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस पहले तीन फीसदी होती थी। तीन रुपये से बढ़ाकर 13 फीसदी कर दी गई थी, इससे बाद यह फिर कम कर दी थी। यह भी एक डारैक्ट टैक्स है। जो आदमी ज्यादा जमीन खरदीता है उस पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए। जिस जमींदार को ज्यादा आमदनी है उसे कुछ न कुछ अपनी आमदनी का हिस्सा सरकार को देना चाहिए। जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके पास बहुत जमीन है ओर वे मैकेनाईज्ड ढंग से खेती करते हैं, उन्हें लाखों रुपये की आमदनी है लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि उनकी तरफ सरकारको जरूर ध्यान देना चाहिये ताकि स्टेट की आमदनी बढ़ सके। सरकार को लैड रैवेन्यू खत्म कर देना चाहिये और सिर्फ इन्कम टैक्स ही लगाना चाहिये और सबसके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। हरियाणा प्रांत जमींदारों का प्रांत है। जमींदारों से ही हमारा गुजारा है इसलिए इसे टैक्स लगा कर पैसा वसूल करके

देश की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। इसमें उनका भी भला है और देश का भी भला है।

इसके बाद मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में में जिक्र करना चाहता हूँ। सब लोग इस बात को जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है यह हर आमदी जानता है कि बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश से किसी का काम बनने वाला नहीं है। दुनिया का कोई भी काम हो उसके लिए जा रिश्वत चाहिए या सिफारिश और कहीं कहीं तो दोनों की जरूरत होती है इसलिए जब तक देश के सब आदमी, जिसमें पोलिटीशियन भी शामिल है, बड़े बड़े आफिसर है, पब्लिक भी शामिल है, इस कुर्रप्शन को दूर करने के लिए ध्यान नहीं देंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेशन की हालत सुधर नहीं सकेगी। जो मशीनरी अंग्रेजों ने सर्दियों से बनाई हुई है वह आस्ता आहिस्ता खराब हो जायेगी और हम बरबार हो जायेंगे। इसलिए सरकार को सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि कुर्रप्शन में कमी हो सके। जिस सरकार को अपने आफिसराज को यह भी पता नहीं कि वह किसनी रिश्वत लेता है तो वह सरकार काम क्या करेगी? मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस आफिसर ने एक लाख रूपये से ज्यादा रिश्वत जी हो फौरन डिमिस कर दिया जाए। अगर सरकार इनक्ककवायरी करवाये तो उसे कम सककम इन रिश्वतखोरों का पता लगा सकता है। बहुत से आफिसर इस किस्म के हैं जिनहोने लाखों रूपये रिश्वत के

इक्ठुठे किये हुए है। ऐसे आफिसरों की इनक्वायरी हो और उन्हें डिसमिस किया जाये ताकि उनकी डिसमिसल से दूसरों आदमी भी सबक ले सकें और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से चले।

इसके बाद में पुलिस के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। पुलिस पर हमार बजट का पांच परसेट रूपया खर्च होता है जो कि बहुत बड़ा खर्च है। मुझे यह भी इत्तलाह मिली है कि पुलिस डिपार्टमेंट में इस समय बहुत से कंस्टेबल और आफिसर सरप्लस हैं अगर यह बात ठीक है तो उनको रिट्रैच कर दिया जाए ताकि हमार खर्चा बच सकें।

जहां तक ला-एंड -आर्डर की हालत है वह बजुत अच्छी नहीं है। आपको भी इस बात का तजुरुबा होगा ओर मुझे भी है कि आप पुलिस के किसी स्टेशन चले जाये, कितना ही बड़ा जुर्म हो, कोई भी आफिसर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगे। जिसको रिपोर्ट लिखवानी होती है वह बहुत तंग होता है। इस तरफ रिपोर्ट नहीं लिखेगा। जिसको रिपोर्ट लिखवानी होती है वह बहुत तंग होता। इस तरह रिपोर्ट न लिखने सहमें पता नहीं रहता कि हमारी स्टेट में कितने जुर्म हो रहे हे। इसलिए मैरसा सुझाव है कि पुलिस स्टेशनों पर दो किस्म के रजिस्टर होनी चाहिये। यह एक रजिस्टर होना चाहिये जिस पर पुलिस ने एक्शन लेना है और ठीक ढंग से रिपोर्ट दर्ज करनी है। ओर दूसरा वह रजिस्टर होना चाहिये जिसमें वह केस हों जिन पर कोई ऐक्शन नहीं लेना। ऐसा

करने से सरकार को यह इत्तलाह रहेगी कि हमारी स्टेट में कितने जुर्म हो रहे है ।

उपाध्यक्षा: श्रीदयाकृष्ण जी, आप अपनी स्पीच कंटिन्यू करना चाहते है या खत्म करना चाहते है ।

श्री दयाकृष्ण: मै कंटिन्यू करना चाहता हूं ।

Deputy Speaker: Order please, It is 6-30 P.M. now. The House stands adjourned till 2-00 P.M. tomorrow.

(The Sabha then adjoruned till 2-00 P.M. on Tuesday, the 23rd July, 1968).